

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

## राजीव नारायण रैना के समक्ष

याचिकाकर्ता - खजान सिंह और अन्य

बनाम

प्रतिवादी - हरियाणा राज्य और अन्य

2011 का सीडब्ल्यूपी नम्बर 10017

28 मई 2014

भारत का संविधान, 1950 - कला। 14, 16, 226 309 और 310 - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - एस.10(एल)(सी) - राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 - महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम अभ्यास रोकथाम अधिनियम, 1971 - एस 30 - याचिकाओं का वर्तमान समूह सेवा की निरंतरता के साथ बहाली प्रदान करने वाले श्रम न्यायालयों के पुरस्कारों से उत्पन्न हुआ है, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने नियमितीकरण के लिए अपने दावे को आधार बनाया है - जबकि याचिकाकर्ताओं ने सेवा की निरंतरता के साथ बहाली की तारीख से अलग-अलग वर्षों में अपने पक्ष में पुरस्कार सुरक्षित किए हैं। अवैध समाप्ति/छंटनी, कई अन्य दैनिक वेतनभोगी बिना किसी छंटनी के कारण सेवा में बने रहे और उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया गया था - याचिकाकर्ताओं की दैनिक वेतन सेवा में

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

बहाली केवल श्रम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर की गई थी - कुछ अन्य दैनिक वेतनभोगी, जिनकी सेवाओं को नियमित किया गया था, याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ - याचिकाकर्ताओं ने अपने दावे को घृणित भेदभाव और संविधान की धारा 14 के उल्लंघन पर आधारित किया - हरियाणा राज्य ने नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के दावे का इस आधार पर विरोध किया कि प्रारंभिक भर्ती नियमों के अनुसार नहीं थी और उन्हें अवैध रूप से नियुक्त किया गया था और इसके अलावा वहाँ था उनकी सेवा में व्यवधान उन्हें रोज़गार के लिए उनकी अनुपस्थिति की अवधि की गणना करने से वंचित कर देता है - उच्च न्यायालय ने माना कि भर्ती नियमों के अभाव में कई साल पहले की गई नियुक्तियों में किसी भी नियम का उल्लंघन पढ़ना संभव नहीं है - इसके अलावा श्रम न्यायालयों द्वारा बहाली को संबंधित माना गया छुट्टी की तारीख पर वापस जाएँ जो याचिकाकर्ताओं को उनकी बेरोज़गारी की अवधि को नियमितीकरण के लिए आवश्यक सेवा की लंबाई के रूप में गिनने का अधिकार देता है - न्यायालय ने आगे कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लाभकारी कानून का एक हिस्सा था और अनुचित श्रम प्रथाओं के रूप में प्रविष्टि 10 में विचार किया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम की 5वीं अनुसूची जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान मामले में घृणित भेदभाव हुआ, उसकी निंदा की गई।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

आगे यह माना गया कि रिट कोर्ट पहली बार समीचीनता के सिद्धांत पर औद्योगिक कानून सिद्धांतों को अच्छी तरह से लागू कर सकता है - प्रविष्टि 10 (पूर्व) शोषण के खिलाफ एक नियम है और यह एक उदार और उद्देश्यपूर्ण निर्माण के लिए असाधारण क्षेत्राधिकार के अभ्यास के लिए उपयुक्त मामलों का एक समूह प्रस्तुत करता है। मानवीय मामलों के संकटों से निपटने के लिए - आगे यह माना गया कि कई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी राज्य के अधीन या राज्य के मामलों के संबंध में पद धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए - वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं को इस रूप में नियोजित किया गया था। दूर-दराज के स्थानों में वन विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जहां बहुत से लोग रोजगार लेने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं और जिनकी सेवाओं को भर्ती के नियमों द्वारा सख्ती से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है - उनके अधिकारों की औद्योगिक कानून सिद्धांतों के सुविधाजनक बिंदु से जांच और घोषणा की जानी चाहिए - मनमानी के मामले में रिट कोर्ट द्वितीयक समीक्षा के सिद्धांतों को अच्छी तरह से लागू कर सकता है - इसलिए वर्तमान मामलों में यथास्थिति देकर संतुलन बहाल करना होगा और याचिकाकर्ताओं को उनके समकक्षों के बराबर लाना होगा जिनकी छंटनी नहीं की गई थी और जिन्होंने प्रशासनिक द्वारा नियमितीकरण का लाभ प्राप्त किया था। न्यायिक हस्तक्षेप के बिना आदेश - सेवा के पूर्व दिनांकित नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के उपरोक्त अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में घोषित - रिट याचिकाएँ स्वीकार की गईं।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

यह माना गया कि उमादेवी में संविधान पीठ ने आधिकारिक रूप से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को आदेश जारी किया है कि वे तदर्थ, दैनिक वेतन भोगी और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित सेवा में शामिल करने और नियमित करने के लिए नियोक्ता राज्यों को परमादेश जारी करने से बचें, जिन्होंने पालन किए बिना रोजगार हासिल किया था। पदों पर भर्ती के लिए लागू नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया क्योंकि यह उन लोगों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अवसर की समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा जो नौकरी बाजार में उपलब्ध थे और ऐसी पोस्टों के आवेदन और प्रतियोगिता के अवसर से वंचित थे। यह माना गया कि अनुच्छेद 16 द्वारा संरक्षित सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने की संविधान की योजना के विपरीत की गई ऐसी नियुक्तियों को भेदभाव के आधार पर भी नियमित नहीं किया जा सकता है और न ही सुप्रीम कोर्ट और न ही हाई कोर्ट ऐसा कोई निर्देश जारी करेगा। भेदभाव के आधार पर सार्वजनिक पद को हथियाने वालों जैसे रैंक के स्थायी लोग, जो सरकारी सेवा या सार्वजनिक रोजगार में नियुक्तियाँ करने की संवैधानिक योजना के विपरीत हैं। संविधान पीठ धारवाड़ जिला लोक निर्माण विभाग बनाम कर्नाटक राज्य 1990 (1) एससीआर 544 मामले में लिए गए अपने पहले के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

(पैरा 12)

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

आगे कहा गया कि संविधान पीठ ने हरियाणा राज्य बनाम प्यारा सिंह 1992 (4) एससीसी 118 के पैरा 50 में जारी अपने पहले के निर्देशों को भी फैसले के पैरा 45 में दिए गए निष्कर्षों के साथ असंगत पाया, जिन्हें संवैधानिक योजना के विपरीत माना गया था। प्यारा सिंह को खराब कानून घोषित किया गया। कोर्ट ने भर्ती के नियमों को तोड़ते हुए ऐसे रोजगार के खिलाफ फैसला सुनाया और निर्देश दिया कि ऐसे तदर्थ, अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जब समान पद नियमित आधार पर भरे जाएं तो उन्हें उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकती है। उनके लिए खुला चयन और आयु सीमा की शर्त हटा दी जानी चाहिए। दस साल की अनियमित तदर्थ या दैनिक वेतन सेवा को राहत देने के लिए पर्याप्त रूप में तैयार किए गए फॉर्मूले में स्वीकार किया गया था लेकिन इसे एक बार के उपाय के रूप में आदेश दिया गया था। यहां यह जोड़ा जा सकता है कि परिपक्व होने के अधिकारों के लिए पुरानी योजनाओं में ऊष्मायन अवधि तीन साल थी, सरकार ने अपनी नीतियों में इसकी कल्पना की थी।

(पैरा 13)

आगे कहा गया कि हालांकि उमादेवी मामले में फैसले की प्रस्तावना में पैरा, 2 में कोर्ट ने कहा कि एक संप्रभु सरकार, देश में आर्थिक स्थिति और किए जाने वाले काम को ध्यान में रखते

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

हुए, अस्थायी नियुक्तियां करने या रोजगार की पेशकश करने से नहीं हिचकिचाती है। प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दैनिक वेतन पर श्रमिकों को नियुक्त करना।

(पैरा 14)

आगे कहा गया कि न्यायालय ने नव अधिनियमित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर ध्यान दिया, जिसका उद्देश्य अधिनियम के तहत तय मजदूरी के भुगतान पर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिनों के लिए रोजगार देना है। न्यायालय फैसले के केंद्रीय विषय पर पहले से ही विचार कर रहा था कि जहां सार्वजनिक पद और नियमित रिक्तियां उपलब्ध हैं, उन्हें भर्ती के नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए न कि उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। रिक्तियों को "अव्यवस्थित तरीके से या संरक्षण या अन्य विचारों के आधार पर नहीं भरा जा सकता है। नियमित नियुक्ति नियम होना चाहिए"। देश में एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसका परिणाम उमादेवी था, जहां संघ और राज्यों ने, राज्य के साधनों के अलावा, विशेष रूप से कर्तव्य और संवैधानिक संदर्भ के बिना कैडर के खिलाफ सेवा के निचले स्तर पर बड़े पैमाने पर अनियमित नियुक्तियों का सहारा लिया था। लोक सेवा आयोगों के माध्यम से या अन्यथा निर्धारित नियमों के अनुसार उचित नियुक्ति प्रक्रिया का पालन और सुनिश्चित करके नियुक्ति करने की शक्ति के प्रयोग पर

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

सीमाएं लगाई गई हैं और इन अनियमित नियुक्तियों या अनुबंध पर या दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त लोगों को साल दर साल जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार जो लोग संबंधित पद के लिए आवेदन करने के योग्य हैं उन्हें बाहर रखा जाता है और उन्हें प्रतिस्पर्धा करने के अवसर से वंचित किया जाता है। न्यायालय पिछले दरवाजे से प्रवेश और नियमित भर्ती को रोकने वाली सेवा की जाँच करने की दुविधा में व्यस्त था।

(पैरा 15)

इसके अलावा, संविधान पीठ इस बात से अवगत थी कि न्यायालयों ने हमेशा कानूनी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा है और कभी-कभी रोजगार की नियमित प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है और कुछ मामलों में यह निर्देश भी दिया है कि ये अवैध, अनियमित और अनुचित प्रवेशकर्ता हैं। सेवा में लीन हो जाओ. उच्चतम न्यायालय ने रोजगार के इस वर्ग को "मुकदमेबाजी रोजगार" कहा है, जो किसी संवैधानिक संरक्षण का हकदार नहीं है। न्यायालय ने ए.उमरानी बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ और अन्य; 2004 (7) एससीसी 112 में अपने पहले के फैसले पर गौर किया और इसकी फिर से पुष्टि की। यह विचार है कि राज्य ऐसी नियुक्तियों को नियमित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है, नियमितीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत किसी भी राज्य प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति या किसी प्राधिकारी द्वारा भर्ती का एक वैध

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

तरीका नहीं है और न ही हो सकता है। एक वैधानिक अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित। तदर्थ नियुक्तियों को कोई नियमितीकरण नहीं मिल सकता है। तदर्थवाद के पिछले दरवाजे से की गई किसी भी अवधि की सेवा का मतलब यह नहीं होगा कि उन्होंने नियमितीकरण का अधिकार हासिल कर लिया है।

(पैरा 16)

इसके अलावा यह माना जाता है कि परिभाषा के अनुसार कामगार सार्वजनिक पद पर हो भी सकते हैं और नहीं भी, उनका रोज़गार सार्वजनिक रोज़गार हो भी सकता है और नहीं भी, उनकी सेवा शर्तें नियमों द्वारा शासित हो भी सकती हैं और नहीं भी, वे पिछले दरवाजे से प्रवेश हो भी सकते हैं और नहीं भी, वे संरक्षण के माध्यम से प्रवेश हो भी सकते हैं और नहीं भी। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में सिफ़ारिश आदि, लेकिन राज्य सरकार को अपनी अवशिष्ट शक्ति में उन्हें कार्यालयों में राज्य या केंद्रीय परियोजनाओं पर काम करने के लिए या राज्य विभागों द्वारा वन के बाहरी इलाकों में दूर-दराज के स्थानों में काम करने के लिए नियोजित करने का अधिकार दिया गया था। सिंचाई विभाग में तब उनका प्रवेश विशेष क्षेत्र की स्थितियों में घृणित नहीं था। दूरदराज के इलाकों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं कर सकती है और अक्सर नहीं भी कर सकती है। दुर्गम क्षेत्रों में साइट पर प्राप्त श्रम स्थानीय श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा का हकदार हो



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

सकता है क्योंकि वे आसानी से मिल जाते हैं और राज्य सरकार की परियोजनाओं या योजनाओं को पूरा करने के लिए दूरदराज के गांवों में काम करने के इच्छुक होते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार की पेशकश करके स्थानीय व्यवस्था की जाती है। संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करने और इसकी अव्यवहारिकता के कारण आयात करने से करदाताओं के पैसे की बर्बादी हो सकती है। यहां अखबारों में दिए गए महंगे विज्ञापन बड़ी संख्या में स्थानीय मजदूरों के लिए अल्प मजदूरी पर खर्च किए गए पैसे का समर्थन और प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो प्रयास मोमबत्ती के लायक नहीं हो सकता है। यदि बहुत कम लोग होंगे तो कम वेतन के कारण दूर-दराज के स्थानों में दैनिक वेतन सेवा लेने के लिए चूल्हा और घर छोड़ देंगे, जो शायद ही विस्थापन के खर्चों की भरपाई के लिए पर्याप्त हो। मुझे हरियाणा वन विभाग में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के मामले से निपटने का अवसर मिला, क्योंकि दमयंती बनाम पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, पानीपत और अन्य, 2012 (4) एस.सी.टी. के इस मामले में अधिकांश याचिकाकर्ता हैं। 506 सिंगल बेंच में बैठे-बैठे मैंने फिर सोचा:-

“एक दैनिक मजदूर या मौसमी श्रमिक भी औद्योगिक अधिकारों वाला एक श्रमिक है। मुझे कोई नियम नहीं दिखाया गया कि मौसमी श्रमिकों या दैनिक वेतनभोगियों की भर्ती कैसे की जाती है। यह स्वाभाविक है कि दूर-दराज के स्थानों में जहां वन विभाग के पास स्थानीय स्तर

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

पर उपलब्ध श्रमिकों को रोजगार देने के लिए काम चल रहे हैं। इसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसे रोजगार के अवसर में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर खरा उतरने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन होने ही चाहिए। वास्तव में यह अंदरूनी इलाकों में छोटे, अकुशल या अर्धकुशल दैनिक वेतन वाले काम के लिए बाहरी लोगों को शामिल करना स्थानीय श्रम अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि अनुच्छेद 14 और 16 को राज्य के लिए बहस के लिए सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि दुर्भाग्य से ऐसे मामलों में नियमित रूप से ऐसा होता है कि नियुक्ति नियम से परे होती है। मैं पूछता हूँ कि 15 वर्षों तक कम वेतन पाने वाले कर्मचारी का शोषण करना और फिर दैनिक वेतन पर मौसमी श्रमिकों की नियुक्ति के नियम का हवाला देना और यह तर्क देना कि वन विभाग कोई उद्योग नहीं है, किस नियम का उल्लंघन है। यह वन विभाग के लिए बहुत ही शर्म की बात है।"

(पैरा 18)

इसके अलावा यह माना गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के विशेष कानून द्वारा संरक्षित संवैधानिक सिद्धांतों और औद्योगिक कानून के नियमों दोनों पर श्रम और औद्योगिक अधिकारों की जांच की जानी चाहिए और ऊपर (iv) में पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर पहले उदाहरण में दिया जाना चाहिए कि क्या उमादेवी कास्टेरिबे में न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले में इसे प्रतिष्ठित और स्पष्ट किया गया है।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने महाराष्ट्र के राज्य कानून, जिसे ट्रेड यूनियनों की महाराष्ट्र मान्यता और अनुचित श्रम अभ्यास रोकथाम अधिनियम 1971 (एमआरटीयू और पीयूएलपी अधिनियम) के रूप में उद्धृत किया गया, पर विचार किया। न्यायालय ने धारा 21(1) और उसके प्रावधान पर विचार किया; अनुसूची IV आइटम 2,5,6 और 9 और विशेष रूप से आइटम 6 के साथ, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की 5वीं अनुसूची की प्रविष्टि 10 के प्रावधानों के साथ समरूपता में है, श्रमिकों को बुरे लोगों के रूप में रखने के लिए अनुचित श्रम अभ्यास का एक पहलू है। , कैजुअल या अस्थायी और उन्हें स्थायी श्रमिकों की स्थिति और विशेषाधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से "वर्षों तक" ऐसे ही जारी रखना।

(पैरा 19)

इसके अलावा यह माना गया कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कास्टराईब में निगम द्वारा उठाया गया तर्क यह था कि जहां औद्योगिक न्यायालय ने पाया है कि निगम ने शिकायतकर्ताओं को पीस-रेट के आधार पर कैजुअल के रूप में नियोजित करने में अनुचित श्रम व्यवहार में लिप्त पाया है, तो एकमात्र निर्देश जो हो सकता है निगम को इस तरह के अनुचित श्रम व्यवहार में शामिल होने से रोकने और रोकने के लिए दिया गया था और उन कर्मचारियों को स्थायीता देने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि उसे अधिनियम के तहत औद्योगिक/श्रम न्यायालय को दी गई विशिष्ट शक्ति

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

मिली। दोषी नियोक्ताओं के खिलाफ सकारात्मक कार्रवाई करें और ऐसे अनुचित श्रम व्यवहार से प्रभावित कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान करने के आदेश दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने सार्वजनिक परिवहन चलाने वाली बसों के लिए निगम द्वारा सफाईकर्मियों के रूप में नियोजित शिकायतकर्ताओं को दर्जा और स्थायित्व देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश में कुछ भी गलत नहीं पाया। उमादेवी में जारी किए गए निर्देशों को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तक ही सीमित माना गया था, जिसमें दैनिक वेतन या तदर्थ कर्मचारियों के अवशोषण / नियमितीकरण के संबंध में निर्देश जारी नहीं किए गए थे, जब तक कि भर्ती स्वयं नियमित नहीं हो जाती। संवैधानिक योजना का. हालाँकि, नियोक्ता के अनुचित श्रम व्यवहार के शिकार लोग स्थायित्व की स्वतंत्रता के पात्र हैं जहाँ तथ्यों और परिस्थितियों की कास्टेरिबे के कैनवास में मांग होती है।

(पैरा 21)

आगे यह माना गया कि मामलों के इस समूह में दावा सेवा की निरंतरता के साथ बहाली प्रदान करने वाले श्रम न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न होता है। यदि याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा पारित गैरकानूनी आदेशों द्वारा सेवा से बाहर रखा गया था, तो अनुपस्थिति की अवधि को 5 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 10 के तहत सुरक्षा के अधिकार के

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

साथ सेवा की कुल अवधि में जोड़ने के लिए निरंतर सेवा के रूप में माना जाना होगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम में, बशर्ते कि वे अधिनियम की धारा 2 (एस) के अर्थ में 'कर्मचारी' के रूप में अर्हता प्राप्त करें, जो स्पष्ट रूप से साक्ष्य के माध्यम से बिना किसी विशेष सबूत के प्रतीत होता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को औद्योगिक निर्णायक द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सेवा में बहाल किया गया है और वे अनुचित भेदभाव के दोष को दूर करने के लिए "भाग्यशाली समूह" के बराबर रखे जाने के पात्र हो सकते हैं, जहां "भाग्यशाली समूह" सुरक्षित है। नियमितीकरण या स्थायीकरण के आदेश प्रशासक द्वारा, न कि न्यायालय द्वारा। इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेशों से याचिकाकर्ताओं को मुकदमेबाजी प्रकृति की बदनामी का सामना नहीं करना चाहिए और न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले पीड़ित व्यक्तियों के दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। इसलिए इस बैच के वे मामले जिनमें व्यक्ति अंतरिम संरक्षण द्वारा या अन्यथा सेवा में बने रहे हैं, उन्हें उन याचिकाकर्ताओं के साथ एक ही समूह में रखा जा सकता है, जिन्होंने नियमितीकरण के लिए अपने अभ्यावेदन को अदालत की घोषणा से पहले या बाद में खारिज कर दिए जाने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

(पैरा 23)

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

आगे कहा गया कि सवाल उठता है कि क्या अनुचित श्रम व्यवहार को केवल औद्योगिक न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित और स्थापित किया जा सकता है या परिणाम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हस्तक्षेप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या जिसे हम रिट द्वारा प्रयोग किए जाने वाले असाधारण क्षेत्राधिकार में कह सकते हैं। न्यायालय ने पीड़ित व्यक्तियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की मशीनरी के तहत उपलब्ध एक कम प्रभावकारी और लंबे समय तक चलने वाले वैकल्पिक उपाय के लिए हलफनामे पर रोक दिया है, जब ऐसे व्यक्तियों ने औद्योगिक न्यायनिर्णयन के माध्यम से बहाली हासिल की है, जहां निष्कर्ष आया है कि समाप्ति या छंटनी गैरकानूनी या गैरकानूनी थी।

(पैरा 24)

आगे यह माना गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की 5वीं अनुसूची की प्रविष्टि 10 में मेरे विचार से "कर्मचारियों को बदमाश, कैजुअल या अस्थायी के रूप में रखने और उन्हें इस उद्देश्य के साथ वर्षों तक जारी रखने के क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य को स्थापित करने के लिए साक्ष्य प्रमाण द्वारा किसी विशेष निर्णय की आवश्यकता नहीं है। उन्हें स्थायी श्रमिकों की स्थिति और विशेषाधिकारों से वंचित करना" जहां दैनिक वेतन सेवा के अंदर और बाहर बिताई गई सेवा की अवधि को श्रम न्यायालय के आदेशों के माध्यम से प्राप्त कानूनी कल्पना के साथ

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

जोड़ दिया जाता है, जो अंतिम रूप ले चुका है क्योंकि दावों को निर्धारित करने के लिए किसी विशेष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। समूह को "भाग्यशाली समूह" के बराबर लाने के लिए छोड़ दिया गया। इस बिंदु पर अनुचित भेदभाव के प्रश्न में प्रवेश करना उचित हो सकता है और इसलिए ओम कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित कानून को समझना और यह वर्तमान मामलों के तथ्यों पर कैसे लागू हो सकता है।

(पैरा 25)

इसके अलावा यह माना गया कि इस मुद्दे को ऊपर प्रश्न (vi) में चित्रित किया गया है और उत्तर की तलाश में न्यायालय के लिए बोलने वाले न्यायमूर्ति एम जगन्नाथ राव के फैसले के निम्नलिखित उद्धरणों को देखने और लेख के दो हिस्सों को शल्य चिकित्सा से अलग करने के अलावा किसी और विस्तार की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि यह निर्णय अनुशासनात्मक कार्यवाही और प्रतिस्पर्धी अपराधी दलों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए उच्च स्तर की सज़ा देने के संदर्भ में दिया गया था, लेकिन निर्धारित सामान्य सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं जब तक कि प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। पैरा 51 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय परिदृश्य में 1950 से मौलिक स्वतंत्रता के चार्टर का अस्तित्व हमारे कानून को अलग करता है और विधायी और साथ ही प्रशासनिक की वैधता का आकलन करने के मामले में हमारे न्यायालयों को इंग्लैंड की तुलना में अधिक

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

लाभप्रद स्थिति में रखा है। जहां तक कार्रवाई का संबंध है। जब मनमानी का सिद्धांत उठाया जाता है, तो आनुपातिकता और अनुचितता का परीक्षण वेडनसबरी नियम पर किया जाता है जो भारत में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। प्रशासनिक निर्णयों को आनुपातिकता और कथित मनमानी के खिलाफ अनुचित भेदभाव दोनों पर परीक्षण किया जाना चाहिए जहां न्यायालय आनुपातिकता के चयन में प्राथमिक भूमिका निभाने वाले प्रशासक की माध्यमिक समीक्षा का परीक्षण लागू करता है। हालाँकि जब अनुच्छेद 14 के तहत आधारित वर्गीकरण को प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध लाया जाता है तो भेदभावपूर्ण वर्गीकरण और मनमानी के सिद्धांत उत्पन्न होते हैं।

(पैरा 26)

आगे यह माना गया कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रिट कोर्ट को जब अनुचित व्यापार भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य है और गलत तरीके से भेदभाव करने वाले व्यक्ति को समान स्तर पर रखकर शत्रुतापूर्ण और द्वेषपूर्ण भेदभाव के दोष को दूर करने में अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहेगा। "भाग्यशाली समूह" (जैसा कि इस मामले में परीक्षण किया गया है) उपचार में समानता लाता है, खासकर जब "भाग्यशाली समूह" ने नीतिगत योजनाओं के तहत नियमितीकरण/स्थायित्व के प्रशासनिक आदेश प्राप्त किए हैं, हालांकि वे योजनाएं अब अदालत के हस्तक्षेप के बिना राज्य द्वारा



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। इस मामले में यहां प्रशासनिक कार्रवाई की तर्कसंगतता या मनमानी के आधार पर जांच की जाने वाली माध्यमिक समीक्षा का कोई सवाल ही नहीं है। रिट कोर्ट अनुचित भेदभाव का प्राथमिक निर्णायक बन जाता है जो वैधानिक औद्योगिक अधिकारों से उत्पन्न हो सकता है लेकिन 5वीं अनुसूची की प्रविष्टि 10 को न्यायिक मंच तक पहुंचाकर अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखा जाता है और जो असाधारण रूप से निर्णय लेने में असमर्थ नहीं है। रिट न्यायालय का क्षेत्राधिकार जहां राज्य न्यायालय को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि उसकी कार्रवाई भेदभाव से मुक्त है और जहां मूलभूत और क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य विवादित नहीं हैं। परिणाम केवल "वर्षों तक" प्रदान की गई लंबी सेवा के फार्मूले को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है जो वैधानिक रूप से प्रविष्टि 10 द्वारा संरक्षित है। "वर्षों तक" का क्या अर्थ है यह कला में से एक नहीं है। यह इसे लागू करने की व्याख्या का अधिक प्रश्न है असहनीय और दमनकारी अवधि जैसी चीजें, सेवा में हताशा का बिंदु, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के प्रति आशा की हानि, जहां सेवा करने की भावना मर सकती है, लेकिन व्यावहारिक मानवतावाद के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है, जिसे मापना मुश्किल हो सकता है। हालांकि केवल एक बात निश्चित है कि नियोक्ता ने बहुत पहले ही किसी सहकर्मी को स्थायित्व प्रदान कर दिया होगा। ऐसी कोई भी राय व्यक्त करना मुश्किल है जो इस मामले में आवश्यक नहीं है और इसे खुला छोड़ दिया गया है, यह संख्यात्मक प्रश्न है कि इसमें "वर्ष के लिए" होने का क्या मतलब है या योग्यता है प्रविष्टि 10. यह आवश्यक नहीं है क्योंकि इन

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

मामलों में सहकर्मियों की तारीखें "भाग्यशाली समूह" को उनके संबंधित निर्धारण बिंदुओं में ज्ञात होती हैं। लेकिन मैं कम से कम इतना तो कहूंगा कि यह मनुष्य द्वारा स्वयं मनुष्य के शोषण के विरुद्ध एक नियम है।

(पैरा 28)

इसके अलावा यह माना गया कि एक पीड़ित व्यक्ति, जिसके पास औद्योगिक निर्णायक के समक्ष वैकल्पिक उपचार हैं, को केवल एक औद्योगिक संदर्भ पर मुकदमे में डालना, जहां अकेले संघ द्वारा कारण का समर्थन किया जा सकता है, मेरे विचार से यह चोट का अपमान करना और देरी करना और स्थगित करना होगा। सुदूर भविष्य में किसी अप्रत्याशित और अज्ञात बिंदु पर गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार का अधिकार, जो औद्योगिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। इसमें कई जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। अनुचित भेदभाव को दूर करना आज मौलिक मूल्य है और लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी के बाद भेदभाव को दूर करने के समान नहीं है। समानता खंड के चश्मे से देखने पर न्यायालय इस पर आंखें नहीं मूंद सकता। इसलिए मेरे विचार में रिट कोर्ट कैस्टेरिबे के अनुपात के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की 5वीं अनुसूची की प्रविष्टि 10 के माध्यम से समीचीनता के सिद्धांत पर पहली बार औद्योगिक कानून सिद्धांतों को अच्छी तरह से लागू कर सकता है, बशर्ते तथ्य गंभीर रूप से विवादित न हों, लेकिन विवादित न हों। प्रतिरोध और खंडन के लिए प्रविष्टि 10 को

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

इस तरह से अर्थ दिया जाना चाहिए जिससे हाशिए पर रहने वाले श्रमिकों का समय और खर्च बचे, अभियान सफल हो और अदालत के संसाधनों की भी बचत हो और श्रम अदालत में लंबे मुकदमे की पीड़ा से बचा जा सके जब तक परिणाम प्राप्त किया जा सके। असाधारण रिट क्षेत्राधिकार कानून के चार कोनों के भीतर काम करता है, जो ज्यादातर औद्योगिक कानून सिद्धांतों पर आधारित होता है। रेस इप्सा लोकिटुर नियम को उचित रूप से सावधानीपूर्वक लागू किया जा सकता है और एक कमजोर नागरिक के प्रतिस्पर्धी हितों और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवारत स्थानीय श्रमिकों के लिए शक्तिशाली राज्य के बीच सावधानी से तौला जा सकता है।

(पैरा 29)

इसके अलावा यह माना गया कि किसी नियोक्ता, कामगार या ट्रेड यूनियन के खिलाफ अनुचित श्रम व्यवहार करने पर पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध है, हालांकि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25वीं के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कारावास की सजा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है श्रम न्यायालय या रिट न्यायालय को घोषणा करने और निर्देश जारी करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है, जहां प्रथम दृष्टया कानून के उल्लंघन का मामला बनता है। जहां तथ्यों पर आधारित मुद्दे इतने जटिल नहीं पाए जाते हैं कि श्रम न्यायालय के समक्ष केवल साक्ष्य और सबूत के माध्यम से

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

समाधान किया जा सके, तो इस न्यायालय को निष्पक्ष भेदभाव के कारण लगातार अधिकार से वंचित होने से पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए कार्य करने से नहीं रोका जा सकता है। इसके विपरीत अनुचित भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत एक बाध्य कर्तव्य के तहत रहेगा। प्रविष्टि 10 शोषण के विरुद्ध एक नियम है। यह आधुनिक गुलामी और अनुचित वर्चस्व के खिलाफ एक नियम है। अनुचित श्रम व्यवहार अनुचित भेदभाव के समान है। वे दोनों एक ही परिवार से हैं। केंद्रीय अधिनियम की प्रविष्टि 10 और महाराष्ट्र अधिनियम की प्रविष्टि 6 यह मानती है कि एक ही नियोक्ता के अधीन और एक ही काम करने वाले श्रमिकों का एक समूह स्थायी है, जबकि अन्य नहीं। इस प्रकार अनुचित श्रम व्यवहार प्रशासनिक कार्रवाई की चुनौती के आधारों के उसी समूह में आएगा, जब रिट कोर्ट दुर्भावना, कानून में द्वेष, वास्तव में द्वेष, पूर्वाग्रह, शक्ति का रंगीन प्रयोग या अधिकार के दुरुपयोग आदि से निपटता है। पर केवल इसलिए कि केंद्रीय अधिनियम में एमआरटीयू और पीयूएलपी अधिनियम और उसकी धारा 30 जैसे विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं हैं, यह इस न्यायालय को अनुचित भेदभाव को दूर करने के लिए रिट कार्यवाही में बाधा नहीं डालेगा, जब भी प्रश्न शुद्ध हो तो श्रम न्यायालय के समक्ष उपचार का सहारा लिए बिना। और निर्णय लेने में सरल प्रविष्टि 10 या प्रविष्टि 6 की सेवा योग्यता परीक्षा के वर्षों की संख्या है जिसे बाद में कास्टेरिबे में माना जाता है।

(पैरा 32)

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

आगे कहा गया कि तब यह पूछा जा सकता है: कौन जानता है कि योग्यता कहाँ है? योग्यता का मूल्यांकन करने वालों की योग्यता कहाँ है, कौन जानता है? कौन जानता है कि सत्य अमूर्तता में कहाँ छिपा है? आइए हम उपदेश न दें या मूसा को हमारे लिए गोलियाँ लिखने के लिए न बुलाएँ। आइए हम कानून के दायरे में दूर-दराज के वन नर्सरी (सरकारी विभाग के कार्यालयों में नहीं) में कमजोर मैनुअल श्रमिकों के ऐसे लंबे समय तक चलने वाले शोषणकारी रोजगार का स्वतंत्र, उचित और उदारतापूर्वक समर्थन करने का प्रयास करें और याचिकाकर्ताओं को कुछ हद तक प्रदान करें। मजदूरों के रूप में भी स्थायित्व ताकि उनका दिन सूर्यास्त के साथ शुरू न हो। वास्तव में, जब तक परिदृश्य बदल नहीं गया, उन्होंने एक-एक ईंट जोड़कर राष्ट्र का निर्माण किया। उन्होंने वे घर बनाए जिनमें हम रहते हैं, जिन रेस्तरांओं में हम भोजन करते हैं, जिन सड़कों पर हम यात्रा करते हैं, जिन पर हवाई जहाज़ उतरते और उड़ान भरते हैं, और वह अदालत जिसमें हम न्याय देने के लिए बैठते हैं। वे न्यायाधीशों के आने से पहले अदालत में आये। ये राष्ट्र के गुमनाम निर्माता हैं जिनके पास उनके द्वारा अर्जित अल्प दैनिक मजदूरी के अलावा न तो पुरस्कार है, न आशा और न ही कोई प्रतिफल, जिसका भुगतान शायद दिन के अंत में उन्हें अपने घर जाने से पहले भी नहीं किया जा सकता है, न जाने कहाँ।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

आगे कहा गया कि लेकिन जब तक 'समाजवाद' शब्द संविधान की प्रस्तावना में रहता है तब तक न्यायाधीश संवैधानिक रूप से वितरणात्मक न्याय लागू करने के लिए बाध्य हैं जो कहता है: "प्रत्येक को उसके योगदान के अनुसार" ऐसे योगदान को कौन माप सकता है? निश्चित रूप से न्यायाधीश नहीं, लेकिन हाँ, यदि चिकित्सक बीमारी को ठीक करने में विफल रहता है तो न्यायाधीश एक सर्जन की तरह हस्तक्षेप कर सकता है। यदि प्रशासक वितरणात्मक न्याय के प्रीमियम के साथ भुगतान की गई सामाजिक बीमा योजना के आधार पर आराम के लिए आवश्यक सहायता की न्यूनतम खुराक की गणना करने के बोझ का निर्वहन करने में अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल रहता है, तो न्यायालय न्याय के पिपेट को कैलिब्रेट कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 51ए (जे) द्वारा दिए गए मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के लिए बाध्य करते हैं ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। अफसोस की बात है कि संविधान का यह हिस्सा उस दिन से अड़तीस साल की विकृति से अपंग है, जब संसद ने बिग बुक में छापना उचित समझा।

(पैरा 37)

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

आगे कहा कि इन सबके सामने मैं यह सोचने के लिए इच्छुक हूँ कि मामलों का वर्तमान समूह "उदार और उद्देश्यपूर्ण निर्माण" के लिए इस तरह के असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होता है और संकट से निपटने के लिए एक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। एम.नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को इस तरह के दृष्टिकोण का अनुकरण करने और पालन करने की सलाह दी है, जिसे दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों से अलग व्यवहार करते समय अनुच्छेद 14 के सिरिंज द्वारा अदालत में पेश किए गए गतिशील और व्यावहारिक मानवतावाद का आदर्श सिद्धांत होना चाहिए। उन व्यक्तियों के मामले जिन्हें पिछले दरवाजे से सार्वजनिक पदों पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों या राज्य, बोर्ड, निगम आदि के स्वतंत्र उपकरण बनाने वाले वैधानिक अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। यह एक नागरिक न्यायाधीश का संवैधानिक कर्तव्य है जैसा कि भारत के प्रत्येक अन्य नागरिक का है कि यह संसद द्वारा 1976 में किए गए बयालीसवें संशोधन द्वारा प्रस्तुत संविधान के अनुच्छेद 51 ए (एच) द्वारा संरक्षित और निर्देशित कर्तव्य है कि यह है 'मानवतावाद' की भावना विकसित करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

(पैरा 40)

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

इसके अलावा यह माना गया कि मानवतावाद भारत के सभी नागरिकों के लिए दूरगामी महत्व का एक संवैधानिक शब्द बन गया है जिसका अनुकरण किया जा सकता है और न्यायाधीशों और नौकरशाहों सहित अपने निर्णयों और प्रशासनिक निर्णयों को संयमित करने के लिए सम्मान के लिए बाध्य महसूस किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अंततः पहले एक नागरिक होता है और उसके बाद पद धारण करने के आधार पर न्यायाधीश होता है। यदि संविधान या कानून द्वारा न्यायालय और प्रशासक पर ऐसे नैतिक कर्तव्य और नैतिक मानकों का पालन करने का कर्तव्य डाला गया है तो यह उन अधिकारों, विशेषाधिकारों या शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक महान और उत्कृष्ट है जिनका वे आनंद ले सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। न्याय प्रशासन या शासन में। संविधान एक विनम्र दस्तावेज़ है, एक शाश्वत स्रोत है जो हमेशा फूटता रहता है और कारण के लिए उचित, उचित और आनुपातिक रूप से निर्णय लेने के लिए शक्ति और अधिकार का सौम्य मार्गदर्शन करता है। यह स्वयं अपनी संवैधानिक सीमाओं पर आत्मसंयम का काम करता है। एक न्यायालय को कानून के अनुसार सामाजिक रूप से उचित आदेश देने के लिए राज्य द्वारा स्वीकृत एक निर्णय लेने वाले उपकरण के रूप में माना जा सकता है, निर्णय बाध्यकारी है और इसके बाध्यकारी क्षेत्राधिकार की गंभीर प्रकृति एक दुर्जेय बाधा और जांच के रूप में कार्य करती है। आदेश या निर्णय देने में यह क्या कर सकता है या क्या करने से बच सकता है। सभी नागरिकों को सौंपा गया कर्तव्य, जिसमें स्पष्ट रूप से उनके पद के आधार पर उच्चतम न्यायपालिका के सदस्य



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

भी शामिल हैं, संविधान के अगुआ के रूप में खड़ा है और जो संसद के ज्ञान के अनुसार अनुच्छेद 51 ए (एच) में योग्य है: - "वैज्ञानिक विकास करना स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना"।

(पैरा 41)

आगे कहा गया कि जब संविधान हमें आगे बढ़ने का निर्देश देता है तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। संवैधानिक कर्तव्य तब संवैधानिक अनिवार्यता और न्यायिक सीमा बन जाता है। फिर न्यायाधीश को अपने सभी निर्णयों को संवैधानिक आदेश के अनुरूप सूचित करना चाहिए। तब न्यायाधीश के लिए कर्तव्य अपने आप में उसके व्यवसाय का आदेश बन जाता है कि वह हमेशा इस मुद्दे से अलग और उदासीन रहे। न्यायाधीश प्रशासक नहीं है। एक प्रशासक यह तर्क दे सकता है और सुना जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य अप्रवर्तनीय हैं। लेकिन न्याय प्रदान करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, न्यायालय इन सिद्धांतों को खारिज नहीं कर सकता है यदि कोई अन्य पूर्ण कानूनी सिद्धांत किसी अन्य तरीके से राहत को पूरी तरह से उचित ठहराने वाला नहीं पाया जाता है। यह रिट के माध्यम से इस कर्तव्य को लागू करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन यदि इसके सिद्धांतों पर आवश्यकता उत्पन्न होती है तो यह अपनी राय बदल सकता है। हालाँकि कर्तव्य

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

को केवल संवैधानिक तरीकों से ही बढ़ावा दिया जा सकता है, संदर्भ: मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुलभाई, एआईआर 1976 एससी 1455.

(पैरा 42)

इसके अलावा यह माना गया कि मैनुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी राज्य के अधीन या राज्य के मामलों के संबंध में बोल्ट पोस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को बासी से पूछने की कोशिश करने और समझने के लिए उन्हें मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। यद्यपि गतिशील मानवतावाद की भावना के साथ उनकी स्थिति सुधारने में उनकी मदद करना, क्योंकि अमीर और शक्तिशाली लोगों को वास्तव में उन्हें समझने या उनके साथ सहानुभूति रखने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इन मामलों के सेट के संबंध में स्टेल द्वारा अपने जवाबों में दिखाए गए भर्ती नियमों की अनुपस्थिति में, इस अदालत के लिए कई वर्षों पहले की गई नियुक्तियों में नियम के उल्लंघन को पढ़ना संभव नहीं हो सकता है। दावों को खारिज करने के लिए मछली पकड़ने की जांच करना इस न्यायालय का काम नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह की व्यस्तताओं को देखते हैं, भले ही इसे 'नियुक्तियां' न कहा जाए, तो इसे मानवतावाद की भावना से जोड़ा जाना चाहिए और इसके बारे में न्यायिक रूप से व्यावहारिक होना चाहिए। मौजूदा ढील में नियमों को अपने आप में लोहे के परदे नहीं बनना चाहिए, जिसमें हाथ से काम करने वालों के लिए कोई अपवाद

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

नहीं होना चाहिए। पीड़ित जनता द्वारा अवैध नियुक्तियों को चुनौती देना जनहित याचिका में और भी अधिक खेदजनक है, जहां सेवा कानून के सिद्धांत उदाहरण का हवाला देते हुए एक गैरकानूनी नियुक्ति को रद्द करने में सक्षम नहीं हैं। यानी गलत काम करने वाले को कानून में कई सुरक्षाएं प्राप्त हैं, लेकिन वे सुरक्षाएं केवल तब तक ही होती हैं जब तक कि कुछ भी संभव होने पर न्यायालय की अंतरात्मा अशांत हो जाती है और हमें इसी तरह देखना चाहिए कि संवैधानिक न्यायाधीश क्या कर सकते हैं। यहीं पर एम. नागराज में न्यायमूर्ति कपाड़िया की अंतर्दृष्टि धड़कती है। यदि प्रशासक ने कानून को उसी तरह लागू किया और उसका पालन किया जैसा कि बनाया गया था और उसका मतलब था और उसने कभी भी नियम से परोक्ष विचलन नहीं किया था, तो यह कहना बेकार होगा कि हज़ारों और हज़ारों निर्णय लिखे नहीं गए होंगे या इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगर दुनिया में सब कुछ आदर्श रूप से ठीक होता तो शायद उमा देवी के बारे में नहीं लिखा जाता या इसकी आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार पूरी तस्वीर को न्यायालय की कलम द्वारा समग्र रूप से चित्रित किया जाना चाहिए, यहां तक कि राहत के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना में खड़े एक व्यक्ति के लिए भी। मैं यही सोचता हूँ और यह पूरी तरह गलत भी हो सकता है।

(पैरा 43)

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

आगे कहा गया कि उपरोक्त पृष्ठभूमि में विवादास्पद प्रश्न यह है: क्या वे दैनिक वेतन भोगी श्रमिक हैं, जिनका राज्य द्वारा अनुचित श्रम प्रथा का सहारा लेकर 'वर्षों से' शोषण किया गया है, क्या वे धूप, छाया में हिस्सेदारी के हकदार नहीं हैं? और चाँदनी, प्रार्थना करो क्या मैं काम की कुछ सुरक्षा माँग सकता हूँ। सवाल उठाने के बाद अभी भी एक जवाब है, राज्य द्वारा उठाए जाने पर एक स्वीकार्य बचाव के रूप में कानून द्वारा अनुमत एक जवाबी बिंदु जिसे राज्य अदालत में मुकदमे का सामना करते समय नियमित और आकस्मिक रूप से उठाता है: आखिरकार उन्होंने सगाई को शुरू करने के लिए स्वीकार क्यों किया? क्या किसी ने उन पर यह जबरदस्ती नहीं की? कौन किसी को मजबूर करता है? जो आदर्श नियोक्ता बनने की उम्मीद रखने वाले राज्य को नौकरी देने के लिए मजबूर करता है या नौकरी न छीनने के लिए मजबूर करता है। यह राज्य का विशेषाधिकार है जिसका पता अनुच्छेद 310 में आनंद सिद्धांत से चलता है। शामिल होने के अधिकार में अलग होने का अधिकार भी शामिल है। न्यायालय में तर्क को ग़लत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिर मानवतावाद के मानकों को लागू करने से यह संवैधानिक न्यायालय द्वारा राहत देने के मामलों में कानून के अनुरूप न्यायिक संवेदनशीलता का मामला बन जाता है, जहां जीवित ऊतकों को रक्त की आपूर्ति करने के लिए पिछले न्यायिक बोझों को खोलने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। कानून ताकि यह विघटित न हो।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

इसके अलावा यह माना गया कि इन मामलों में 13 दिसंबर 2013 को आदेश सुरक्षित रखे गए थे। उस समय मुझे संदेह था कि चन्नी (2013) और राजिंदर कुमार (2006) में दो डिवीजन बेंचों में प्रतिपादित कानून के सिद्धांत पूरी तरह से दैनिक आसानियों पर लागू नहीं हो सकते हैं। स्थानीय स्तर पर नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी और जिनकी सेवाएँ भर्ती के नियमों द्वारा कड़ाई से शासित नहीं हो सकती हैं। औद्योगिक कानून सिद्धांतों के सुविधाजनक बिंदु से अधिकारों की जांच और घोषणा की जानी चाहिए और इस प्रकार इन आसानताओं को अलग-अलग उपचार के लिए समूहित किया जाना चाहिए। सोच की यह दिशा कास्टेरीबे से प्रभावित थी जिसे चन्नी में डिवीजन बेंच के ध्यान में नहीं लाया गया था। आगे का कारण संविधान के अनुच्छेद 14 के दो अलग-अलग हिस्सों पर ओम कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों के अनुरूप था, एक मनमानी का और दूसरा भेदभाव का, जिसके सिद्धांतों को निर्णय लेने में शामिल किया जा सकता है। संबंधित पक्षों के अधिकारों के निष्पक्ष, सार्थक और प्रभावोत्पादक निर्णय के लिए प्रक्रिया। मनमानी के एक मामले में रिट कोर्ट को सूचित किया गया था कि वह द्वितीयक समीक्षा के सिद्धांतों को अच्छी तरह से लागू कर सकता है, लेकिन जब अनुचित भेदभाव की वकालत की जाती है, दबाव डाला जाता है और अभ्यास किया जाता है और मूलभूत तथ्यों पर गंभीरता से विवाद नहीं किया जाता है तो रिट कोर्ट के पास आरोपमुक्त करने के अलावा बहुत कम विकल्प बचता है। प्राथमिक

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

समीक्षा के सिद्धांतों को लागू करके अनुचित भेदभाव को खत्म करना उसका संवैधानिक कर्तव्य है, चाहे जो भी हो उस कर्तव्य से पीछे हटना नहीं। गनयुथम और ओम कुमार में बताए गए कानून के सिद्धांतों को भी अनुचित भेदभाव के बिंदु पर विचार के लिए चन्नी में डिवीजन बेंच के ध्यान में नहीं लाया गया था।

(पैरा 61)

आगे कहा कि आदेश सुरक्षित रखने के बाद निर्णय तैयार करने के बाद मैंने उत्सुकता से सोचा था कि मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसमें शामिल संवेदनशील मुद्दों पर क्या किया जाए और क्या मुझे चन्नी को अलग करना चाहिए और सुखमिंदर कौर का अनुसरण करना चाहिए और उमादेवी को कास्टेरिबे द्वारा अलग करना चाहिए या संदर्भित करना चाहिए श्री नेहरा द्वारा हरि नंदन प्रसाद और अन्य बनाम नियोक्ता 1/आर मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के दौरान उठाए गए संघर्ष को हल करने के लिए एक बड़ी बेंच के सामने तैयार किए गए आठ प्रश्न। एफसीआई और अन्य का; 2014 (2) एससीटी 234 मेरे संज्ञान में आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने चन्नी (दोनों माननीय श्री न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी द्वारा लिखित, जब उनके आधिपत्य ने इस न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया था, उससे एक दिन पहले) के तीव्र प्रस्थान में कास्टेरिबे और उमादेवी को नोटिस करने के बाद, सर्वोच्च

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

न्यायालय में उनके आधिपत्य के उत्थान के बाद) पैरा 34 में भेदभाव के जटिल प्रश्न को निम्नानुसार हल किया गया :-

"34. ऊपर विस्तार से चर्चा किए गए दो निर्णयों के सामंजस्यपूर्ण पढ़ने पर हमारी राय है कि जब किसी भी अनुचित श्रम अभ्यास के अभाव में पद उपलब्ध हों तो श्रम न्यायालय केवल इसलिए नियमितीकरण के लिए निर्देश नहीं देगा क्योंकि एक कर्मचारी दैनिक की तरह जारी रहा है कई वर्षों के लिए वेतनभोगी कर्मचारी/तदर्थ/अस्थायी कर्मचारी। इसके अलावा, यदि कोई पद उपलब्ध नहीं है, तो नियमितीकरण के लिए ऐसा निर्देश अस्वीकार्य होगा। उपरोक्त परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को केवल वर्षों की संख्या के आधार पर नियमित करने का निर्देश दिया जा रहा है। ऐसे कर्मचारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी आदि के रूप में सेवा में पिछले दरवाजे से प्रवेश माना जा सकता है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 के लिए अभिशाप है। इसके अलावा, ऐसा कोई निर्देश तब नहीं दिया जाएगा जब संबंधित कर्मचारी पद की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हो। भर्ती नियमों के अनुसार प्रश्न। हालाँकि, जहाँ भी यह पाया जाता है कि समान स्थिति वाले श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा किसी योजना या अन्यथा के तहत नियमित किया जाता है और जिन श्रमिकों ने औद्योगिक श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, वे ऐसे मामलों में नियमितीकरण की दिशा में उनके समान हैं। कानूनी रूप से उचित ठहराया जा सकता है, अन्यथा बचे हुए श्रमिकों का नियमितीकरण न करना ऐसे

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

मामलों में उनके साथ घृणित भेदभाव होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इस प्रकार औद्योगिक निर्णायक इस संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करने के बजाय अनुच्छेद 14 को बरकरार रखते हुए समानता प्राप्त करेगा।" (ज़ोर दिया गया)

(पैरा - 62)

आगे कहा गया कि फैसले में इस ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि ने स्थिति बदल दी है। तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए पैरा 34 में दिए गए फैसले ने औद्योगिक न्यायशास्त्र की सीमाओं को इतना व्यापक रूप से बढ़ाया है जितना पहले कभी नहीं हुआ था। यह यू.पी.एस.ई.बी बनाम पूरन चंद पांडे, 2007 (11) एससीसी 92 के समान ही है, जिसे आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अस्वीकार कर दिया था, जो कास्टेरिबे से पहले का निर्णय है।

(पैरा 63)

आगे यह माना गया कि उमादेवी (3) को अब श्रम न्यायशास्त्र के अनुप्रयोग में कास्टेरिबे और हरि नंदन प्रसाद दोनों के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए, पूर्व अनुचित श्रम अभ्यास के दृष्टिकोण से, बाद वाला दृष्टिकोण से। जबकि उमादेवी श्रम कानून के दायरे से परे हैं और मुख्य सेवा कानून न्यायशास्त्र और उनके सूक्ष्म अंतर से अलग हैं। श्रम कानून



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

कास्टेरिबे में चित्रित किया गया था। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी ताकत नहीं लगाई और उमादेवी (3) में निर्धारित संविधान पीठ के सिद्धांतों से बंधे रिक्तियों के सिद्धांतों और प्रारंभिक नियुक्तियों की प्रकृति के आधार पर सेवा कानून सिद्धांतों पर अपने फैसले को सीमित नहीं किया। फिर भी, हरि नंदन प्रसाद (पैरा 34) में उल्लिखित अपवाद वह जगह है जहां पैर जमा हुआ है और मामलों के वर्तमान बैच का समापन बिंदु अब आराम कर रहा है। अनुचित भेदभाव के सिद्धांतों पर नियमितीकरण की मांग अब औद्योगिक न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों के माध्यम से आने वाले मामलों में नियमितीकरण के अनुकूल कार्यालय आदेश पारित करने के लिए तेज हो गई है, जिससे भेदभाव पर संवैधानिक कानून सिद्धांतों को लागू करने की मांग बढ़ रही है। मैं कह सकता हूं कि कोई भी छोटा भेदभाव अनुचित नहीं है क्योंकि उस पर कानून द्वारा लिखित उचित प्रतिबंध लग सकते हैं। इसीलिए मैंने केवल अनुचित भेदभाव पर ध्यान दिया है जो न्यायिक रूप से अस्वीकार्य है, लेकिन केवल भेदभाव नहीं है जिस पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं। लेकिन यहां स्थिति अस्वीकार्य है क्योंकि किसी समरूप समूह को कृत्रिम रूप से तोड़ना कानूनी रूप से उचित नहीं है। ऐसा न होने पर बचे हुए श्रमिकों/दुर्भाग्यपूर्ण समूह का नियमितीकरण न करना, जैसा कि अब हरि नंदन प्रसाद में परिभाषित किया गया है, शत्रुतापूर्ण और द्वेषपूर्ण भेदभाव होगा, इसलिए समकक्षों को प्रशासनिक द्वारा नियमितीकरण का लाभ प्राप्त करने की तारीखों से यथास्थिति प्रदान करके संतुलन बहाल किया जाना चाहिए। न्यायिक हस्तक्षेप के बिना आदेश पारित किए गए।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

हरि नंदन प्रसाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि "...औद्योगिक निर्णायक इस संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करने के बजाय अनुच्छेद 14 को कायम रखकर समानता प्राप्त करेंगे"।

(पैरा 64)

इसके अलावा यह माना गया कि अनुच्छेद 14 में संवैधानिक सीमाओं से बंधे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रतिकूल राज्य कार्रवाई या निष्क्रियता के परिणामस्वरूप होने वाली अनुचित असमानता को मिटाने का आदेश दिया गया है और न्यायिक कर्तव्यों का पालन करते समय वे अनुचित भेदभाव को देखते ही उसे खत्म करने की शपथ लेंगे। उनके सामने रखे गए केस के कागजों से सिर फट गया। वे अनुच्छेद 14 के घास के मैदान में उगने से पहले खरपतवार को मारने के लिए बाध्य रहेंगे। अनुच्छेद 14 कम से कम कानून का दिल है जो संविधान की कोशिकाओं में रस पंप करता है ताकि यह अच्छी तरह से पोषित हो और एक बरगद के रूप में विकसित हो सके। वृक्ष अपनी जड़ प्रणाली के साथ सभी चीजों में व्याप्त है। एलेर दक्षिण अफ्रीका ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की, इसका प्रतीक संवैधानिक न्यायालय बरगद का पेड़ बन गया।

(पैरा 65)

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

इसके अलावा यह माना गया कि राज्य द्वारा किए जाने वाले किसी भी अनुचित भेदभाव को कानून की मजबूत बांह द्वारा कठोर सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए ताकि अनुचित भेदभाव को दूर किया जा सके और इसे बढ़ावा न दिया जाए ताकि किसी भी नागरिक के अधिकार बिना निवारण के न रह जाएं। याचिकाकर्ताओं को अकेला छोड़ देना और यह महसूस करना बेहद शर्म की बात होगी कि अनुच्छेद 14 उनके लिए नहीं है और केवल 'संपन्नो' के लिए है। अनुच्छेद 14 में समानता खंड को जानबूझकर नष्ट करना संविधान के लिए अभिशाप होगा। फिर न्यायाधीश भी अपना बैग पैक करके घर जा सकते हैं।

(पैरा 66)

इसके अलावा यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं के अधिकार जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन्हें सेवा की निरंतरता प्रदान करने के लिए उनके पक्ष में दिए गए श्रम न्यायालय के फैसले से अर्जित और प्रवाहित होते हैं। जहां श्रम न्यायालय द्वारा प्रेषक की निरंतरता प्रदान नहीं की जाती है और ऐसे पुरस्कारों ने अंतिम अवधि प्राप्त कर ली है, जिसके लिए पिछली सेवा का लाभ नहीं दिया गया है, तो इरादों और उद्देश्यों के लिए गणना योग्य अवधि से वंचित कर दिया जाएगा। वर्तमान मामलों में याचिकाकर्ताओं को सेवा में माना जाएगा जैसे कि प्रतिकूल छंटनी आदेश कभी पारित नहीं किए गए थे, राज्य इनमें से किसी भी मामले में याचिकाकर्ताओं की दैनिक नियुक्ति के लिए लागू सेवा के नियमों को दिखाने में सक्षम नहीं

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

था। जंगल और सिंचाई विभाग में दांव लगाना। इसलिए इन मामलों में उनकी अवैध या अनियमित नियुक्तियों का सवाल बहस का मुद्दा नहीं है और एक मजबूत धारणा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जाएगी कि उनकी प्रारंभिक नियुक्तियाँ कानून के विपरीत नहीं थीं, क्योंकि उन्हें नियोजित करने की शक्ति राज्य में थी। मस्टर रोल प्रणाली को संचालित करने के लिए मैनुअल से प्राप्त शक्ति के साथ अपने स्थानीय पदाधिकारियों के माध्यम से उन्हें दैनिक वेतन रोजगार की पेशकश करना। औद्योगिक विवाद अधिनियम बुनियादी सामाजिक कल्याण कानून का एक हिस्सा है जो संवैधानिक सेवा कानून से अलग और अलग है। हालाँकि जैसे-जैसे समय बीतता गया और वैश्वीकरण और मुक्त उद्यम के लिए भारत के खुलने के साथ प्रस्थान हुआ, धुरी को पूंजी की ओर एक आदर्श बदलाव का सामना करना पड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (2010) 3 एससीसी 192 में इस बढ़ती प्रवृत्ति को वापस लाने के लिए बात की। ज्वार-भाटा। हरजिंदर सिंह की अगुवाई में त्वरित निर्णयों की श्रृंखला से एक बड़ा बदलाव आया।

(पैरा 69)

आगे कहा कि जाने से पहले मैं प्रशासनिक कार्रवाई की प्राथमिक और माध्यमिक समीक्षा के सिद्धांतों पर कुछ और शब्द कहूंगा, जो कि ओम कुमार द्वारा दिए गए फैसले से कुछ साल पहले न्यायमूर्ति एम.जगन्नाथा राव द्वारा पेश किया गया था, अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

सही हूँ। भारत संघ बनाम गणयुथम में उनका आधिपत्य; (1997) 7 एससीसी 463. विषय पर कानूनी स्थिति को रिपोर्ट के पैरा 31 में संक्षेपित किया गया था, जो मेरे विचार से प्रशासनिक कानून और विषय वस्तु श्रम कानून में सार्वभौमिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम है। ऐसा प्रतीत होता है कि गणयुथम में उप पैरा 4(बी) में खुला छोड़ा गया प्रश्न यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम में इस विषय पर विदेशी न्यायालयों में शीर्ष स्तर पर बैठे न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों में बताई गई न्यायिक विचार प्रक्रियाओं को देखने के बाद ओम कुमार में विस्तृत रूप से उत्तर दिया गया है।

(पैरा 71)

आगे माना गया कि जहां तक प्राथमिक समीक्षा का सवाल है, अनुच्छेद 19 और 21 बहस योग्य थे। अनुच्छेद 14 प्रभावहीन था. यह समझौता योग्य नहीं है। ओम कुमार (सुप्रा) में अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के प्रश्न का उत्तर सीधे उसी माननीय न्यायाधीश द्वारा दिया गया था। इस प्रकार अनुच्छेद 14 के दमनकारी उल्लंघनों से निपटने के दौरान प्राथमिक समीक्षा क्षेत्राधिकार के पहले खोजपूर्ण और दूसरे व्याख्यात्मक दोनों फैसलों को एक साथ जोड़ना होगा। इसलिए जब प्राथमिक समीक्षा क्षेत्राधिकार के साथ सशक्त होता है तो न्यायालय कानून के समक्ष समानता का प्रशासक और रक्षक बन जाता है। और कानूनों की समान सुरक्षा ताकि मौलिक स्वतंत्रता को सार्थक, त्वरित और सुधारात्मक प्रभाव दिया जा सके, जब तथ्यों

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

की मांग हो और तथ्यों और परिस्थितियों में साक्ष्य आवश्यक न हो तो गैर-संवैधानिक न्यायनिर्णयन के माध्यम से निवारण के लिए ऐसे अधिकारों से वंचितों को स्थगित न किया जाए। एक दिया गया मामला. वर्तमान मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई की प्राथमिक समीक्षा के इन मानकों को लागू करके, जहां भाग्यशाली लोगों ने अदालत के हस्तक्षेप के बिना नियमितीकरण की स्वतंत्रता हासिल की है, लेकिन जिसके परिणामस्वरूप शत्रुतापूर्ण और द्वेषपूर्ण भेदभाव हुआ है, उन्हें कानून की नजर में बुरा घोषित किया गया है। कानून का शासन स्पष्ट रूप से मनुष्य की मनुष्य के प्रति अमानवीयता के विरुद्ध है। इस प्रकार का अभाव नागरिकों के बीच समानता के प्राकृतिक कानून का उल्लंघन है, जो मानव के रूप में दोनों के पास मौजूद बुनियादी अधिकारों के सभी मामलों में समान रूप से रखे गए हैं या हो गए हैं, भले ही 110 लिखित संविधान या वैधानिक कानून श्रमिकों को अन्याय से बचाते हों। जो लोग अपने समकक्षों के साथ समानता के व्यवहार के हकदार हैं, उनके साथ भेदभाव और अनुचित श्रम व्यवहार को श्रम न्यायालय के मुकदमे की धीमी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कानून की कल्पना से अनुकूल पुरस्कार प्राप्त होते हैं, फिर भी न्यायालय को आत्मा की अधीनता को खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। किसी भी पीड़ित व्यक्ति को यह सोचकर लौटाया नहीं जाना चाहिए कि न्यायालय प्रशासक द्वारा बनाए गए अनुचित असंतुलन को बहाल करने में सहायता करने में विफल रहा है।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

इसके अलावा यह माना गया कि उपरोक्त तथ्यों, कानून और निर्णयों के सूत्र को एक साथ पढ़ने पर और न्यायिक निर्णयों को आपस में जोड़ने वाले विभिन्न कारणों के लिए, सेवाओं के पूर्ववर्ती नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को उनके पक्ष में और राज्य के खिलाफ घोषित किया जाता है।

(पैरा 73)

आगे कहा गया कि रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। मामलों के इस बैच में नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कम करने के प्रतिवादी राज्य के आदेश को रद्द कर दिया गया है और रद्द कर दिया गया है। ऐसे मामलों में जहां 2003 से नियमितीकरण प्रदान किया गया है, वे इस फैसले के संदर्भ में उन तारीखों से पूर्व-दिनांकित होंगे, जब ऐसे याचिकाकर्ताओं को उनके पूर्व कनिष्ठों और साथी श्रमिकों से अलग कर दिया गया था। तदनुसार, इस आदेश पर सवाल उठाने के लिए निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, हरियाणा का स्लेट प्रत्येक मामले में इस निर्णय के संदर्भ में नए आदेश पारित करेगा।

(पैरा 74)

जे.एस.मणिपुर, अधिवक्ता, एचसीपीसीटीशनसीआर(एस) के लिए। (2004 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9024, 2013 का 27407)

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील मनोज चाहल) (सीडब्ल्यूपी संख्या 22885. 22886,  
23736, 2011 का 23745, 2012 का 14170, 10433. 15068. 2013 का 26220)

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील, विजय गुलेरिया । (2012 का सीडब्ल्यूपी नं. 17351)

याचिका दायर करने वालों के लिए, वकील एस.बी.कौशिक (2013 का CWP No.3901)

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील, राजेश मलिक, (2013 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9496)

याचिकाकर्ताओं के वकील बी.एस. रथी। (2013 का सीडब्ल्यूपी नंबर 23938)

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील संदीप ठाकन। (2013 का सीडब्ल्यूपी नंबर 27659)

याचिकाकर्ताओं के वकील दीपक सोनक। (सीडब्ल्यूपी नंबर 28074, 2013 का 28151)

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील के.बी.रहेजा। (2011 का सीडब्ल्यूपी नंबर 3526)

हरीश राठी, सीनियर डीएजी, हरियाणा और सुनील नेहरा, सीनियर डीएजी, हरियाणा ।



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

### जस्टिस राजीव नारायण रैना

(1) यह आदेश 19 याचिकाओं\* के एक समूह का निपटान करेगा क्योंकि इन मामलों में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं। उन्हें एक साथ सुना गया है और एक सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है। सुविधा के लिए तथ्य 2004 के सीडब्ल्यूपी नंबर 9024 से लिए गए हैं। भौतिक तथ्य 2011 के सीडब्ल्यूपी 10017 (खज्जन सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) से भी लिए गए हैं क्योंकि दोनों एक ही दर्पण के दो अलग-अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्व सुनवाई में हैं जबकि बाद वाले लेटर्स पेटेंट अपील से रिमांड पर हैं। **सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य(1)** मामले में निर्णय के बावजूद, भेदभाव के आधार पर न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना सरकार द्वारा कनिष्ठों को नियमित करने की तारीखों से नियमितीकरण की राहत देने के एकल पीठ के आदेशों के खिलाफ हरियाणा राज्य, {संक्षिप्तता के लिए 'उमादेवी'(3)}. 2011 के सीडब्ल्यूपी 10017 में पारित आदेश कमोबेश इस मामले के केंद्र में हैं जिस पर मैं बाद में चर्चा में आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहां जाऊंगा :- 2004 के सीडब्ल्यूपी नंबर 9024 के तथ्य :

(1) (2006) 4 एससीसी 1

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(2) 2004 की सीडब्ल्यूपी संख्या 9024 को 18 सितंबर 2004 को डिवीजन बेंच द्वारा नियमित सुनवाई के लिए छह महीने के भीतर अंतिम निपटान के लिए सूचीबद्ध करने के लिए स्वीकार किया गया था। इससे पहले 29 मई 2004 के एक अंतरिम आदेश द्वारा न्यायालय ने रिट याचिका के अंतिम निपटान के लिए उत्तरदाताओं को प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए 14 मई के छंटनी नोटिस के संचालन पर रोक लगा दी थी। 2004 (पी-4 एवं पी-5) प्रभागीय शुद्धतम अधिकारी, उत्पादन प्रभाग, यमुनानगर द्वारा जारी किया गया और दोनों याचिकाकर्ताओं को तामील किया गया और एक अंतरिम आदेश जारी करने में प्रसन्नता हुई जिसमें निर्देश दिया गया कि उन्हें उसी पद पर बने रहने की अनुमति दी जाएगी जिस पर वे थे। 14 मई 2004 को कार्यरत थे। मामले को नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए अगले आदेश तक जारी रखने का अंतरिम आदेश दिया गया। इस अंतरिम आदेश के बल पर ये याचिकाकर्ता वन विभाग की सेवा में दैनिक वेतनभोगी, श्रमिक या देहरिदार के रूप में बने रहे हैं।

(3) संक्षेप में कहा गया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 को 1 अक्टूबर 1986 को दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता नंबर 2 को इसी तरह 1 सितंबर, 1988 को नियुक्त किया गया था। ग्रुप-डी/सीआईएस-IV पद पर नियमितीकरण के उनके दावे को

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

विवादित पक्ष ने खारिज कर दिया था। आदेश दिनांक 11 मई, 2004 को इस आधार पर कि वे 31 जनवरी 1996 से पहले सेवा में नहीं थे और नीति परिपत्र के तहत निर्धारित नियत दिन 30 सितंबर 2003 को कार्यबल की रोजगार संख्या पर नहीं थे और इस प्रकार यह अनुरूप नहीं था। हरियाणा सरकार द्वारा प्रख्यापित नियमितीकरण की योजना में अधिसूचित शर्तें। उनका दावा है कि उन दोनों को 14 मई 2004 को बिना कोई कामकाजी वरिष्ठता/प्राथमिकता सूची प्रसारित किए सेवा से हटा दिया गया था ताकि उन्हें अपने सहकर्मियों के मुकाबले उनकी स्थिति का पता चल सके। इनमें से कुछ मामलों में याचिकाकर्ताओं को स्थगन आदेशों द्वारा संरक्षित किया गया था जबकि अन्य को नहीं।

(4) हालाँकि कुछ जुड़े हुए मामलों में ऐसे याचिकाकर्ता हैं जिन्हें इस न्यायालय के आदेशों द्वारा संरक्षित नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10(1)(सी) के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा दिए गए संदर्भों पर हरियाणा में विभिन्न श्रम न्यायालयों से संपर्क किया था। 1947 (संक्षेप में "अधिनियम") औद्योगिक निर्णायक के समक्ष लिखित या मौखिक रूप से जारी किए गए उनके समाप्ति आदेशों की वैधता पर सवाल उठाने के लिए। याचिकाकर्ताओं के इन समूहों ने अवैध समाप्ति/छंटनी की तारीखों से सेवा की निरंतरता के साथ बहाली प्रदान करते हुए अलग-अलग वर्षों में अपने पक्ष में पुरस्कार प्राप्त किए। इन मामलों में, पुरस्कार विवाद में

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

नहीं हैं क्योंकि वे अंतिम रूप ले चुके हैं और ऐसे याचिकाकर्ताओं ने अनुपालन में जारी प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से उन पुरस्कारों के कार्यान्वयन में दैनिक वेतन सेवा में बहाली हासिल कर ली है। ऐसे सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, जिनमें वन विभाग, सिंचाई विभाग आदि शामिल हैं, में सेवा कर चुके हैं या कार्यरत हैं।

(5) जिन मामलों में याचिकाकर्ताओं को छंटनी या समाप्ति के कारण सेवा से मुक्त कर दिया गया था, उन्हें अपने पक्ष में श्रम न्यायालय के फैसले हासिल करने में सफल होने से पहले मुकदमा करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उनकी अवैध छंटनी की संबंधित तिथियों से पूर्वव्यापी रूप से सेवा की निरंतरता के साथ बहाली हुई। उन्हें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का दर्जा वापस कर दिया गया है।

(6) यह पता चला कि जब वे कई अन्य दिहाड़ी मजदूरों पर मुकदमा कर रहे थे, जो उनके समय के दौरान या उसके बाद लगे थे, लेकिन गैर-छंटनी के कारण सेवा में बने रहे, इस बीच हरियाणा राज्य द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीति परिपत्रों के लाभ के प्राप्तकर्ता बन गए। समय-समय पर उनकी सेवाओं को सरकार द्वारा नियमित कर दिया गया है और वे सरकार के विभागों में तैनात नियमित कर्मचारियों के रूप में काम करना जारी रखते हैं। वे

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

याचिकाकर्ता इतने भाग्यशाली नहीं हैं जिन्होंने अपने खिलाफ पारित प्रतिकूल आदेशों के कारण सेवा में पुनः प्रवेश के लिए मुकदमेबाजी में समय बिताया, वे इस अदालत के समक्ष प्रतिवादी विभागों से पुरस्कारों के आधार पर नियमितीकरण का दावा कर रहे हैं, जिससे उन्हें उनकी प्रारंभिक तिथियों से सेवा की निरंतरता प्रदान की जा सके। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में नियुक्तियाँ/सगाई। इन याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे रोजगार की तारीख से अपने पूर्व कनिष्ठ सहकर्मियों के साथ समान और समानता के व्यवहार के पात्र हैं। यह समानता उसके तुरंत बाद नियोजित लोगों की दैनिक-मजदूरी के आधार पर नियुक्ति की तारीखों के संदर्भ में मांगी गई है, जिन्हें सरकार के विभिन्न नीति परिपत्रों के तहत नियमित की गई उनकी सेवाओं का लाभ मिला था, जिसमें छंटनी के समय परिचालन भी शामिल था।

(7) 10 अप्रैल 2006 से पहले याचिकाकर्ताओं के दावों को विभिन्न तकनीकी आधारों पर खारिज कर दिया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य (पूर्व), ("उमादेवी") मामले में फैसला सुनाया था। कुछ मामलों में, वर्तमान में नियमितीकरण की राहत से इनकार करने के लिए उमादेवी में निर्धारित कानून का हवाला दिया गया है। गैर-नियमितीकरण के औचित्य में राज्य का रुख न्यायिक घोषणाओं पर आधारित है, जिसके अनुसार राज्य ने इसे राहत देने में असमर्थ बना दिया है। इसका कारण यह है कि सेवा में उनका प्रारंभिक प्रवेश अवसर की समानता और गैर-भेदभाव प्रदान करने

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

वाले भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों द्वारा राज्य पर लगाई गई सीमाओं के आधार पर सार्वजनिक रोजगार की संवैधानिक योजना के विपरीत था।

(8) यह इस पृष्ठभूमि में है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष मामलों के इस समूह में उमादेवी से पहले समय-समय पर जारी नियमितीकरण पर नीति निर्देशों के संदर्भ में प्रतिवादी राज्य को उनकी सेवाओं को नियमित करने के निर्देश देने की प्रार्थना कर रहे हैं। यह दावा पिछली तारीख से इस आधार पर स्थापित किया गया है कि कनिष्ठों को इस बीच सेवा में नियमित कर दिया गया है और उन्हें अलग-अलग श्रम न्यायालयों में मुकदमेबाजी करने से छोड़ दिया गया है, जबकि उनके कनिष्ठों या इसी तरह के पदों पर बैठे व्यक्तियों ने छंटनी न होने की आकस्मिक परिस्थिति के कारण उनसे एक रास्ता चुरा लिया है। और अपने अधिकारों को स्थापित करने के लिए लंबी मुकदमेबाजी की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई केंद्रीय दलील समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच शत्रुतापूर्ण, द्वेषपूर्ण और अनुचित भेदभाव पर आधारित है; यानी जिसे अदालती हस्तक्षेप के बिना नीति परिपत्रों के तहत पारित प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से नियमितीकरण का लाभ मिला, जबकि परिस्थितियों के कारण 'छूटे हुए समूह' को समान उपचार के अवसर से वंचित कर दिया गया। यह उनकी सेवाओं की समाप्ति के कारण था, हालांकि वे समय-समय

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

पर सरकार द्वारा प्रख्यापित लाभकारी नीतियों की शर्तों और शर्तों को पूरा करते थे, लेकिन तत्कालीन प्रचलित योजनाओं के तहत नियमितीकरण के उनके अधिकार उनकी जबरन आलस्य और परिणामी अनुपस्थिति के कारण फलीभूत नहीं हो सके। कटऑफ तिथि पर कार्यस्थल पर। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1 अप्रैल 2006 को दिए गए उमादेवी के फैसले के बाद नीतियों को वापस लेने से पूर्वव्यापी प्रभाव से उनके अधिकार छीन नहीं लिए जाएंगे।

(9) संक्षेप में कहें तो सभी दिहाड़ी मजदूरों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली भाग्यशाली श्रेणी में दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं जो सेवा में बने रहे और उनकी छंटनी नहीं हुई और जो हरियाणा सरकार के नीति परिपत्रों के लाभार्थी थे, जिसके कारण उनकी सेवाओं को नियमित किया गया। दूसरी कम भाग्यशाली श्रेणी में दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं जो उन्हीं नावों पर चढ़े लेकिन उनमें सवार नहीं हुए। दिहाड़ी मजदूरों की इस श्रेणी में छंटनी किए गए मजदूर शामिल हैं, जिन्होंने अधिनियम के तहत अपने उपचार का सहारा लिया और औद्योगिक से सेवा की निरंतरता के साथ बहाली हासिल की। इससे उनकी पीड़ा समाप्त नहीं हुई। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक आदेशों द्वारा उन्हें उमादेवी के मामले में फैसले के छत्र संरक्षण के तहत नियमितीकरण का लाभ देने से इनकार कर दिया। यद्यपि "नहीं है" की यह श्रेणी बहाली के परिणामस्वरूप सेवा में बनी हुई है, लेकिन नियमितीकरण का लाभ मायावी अल्बार्ट्रॉस की तरह उनसे छूट गया है। इसलिए अनियमित दिहाड़ी मजदूरों का यह वर्ग इस न्यायालय के

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

समक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए जाता है कि उनके भाग्यशाली हमवतन को बिना मूँछें उठाए या कर्कश आवाज़ के क्या मिले। हम ऐसे ही हैं।

(10) प्रत्येक मामले के तथ्यों का विस्तृत संदर्भ न तो आवश्यक है और न ही आवश्यक है, जो केवल दैनिक वेतनभोगी के रूप में सगाई की तारीखों को शामिल करने के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों को बताकर इस निर्णय पर अनावश्यक रूप से बोझ डालेगा; उनकी समाप्ति की तारीखें; अधिनियम की धारा 10(1)(सी) के प्रावधानों के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा किए गए औद्योगिक संदर्भों की तारीखें और राजपत्र में श्रम न्यायालय पुरस्कारों के प्रकाशन की तारीखें। इन मामलों के निर्णय के लिए चिंता की बात यह है कि इन सभी को बहाली प्रदान करते समय श्रम न्यायालयों द्वारा पारित पुरस्कारों द्वारा सेवा की निरंतरता प्रदान की गई थी, जिसे समाप्ति या छंटनी की तारीखों से प्रभावी माना जाएगा और इसलिए उनका दैनिक वेतन होगा। सेवाओं की गणना प्रारंभिक नियुक्ति/सगाई की तारीखों से की जानी चाहिए। सुविधा के लिए जिस समूह के खिलाफ अनुचित भेदभाव की वकालत की जाती है उसे 'भाग्यशाली समूह' कहा जाता है, जो नियमितीकरण तक सेवा में बने रहे और याचिकाकर्ताओं को 'छूटे हुए समूह' कहा जाता है।



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(11) मामलों के वर्तमान सेट में निर्धारण के लिए जो जटिल प्रश्न उठते हैं, उन्हें निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है: -

(i) क्या श्रम न्यायालय द्वारा दी गई सेवा की निरंतरता के साथ बहाली पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के उल्लंघन में दैनिक वेतन मैनुअल सेवा से हटा दिए गए 'छूटे हुए समूह' को 'भाग्यशाली समूह' के साथ पूर्वव्यापी समानता का अधिकार होगा? न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विभाग द्वारा हरियाणा सरकार के प्रासंगिक नीति निर्देशों के तहत सेवाओं को नियमित किया गया था और इसी तरह स्थित श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा स्वयं नियमित किया गया है, तो क्या वे अपने सेवा कार्यकाल के बराबर नियमितीकरण/स्थायीता/अर्ध-स्थायीता के हकदार होंगे? कनिष्ठों को अनुचित भेदभाव के आधार पर वंचित वर्ग को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का संरक्षण देकर?

(ii) क्या 'उमादेवी' का अनुपात छूटे हुए समूह को कानूनी तौर पर 7 मार्च 1996 की नियमितीकरण की नीतियों के बल पर नियमितीकरण की रियायत/लाभ देने में असमर्थ बनाता है। 7 मार्च, 1996 और 1 जनवरी 2003 को अनुच्छेद 162 में देखा जा सकता है। उमादेवी के बाद 13 अप्रैल 2007 की अधिसूचना के तहत संविधान को वापस ले लिया गया और उसके बाद हरियाणा सरकार के खंड 6 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 209 के तहत

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

तैयार की गई अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 के तहत इसे वापस ले लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएँ) की अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 1970, बशर्ते कि उन्होंने 10 अप्रैल 1996 को 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, 10 अप्रैल 2006 से पीछे की ओर गिना गया है और उमादेवी में निर्णय के भाग्य की व्याख्या और इस प्रकार बताया गया है?

(iii) क्या उमादेवी को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड बनाम कास्ट्राइब राज्य परिवहन कर्मचारी संघलाना में प्रतिष्ठित और स्पष्ट किया गया है; (2009) 8 एससीसी 556 (संक्षेप में "कास्ट्राइब") जो उमादेवी के अनुपात को हटा देता है और इसे एक फैसले के रूप में रखता है जो परिभाषा के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों या 'कर्मचारियों' पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए पांचवीं अनुसूची की प्रविष्टि 10 से प्राप्त सुरक्षात्मक अधिकार हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में अनुचित श्रम प्रथा के माध्यम से रोज़गार को शामिल करना : "कर्मचारी उतने ही बुरे हैं जितने मैं हूँ। कैजुअल अस्थायी हैं और उन्हें स्थायी श्रमिकों की स्थिति और विशेषाधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से वर्षों तक उन्हें इसी तरह जारी रखना है" (ज़ोर दिया गया) और इस प्रकार राज्य और उसके अंगों द्वारा अनुचित और शत्रुतापूर्ण शोषण के कारण दैनिक-मजदूरी पर कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं होने के कारण अनुचित समय बिताया जाता है, तो क्या नियमितीकरण के आदेशों को श्रम न्यायालय के निर्णय के बाहर पारित किया जा सकता है?

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(iv) क्या रिट कोर्ट को अनुचित श्रम अभ्यास के सिद्धांतों का सहारा लेकर कास्टेरिबे में निर्धारित सिद्धांतों को वर्तमान मामले में लागू करना उचित होगा, जो कि अनुचित भेदभाव, दुर्भावना, पूर्वाग्रह और भेजने वाले कानून के लिए जाना जाता है, जो कार्रवाई योग्य है, की एक प्रजाति है। रिट कार्यवाही में और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत पीड़ित व्यक्ति को कम प्रभावकारी और लंबे वैकल्पिक उपचार के लिए आरोपित किए बिना रिट न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले असाधारण क्षेत्राधिकार में निर्धारण करने में सक्षम, श्रम न्यायालय में अनुचित श्रम अभ्यास को साबित करने के लिए साक्ष्य की रिकॉर्डिंग की आवश्यकता को समाप्त करना और इस प्रकार राज्य को 'भाग्यशाली समूह' और 'छूटे हुए समूह' के बीच शत्रुतापूर्ण और द्वेषपूर्ण भेदभाव को दूर करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से 'छूटे हुए समूह' की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया जाए और ऐसा करने में उनके बीच अवसर की असमानता को दूर करने के लिए उन्हें समान स्तर पर रखा जाए।

(v) क्या मनमाने और भेदभावपूर्ण प्रशासनिक आदेशों के खिलाफ रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाला न्यायालय, वर्तमान मामले में नियमितीकरण के अनुरोधों को खारिज करते हुए, प्राथमिक नवीनीकरण के अनुरूप भेदभाव का इलाज करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, जैसा कि ओम कुमार बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समझाया गया है। दिल्ली

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन; 2001 (2) एससीसी 386; (संक्षेप में "ओम कुमार") और ऐसे मामलों में सीधे हस्तक्षेप के सिद्धांत को लागू करने के लिए जहां रिट न्यायालय को राज्य द्वारा किए जाने वाले अनुचित भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो न्यायालय को पीड़ित व्यक्ति द्वारा उसके सामने लाए गए अनुचित भेदभाव को दूर करने के लिए अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाना चाहिए। ओम कुमार द्वारा समझाए गए संविधान के अनुच्छेद 14 के सुप्रसिद्ध भागों पर ध्यान दें; एक मनमानी का और एक अनुचित भेदभाव का, दोनों को अलग-अलग मापदंडों पर परीक्षण किया गया, एक आनुपातिकता पर और एक मनमानी प्रशासनिक कार्रवाई की माध्यमिक समीक्षा के परीक्षण को लागू करके मनमानी के बुधवारबरी नियमों पर, जबकि दूसरा अनुचित और कार्रवाई योग्य भेदभाव के मामले में प्राथमिक समीक्षा के सिद्धांतों पर और आओ। अन्यायपूर्ण व्यवहार वाले व्यक्ति को बचाने के लिए और संतुलन बनाए रखने के लिए श्रम न्यायालय द्वारा दी गई सेवा की निरंतरता के कारण 'भाग्यशाली' और 'छूट गए समूह' को समान स्तर पर समान समरूप समूह के भीतर सकारात्मक कार्रवाई द्वारा समान सुरक्षा बहाल करना ?

(vi) क्या जिनके खिलाफ अनुचित भेदभाव की वकालत की जाती है और अभ्यास किया जाता है, यानी भाग्यशाली समूह जो दैनिक वेतन पर सेवा करना जारी रखते हैं, उन्हें नियमित कर्मचारी के रूप में माना जाना चाहिए, जिस क्षण उनके पक्ष में नियमितीकरण के आदेश

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

पारित किए गए थे, उनके अतीत के अवैध या अनियमित को मिटा दिया गया था। दिहाड़ी मजदूरों के रूप में सेवा को नए सिरे से शुरू करने योग्य माना जाता है, तो आगे चलकर ऐसी घटना 'छूट गए समूह' पर पूर्वव्यापी रूप से समान व्यवहार की मांग करने का अधिकार सक्रिय कर देगी, यह मानते हुए कि उनकी कभी छंटनी नहीं हुई थी और अब निरंतरता प्रदान करने वाले श्रम न्यायालय के फैसले के आधार पर जब 'भाग्यशाली समूह' को न्यायालय के आदेश से नहीं बल्कि सरकार के विभाग द्वारा अपनी इच्छा से नियमित किया गया था, तो उन्हें नीति परिपत्रों द्वारा निर्धारित कटऑफ तिथि पर काम करने वाला मानते हुए निरंतर सेवा की समझी गई कानूनी कल्पना का लाभ दिया जाएगा ?

(vii) क्या दैनिक वेतनभोगी श्रमिक जब कोई सार्वजनिक पद धारण नहीं कर रहे हों तो उन्हें इस दलील पर घोषणा के दावे से वंचित किया जा सकता है कि उनकी नियुक्तियाँ/नियुक्तियाँ 'अवैध' और 'अनियमित' हैं और नियुक्तियाँ करने की संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 309 या सरकार या इस संबंध में बनाए गए वैधानिक निकायों द्वारा बनाए गए अन्य भर्ती नियमों और उपकानूनों के प्रावधान के तहत कोई वैधानिक भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं और इस तरह की नियुक्ति नियमों द्वारा शासित सार्वजनिक पदों पर भर्ती नियम का अपवाद है और इसलिए अलग-अलग मानकों से निपटा जाना चाहिए, एक नियमों की सख्त जांच पर और दूसरा नियमों में ढील देने वाले मानकों पर?

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(viii) क्या सेवाओं के नियमितीकरण के औपचारिक आदेश केवल ग्रुप डी कैडर पदों की उपलब्धता या पदों के सृजन पर जारी किए जा सकते हैं और इसके अभाव में याचिकाकर्ताओं के 'छूटे हुए समूह' के अधिकार को किसी मामले में पराजित या स्थगित किया जा सकता है जब संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गैर-भेदभाव के मौलिक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है, तो पूर्वव्यापी अनुचित भेदभाव की गारंटी दी गई है और इसके अलावा क्या अनुचित भेदभाव को दूर करने के लिए पूर्वव्यापी समता का निर्देश देकर निरंतर मौलिक अधिकार से वंचित करने के लिए अधिक उपयुक्त पाठ्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। जब राज्य संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत कार्य करता है तो असमानता को ठीक करने का एकमात्र संभावित तरीका एक अलौकिक व्यवस्था है?

**उमादेवी के मामले में क्या कहा गया?**

(12) उमादेवी में संविधान पीठ ने आधिकारिक तौर पर उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को एक आदेश जारी किया है कि वे नियोक्ता राज्यों को नियमित सेवा में तदर्थ, दैनिक वेतन और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और समाहित करने के लिए परमादेश जारी करने से बचें, जिन्होंने बिना रोजगार प्राप्त किया है। पदों पर भर्ती के लिए लागू नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना क्योंकि यह उन लोगों के लिए भारत

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अवसर की समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा जो नौकरी बाजार में उपलब्ध थे और आवेदन के अवसर से वंचित थे और ऐसे पदों पर चुनाव लड़ें। यह माना गया कि अनुच्छेद 16 द्वारा संरक्षित सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने की संविधान की योजना के विपरीत की गई ऐसी नियुक्तियों को भेदभाव के आधार पर भी नियमित नहीं किया जा सकता है और न ही सुप्रीम कोर्ट और न ही हाई कोर्ट ऐसा कोई निर्देश जारी करेगा। स्थायी जैसे भेदभाव के आधार पर सार्वजनिक कार्यालय के रैंक हड़पने वाले हैं जो सरकारी सेवा या सार्वजनिक रोजगार में नियुक्तियाँ करने की संवैधानिक योजना के विपरीत है। "संविधान पीठ धारवाड़ जिला लोक निर्माण विभाग बनाम कर्नाटक राज्य (2) में लिए गए अपने पहले के दृष्टिकोण से सहमत नहीं थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

(13) संविधान पीठ ने हरियाणा राज्य बनाम पियारा सिंह (3) के पैरा 50 में जारी अपने पहले के निर्देशों को भी फैसले के पैरा 45 में पहुंचे निष्कर्षों के साथ असंगत पाया, जिन्हें रोजगार की संवैधानिक योजना के विपरीत माना गया था। प्यारा सिंह को खराब कानून घोषित किया गया। न्यायालय ने ऐसे रोजगार के खिलाफ भर्ती के नियम

(2) 1990 (1) एससीआर 544

(3) 1992 (4) एससीसी 118

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

बनाए और निर्देश दिया कि ऐसे तदर्थ, अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हीं पदों को नियमित आधार पर भरने के समय उनके अनुभव के आधार पर वरीयता दी जा सकती है। उनके लिए खुला चयन और आयु सीमा की शर्त हटा दी जानी चाहिए। राहत देने के लिए तैयार किए गए फॉर्मूले में दस साल की अनियमित तदर्थ या दैनिक वेतन सेवा को पर्याप्त माना गया। लेकिन यह एक बार के उपाय के रूप में आदेश दिया गया था। यहां यह जोड़ा जा सकता है कि परिपक्व होने के अधिकारों के लिए पुरानी योजनाओं में ऊष्मायन अवधि तीन साल थी, सरकार ने अपनी नीतियों में इसकी कल्पना की थी।

(14) हालाँकि, उमादेवी मामले में फैसले की प्रस्तावना में पैरा 2 में न्यायालय ने कहा कि एक संप्रभु सरकार, देश में आर्थिक स्थिति और किए जाने वाले काम को ध्यान में रखते हुए, अस्थायी नियुक्तियाँ करने या रोजगार देने या श्रमिकों को नियुक्त करने से नहीं रोकती है। प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दैनिक वेतन पर।

(15) न्यायालय ने नव अधिनियमित, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर ध्यान दिया, जिसका उद्देश्य एईटी के तहत तय मजदूरी का भुगतान करने पर एक वर्ष में



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

100 दिनों के लिए परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देना है। 'न्यायालय फैसले के केंद्रीय विषय से पहले से ही चिंतित था कि जहां सार्वजनिक पद और नियमित रिक्तियां उपलब्ध हैं, उन्हें भर्ती के नियमों के अनुसार भरा जाना चाहिए, न कि उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। रिक्तियों को "अव्यवस्थित तरीके से या संरक्षण या अन्य विचारों के आधार पर नहीं भरा जा सकता। नियमित नियुक्ति का नियम होना चाहिए"। देश में एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसका परिणाम उमादेवी था जहां संघ और राज्यों ने राज्य के उपकरणों के अलावा विशेष रूप से कर्तव्य और संवैधानिक सीमाओं के संदर्भ के बिना कैडर के निचले स्तर पर बड़े पैमाने पर अनियमित नियुक्तियों का सहारा लिया था। लोक सेवा आयोगों के माध्यम से या अन्यथा निर्धारित नियमों के अनुसार एक उचित नियुक्ति प्रक्रिया का पालन और सुनिश्चित करके नियुक्ति करने की शक्ति का प्रयोग किया गया है और इन अनियमित नियुक्तियों या अनुबंध पर या दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त लोगों को इस प्रकार वर्ष दर वर्ष जारी रखने की अनुमति दी गई है। जो लोग संबंधित पद के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हैं उन्हें बाहर रखना और उन्हें प्रतिस्पर्धा करने के अवसर से वंचित करना। न्यायालय पिछले दरवाजे से प्रवेश की दुविधा और नियमित भर्ती को रोकने वाली सेवा की जांच करने में व्यस्त था।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(16) संविधान पीठ इस बात से अवगत थी कि न्यायालयों ने हमेशा कानूनी पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा है और कभी-कभी रोजगार की नियमित प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है और कुछ मामलों में, यहां तक कि निर्देश भी दिया है कि ये अवैध, अनियमित और अनुचित प्रवेशकर्ता हैं। सेवा में लीन हो जाओ. उच्चतम न्यायालय ने रोजगार के इस वर्ग को "आधुनिक रोजगार" कहा, जो किसी संवैधानिक संरक्षण का हकदार नहीं था। न्यायालय ने **ए उमारानी बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां और अन्य (4)** में अपने पहले के फैसले पर गौर किया और अपने विचार की फिर से पुष्टि की कि स्टेट ऐसी नियुक्तियों को नियमित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है, नियमितीकरण नहीं है और न ही हो सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत किसी भी राज्य प्राधिकारी द्वारा या वैधानिक अधिनियम द्वारा शासित किसी भी प्राधिकारी द्वारा या तदर्थ नियुक्तियों के तहत वहां बनाए गए नियमों द्वारा भर्ती का वैध तरीका कोई नियमितीकरण नहीं अर्जित कर सकता है। तदर्थवाद के पिछले दरवाजे से की गई किसी भी अवधि की सेवा का मतलब यह नहीं होगा कि उन्होंने नियमितीकरण का अधिकार प्राप्त कर लिया है।

(4) 2004 (7) एससीसी 112.

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

न्यायालय ने फेयरवेल लॉर्ड जस्टिसिन लाथन बनाम रिचर्ड जॉनसन एंड नेफ्यू लिमिटेड (5)

की टिप्पणियों को उद्धृत किया:—

"हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि नवजात वादी के प्रति हमारी सहानुभूति हमारे फैसले को प्रभावित न करे। भावना कानूनी सिद्धांतों की खोज में एक मार्गदर्शक के रूप में लेने की एक खतरनाक इच्छा है।

पैरा में उमादेवी के 42 और 44 पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया :-

42. यह तर्क कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित जीवन के अधिकार में रोजगार का अधिकार भी शामिल होगा, इस समय स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कानून गतिशील है और हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है। हो सकता है कि भविष्य में किसी समय रोजगार के अधिकार को भी जीवन के अधिकार की अवधारणा के अंतर्गत लाया जा सके या मौलिक अधिकार के रूप में भी शामिल किया जा सके। नया कानून शायद एक शुरुआत है। जैसा कि अब स्थिति यह है कि हमारे सामने कर्मचारियों के कहने पर इस तरह की याचिका को स्वीकार करने से बड़ी संख्या में अन्य उम्मीदवारों को पद या रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

करने के अवसर से वंचित होना पड़ेगा। यदि रोज़गार का उनका अधिकार जीवन के अधिकार से अलग है, तो उन लोगों को प्राथमिकता देने से वंचित कर दिया जाएगा जो आकस्मिक रूप से आए हैं या जो पिछले दरवाजे से आए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (ए) के तहत राज्य पर डाला गया दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो। यह उस नीति के साथ अधिक सुसंगत होगा यदि अदालतें यह मानती हैं कि सरकारी सेवा में या उसके सहायकों की सेवा में किसी पद पर नियुक्ति केवल प्रासंगिक संदर्भ में प्रासंगिक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से उचित चयन के माध्यम से हो सकती है। संविधान के प्रावधान. न्याय को वैयक्तिकृत करने के नाम पर, संवैधानिक योजना और अदालत के सामने आने वाले कुछ लोगों की तुलना में असंख्य लोगों के अधिकारों के प्रति अपनी आँखें बंद करना भी संभव नहीं है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को संविधान के भाग III के तहत नागरिकों को उपलब्ध अधिकारों और नागरिकों के किसी विशेष समूह के लिए नहीं बल्कि सभी के प्रति राज्य के दायित्व के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। इसलिए हम संविधान के अनुच्छेद 21 पर आधारित तर्क को खारिज करते हैं।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

44. एक पहलू को स्पष्ट करने की जरूरत है. ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अनियमित नियुक्तियां (अवैध नियुक्तियां नहीं) जैसा कि एस.वी.नारायणप्पा (पूर्व) आर.एन. में बताया गया है। नंजुंदप्पा (पूर्व) और बी.एन.नागराजन (पूर्व) और उपर्युक्त पैराग्राफ 15 में उल्लिखित रिक्त पदों पर विधिवत योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया होगा और कर्मचारी दस साल या उससे अधिक समय तक काम करते रहे होंगे, लेकिन अदालतों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना या न्यायाधिकरणों का ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित मामलों में तय किए गए सिद्धांतों और इस निर्णय के आलोक में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। उस संदर्भ में भारत संघ, राज्य सरकारों और उनकी संस्थाओं को ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त लोगों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक बार के उपाय के रूप में कदम उठाना चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, लेकिन अदालतों के आदेशों की आड़ में नहीं। न्यायाधिकरणों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्तियां की जाएं, जिन मामलों में अस्थायी कर्मचारियों या दैनिक वेतनभोगियों को नियोजित किया जा रहा है, उन्हें भरने की आवश्यकता है। इस तिथि से छह महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई नियमितीकरण पहले ही हो चुका है, लेकिन न्यायाधीन नहीं है, तो उसे इस फैसले के आधार पर फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संवैधानिक

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

आवश्यकता को और अधिक दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए और संवैधानिक योजना के अनुसार विधिवत नियुक्त नहीं किए गए लोगों को नियमित या स्थायी नहीं किया जाना चाहिए।

### **कास्ट्राइब मामले में उमादेवी के बारे में क्या कहा गया**

(17) सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में कास्ट्राइब में एक बदलाव किया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मामलों का वर्तमान समूह दैनिक वेतनभोगियों के अधिकारों से संबंधित है जो अदालतों द्वारा विकसित क्लासिक सेवा कानून न्यायशास्त्र द्वारा संरक्षित या बोझ नहीं हैं, लेकिन दोनों व्यापक सेवा कानून के सिद्धांतों द्वारा लेकिन एक विशेष द्वारा संरक्षित औद्योगिक कानून सिद्धांतों के विपरीत हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और इसके समान राज्य औद्योगिक कानूनों में अधिनियमन पाया गया।

(18) परिभाषा के अनुसार कर्मचारी सार्वजनिक पद धारण कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, उनका रोजगार सार्वजनिक रोजगार हो भी सकता है और नहीं भी, उनकी सेवा शर्तें नियमों द्वारा शासित हो भी सकती हैं और नहीं भी, वे पिछले दरवाजे से प्रवेश कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, वे प्रविष्टियाँ हो भी सकते हैं और नहीं भी। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में संरक्षण, सिफ़ारिश आदि के माध्यम से, लेकिन राज्य सरकार को अपनी अवशिष्ट शक्ति में

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

उन्हें कार्यालयों में या राज्य के विभागों द्वारा दूर-दराज के स्थानों में संचालित क्षेत्र में बासी या केंद्रीय परियोजनाओं पर काम करने के लिए नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। वन और सिंचाई विभाग में तब उनका प्रवेश विशेष क्षेत्र की परिस्थितियों में प्रति एससी घृणित नहीं था। दूरदराज के इलाकों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं कर सकती है और अक्सर नहीं भी कर सकती है। दुर्गम क्षेत्रों में साइट पर प्राप्त श्रम स्थानीय श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा का हकदार हो सकता है क्योंकि वे आसानी से मिल जाते हैं और राज्य सरकार की परियोजनाओं या योजनाओं को पूरा करने के लिए दूरदराज के गांवों में काम करने के इच्छुक होते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार की पेशकश करके स्थानीय व्यवस्था की जाती है, श्रम मुश्किल होता है। संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करने और इसके अव्यवहारिक रूप से आयात करने के लिए इस तरह से करदाताओं के पैसे का अपव्यय हो सकता है। यहां अखबारों में दिए गए महंगे विज्ञापन बड़ी संख्या में स्थानीय मजदूरों के लिए अल्प मजदूरी पर खर्च किए गए पैसे का समर्थन और प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो प्रयास मोमबत्ती के लायक नहीं हो सकता है। यदि बहुत कम नहीं तो बहुत कम लोग दूर-दूर तक दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए अपना घर-बार छोड़ देंगे। हालांकि कम मजदूरी दी जाती है, जो शायद ही विस्थापन के खर्चों की भरपाई के लिए पर्याप्त हो।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

**दमयंती बनाम पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय पानीपत और एक अन्य (6)** मामले में एकल में बैठते समय मुझे लारियाना वन विभाग में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के साथ सहजता से निपटने का अवसर मिला, क्योंकि अधिकांश याचिकाकर्ता इस सहजता में हैं। बेंच, मैंने फिर सोचा:-

“एक दैनिक मजदूर या मौसमी श्रमिक भी औद्योगिक अधिकारों वाला एक श्रमिक है। मुझे कोई नियम नहीं दिखाया गया कि मौसमी श्रमिकों या दैनिक वेतनभोगियों की भर्ती कैसे की जाती है। यह स्वाभाविक है कि दूर-दराज के स्थानों में जहां वन विभाग के पास स्थानीय स्तर पर उपलब्ध श्रमिकों को रोजगार देने के लिए काम चल रहे हैं। इसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसे रोजगार के अवसर में संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर खरा उतरने के लिए सार्वजनिक विज्ञापन होने ही चाहिए। वास्तव में बाहरी लोगों को भीतरी इलाकों में साधारण अकुशल या अर्धकुशल दैनिक वेतन कार्य के लिए लाना स्थानीय श्रम अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि अनुच्छेद 14 और 16 को राज्य के लिए विवाद के बिंदु से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दुर्भाग्य से ऐसे मामलों में नियमित

(6) 2012 (4) एस.सी. टी. 506.



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

रूप से होता है कि नियुक्ति नियम से परे होती है। मैं पूछता हूँ कि 15 वर्षों तक कम वेतन पाने वाले कर्मचारी का शोषण करना और फिर दैनिक वेतन पर मौसमी श्रमिकों की नियुक्ति के नियम का हवाला देना और यह तर्क देना कि वन विभाग कोई उद्योग नहीं है, किस नियम का उल्लंघन है। यह वन विभाग के लिए बहुत ही शर्म की बात है।

(19) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के विशेष कानून द्वारा संरक्षित संवैधानिक सिद्धांतों और औद्योगिक कानून के सिद्धांतों दोनों पर श्रम और औद्योगिक अधिकारों की जांच की जानी चाहिए और ऊपर (iv) में पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर पहले उदाहरण में दिया जाना चाहिए कि क्या उमादेवी प्रतिष्ठित हैं और कास्टेरिबे में न्यायमूर्ति आर.एम. लोढा द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले में समझाया गया। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने महाराष्ट्र के राज्य कानून को महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम अभ्यास रोकथाम अधिनियम 1971 (एमआरटीयू और पीयूएलपी अधिनियम) के रूप में उद्धृत किया। न्यायालय ने धारा 21(1) और उसके प्रावधान पर विचार किया; अनुसूची IV आइटम 2, 5, 6 और 9 और विशेष रूप से आइटम 6 के साथ, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की 5वीं अनुसूची की प्रविष्टि 10 के प्रावधानों के साथ सममूल्य पर है, श्रमिकों को बुरे के रूप में रखने के लिए अनुचित श्रम अभ्यास का एक पहलू है। कैजुअल या

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

अस्थायी और उन्हें स्थायी श्रमिकों की स्थिति और विशेषाधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से "वर्षों तक" ऐसे ही जारी रखना। उमादेवी में संविधान पीठ को कास्टेरिबे में पैरा 35 और 36 में इस प्रकार समझाया गया था :

(35) उमादेवी (3) 1 इस प्रस्ताव के लिए एक आधिकारिक घोषणा है कि सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को अस्थायी, संविदात्मक, आकस्मिक, दैनिक के अवशोषण, नियमितीकरण या स्थायी निरंतरता पर निर्देश जारी नहीं करना चाहिए। वेतनभोगी या तदर्थ कर्मचारी, जब तक कि भर्ती स्वयं संवैधानिक योजना के तहत नियमित रूप से नहीं की जाती।

(36) उमादेवी (3) 1 उन श्रमिकों के स्थायित्व का आदेश देने के लिए एमआरटीयू और पीयूएलपी अधिनियम की धारा 32 के साथ पढ़ी गई धारा 30 के तहत औद्योगिक और श्रम न्यायालयों को उनकी वैधानिक शक्ति से वंचित नहीं करता है, जो कि निष्पक्ष श्रम अभ्यास के शिकार हैं। अनुसूची IV के आइटम 6 के तहत नियोक्ता के जहां वे पद मौजूद हैं जिन पर वे काम कर रहे हैं। अनुसूची IV के आइटम 6 के तहत नियोक्ता की ओर से अनुचित श्रम व्यवहार स्थापित होने के बाद उमादेवी (3) को एमआरटीयू और पीयूएलपी अधिनियम की धारा 30 के

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

तहत उचित आदेश पारित करने में औद्योगिक और श्रम न्यायालयों की शक्तियों को खत्म करने के लिए नहीं ठहराया जा सकता है। ” (ज़ोर दिया गया)

(20) न्यायालय ने कहा कि इस प्रस्ताव से कभी कोई झगड़ा नहीं हो सकता कि न्यायालय ऐसे पदों के निर्माण का निर्देश नहीं दे सकते जिनके सिद्धांत महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय बनाम नासिक जिला शेठ कामगार यूनियन (7) में अंतर्निहित हैं महाराष्ट्र राज्य बनाम आर.एस.भोंडे (8) इंडियंस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन (9) अरावली गोल्ड क्लब बनाम चान डे आर हस (10) । पैरा 41 में, कास्ट्राइब में न्यायालय ने कहा :

(7) 2001 (3) एससीआर 1089

(8) (2005) 6 एससीसी 751

(9) (2007) 1 एससीसी 408

(10) (2008) 1 एससीसी 683

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

“41. इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदों का सृजन न्यायिक कार्यों के क्षेत्र में नहीं है जो स्पष्ट रूप से कार्यपालिका से संबंधित है। यह भी सच है कि जहां ऐसे कोई पद मौजूद नहीं हैं, वहां न्यायालय द्वारा स्थायित्व की स्थिति नहीं दी जा सकती है और पदों के निर्माण के संबंध में कार्यकारी कार्यों और शक्तियों को न्यायालयों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।”

(21) सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कास्ट्राइब में निगम द्वारा उठाया गया तर्क यह था कि जहां औद्योगिक न्यायालय ने पाया है कि निगम ने शिकायतकर्ताओं को पीस-रेट के आधार पर कैजुअल के रूप में नियोजित करने में अनुचित श्रम व्यवहार में लिप्त पाया है, तो एकमात्र निर्देश जो हो सकता है निगम को इस तरह के अनुचित श्रम अभ्यास में शामिल होने से रोकने और रोकने के लिए दिया गया था और उन कर्मचारियों को स्थायीता\* देने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था क्योंकि इसमें औद्योगिक/श्रम न्यायालय को दी गई विशिष्ट शक्ति पाई गई थी। दोषी नियोक्ताओं के खिलाफ सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिनियम बनाया जा सकता है और ऐसे अनुचित श्रम व्यवहार से प्रभावित कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने सार्वजनिक परिवहन चलाने वाली बसों के लिए निगम द्वारा सफाईकर्मियों के रूप में नियोजित शिकायतकर्ताओं को दर्जा और स्थायित्व देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश में कुछ

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

भी गलत नहीं पाया। उमादेवी में जारी किए गए निर्देशों को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तक ही सीमित माना गया था, जिसमें दैनिक वेतन या एडएओसी कर्मचारियों के अवशोषण/नियमितीकरण के संबंध में निर्देश जारी नहीं किए जाने थे, जब तक कि भर्ती स्वयं शर्तों के अनुसार नियमित न हो जाए। संवैधानिक योजना का. हालाँकि, नियोक्ता के अनुचित श्रम व्यवहार के शिकार लोग स्थायित्व की स्वतंत्रता के पात्र हैं जहाँ तथ्यों और परिस्थितियों की कास्टेरिबे के कैनवास में मांग होती है।

श्रम एवं औद्योगिक कानून में अनुचित श्रम व्यवहार और अनुचित भेदभाव क्या है?

(22) हालाँकि कास्ट्राइब ने महाराष्ट्र राज्य द्वारा अधिनियमित एमआरटीयू और पीयूएलपी अधिनियम से निपटा है, लेकिन अनुचित श्रम व्यवहार के प्रावधान औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की 5वीं अनुसूची की प्रविष्टि 10 के समान हैं। प्रविष्टि 10 घृणित भेदभाव के खिलाफ एक वैधानिक सुरक्षा है और शोषण बशर्ते कि भेदभाव 'वर्षों तक' जारी रहे। इसका मतलब यह होगा कि रोजगार की छोटी अवधि अधिनियम की प्रविष्टि 10 का उल्लंघन नहीं है और रोजगार की अवधि निष्पक्ष श्रम अभ्यास के मुद्दों की जांच के लिए प्रासंगिक विचार बन जाती है। 10 साल या उससे अधिक की सेवा के लिए उमादेवी में विकसित नियम को

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

अनियमित रूप से नियुक्त लेकिन अवैध रूप से नियुक्त नहीं किए गए कर्मचारियों की सेवाओं को एक बार के उपाय के रूप में नियमित करने के कदम उठाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों और उनकी संस्थाओं को बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पर्याप्त मंजूरी प्राप्त है। स्वीकृत पदों की उपलब्धता के अधीन, जहां ऐसा रोजगार प्रकृति में मुकदमेबाजी नहीं है या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के आदेशों की आड़ में है। उमादेवी मामले में संविधान पीठ ने नियमितीकरण को तो संरक्षण दे दिया लेकिन जो नियुक्तियां विचाराधीन नहीं थीं उन्हें दोबारा नहीं खोला जा सका। उमादेवी के अनुसार, पैरा 44 से पैरा 46 में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अनियमित नियुक्तियों और अवैध नियुक्तियों के बीच अंतर को ध्यान में रखना होगा और इस प्रकार नियमितीकरण और स्थायीकरण देने के बीच भी अंतर को ध्यान में रखना होगा।

(23) मामलों के इस समूह में दावा सेवा की निरंतरता के साथ बहाली प्रदान करने वाले श्रम न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न होता है। यदि याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा पारित गैरकानूनी आदेशों द्वारा सेवा से बाहर रखा गया था, तो अनुपस्थिति की अवधि को 5 वीं अनुसूची की प्रविष्टि 10 के तहत सुरक्षा के अधिकार के साथ सेवा की कुल अवधि में जोड़ने के लिए निरंतर सेवा के रूप में माना जाना होगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम में, बशर्ते कि वे अधिनियम की धारा 2 (एस) के अर्थ में 'कर्मचारी' के रूप में अर्हता प्राप्त करें, जो साक्ष्य के माध्यम से बिना किसी विशेष सबूत के प्रतीत होता है। इसमें

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को औद्योगिक निर्णायक द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में सेवा में बहाल किया गया है और वे अनुचित भेदभाव के दोष को दूर करने के लिए "भाग्यशाली समूह" के बराबर रखे जाने के पात्र हो सकते हैं, जहां "भाग्यशाली समूह" सुरक्षित है। नियमितीकरण या स्थायीकरण के आदेश प्रशासक द्वारा, न कि न्यायालय द्वारा। इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेशों से याचिकाकर्ताओं को मुकदमेबाजी प्रकृति की बदनामी का सामना नहीं करना चाहिए और न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले पीड़ित व्यक्तियों के दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। खुद। इसलिए इस बैच के वे मामले जिनमें व्यक्ति अंतरिम संरक्षण द्वारा या अन्यथा सेवा में बने रहे हैं, उन्हें उन याचिकाकर्ताओं के साथ एक ही समूह में रखा जा सकता है, जिन्होंने नियमितीकरण के लिए अपने अभ्यावेदन को अदालत की घोषणा से पहले या बाद में खारिज कर दिए जाने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

(24) प्रश्न उठता है कि क्या अनुचित श्रम प्रथा को केवल औद्योगिक न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित और स्थापित किया जा सकता है या परिणाम संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हस्तक्षेप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या जिसे हम रिट द्वारा प्रयोग किए जाने वाले असाधारण क्षेत्राधिकार में कह सकते हैं। न्यायालय ने पीड़ित

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

व्यक्तियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की मशीनरी के तहत उपलब्ध एक कम प्रभावकारी और लंबे समय तक चलने वाले वैकल्पिक उपाय के लिए हलफनामे पर रोक दिया है, जब ऐसे व्यक्तियों ने औद्योगिक न्यायनिर्णयन के माध्यम से बहाली हासिल की है, जहां निष्कर्ष आया है कि समाप्ति या छंटनी गैरकानूनी थी।

(25) मेरे विचार से औद्योगिक विवाद अधिनियम की 5वीं अनुसूची की प्रविष्टि 10 में "कर्मचारियों को बदमाश, कैजुअल या अस्थायी" के रूप में रखने और उन्हें इस उद्देश्य के साथ वर्षों तक जारी रखने के क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य को स्थापित करने के लिए साक्ष्य प्रमाण द्वारा किसी विशेष निर्णय की आवश्यकता नहीं है। उन्हें "पैसा कामगार" की स्थिति और विशेषाधिकारों से वंचित करना, जहां दैनिक वेतन सेवा के अंदर और बाहर बिताई गई सेवा की अवधि को श्रम न्यायालय के आदेशों के माध्यम से प्राप्त कानूनी कल्पना के साथ जोड़ दिया जाता है, जो अंतिम रूप ले चुका है क्योंकि दावों को निर्धारित करने के लिए किसी विशेष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। समूह को "भाग्यशाली समूह" के बराबर लाने के लिए छोड़ दिया गया। इस बिंदु पर अनुचित भेदभाव के प्रश्न में प्रवेश करना उचित हो सकता है और इसलिए ओम कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित कानून को समझना और यह वर्तमान मामलों के तथ्यों पर कैसे लागू हो सकता है।



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

### आर्टिकल 14 के बारे में ओम कुमार क्या बताते हैं

(26) इस मुद्दे को ऊपर प्रश्न (vi) में चित्रित किया गया है और उत्तर की तलाश में किसी और विस्तार की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि न्यायमूर्ति एम जगन्नाथ राव के न्यायालय के लिए बोलने और शल्य चिकित्सा द्वारा दो हिस्सों को अलग करने के फैसले के निम्नलिखित उद्धरणों को देखें। अनुच्छेद 14 मनमानी और भेदभाव का। हालाँकि यह निर्णय अनुशासनात्मक कार्यवाही और प्रतिस्पर्धी अपराधी दलों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के लिए उच्च स्तर की सज़ा देने के संदर्भ में दिया गया था, लेकिन निर्धारित सामान्य सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं जब तक कि प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। पैरा में. 51, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय परिदृश्य में 1950 से मौलिक स्वतंत्रता के चार्टर का अस्तित्व हमारे कानून को अलग करता है और विधायी और प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता का आकलन करने के मामले में हमारे न्यायालयों को इंग्लैंड की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में रखा है। संबद्ध है। जब मनमानी का सिद्धांत उठाया जाता है, तो आनुपातिकता और अनुचितता का परीक्षण वेडनसबरी नियम पर किया जाता है जो भारत में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। प्रशासनिक निर्णयों को आनुपातिकता और कथित मनमानी के खिलाफ अनुचित भेदभाव दोनों पर परीक्षण किया जाना चाहिए जहां न्यायालय द्वितीयक समीक्षा का परीक्षण लागू करता है, प्रशासक आनुपातिकता का चयन

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

करने में प्राथमिक भूमिका निभाता है। हालाँकि जब अनुच्छेद 14 के तहत आधारित वर्गीकरण को प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध लाया जाता है तो भेदभावपूर्ण वर्गीकरण और मनमानी के सिद्धांत उत्पन्न होते हैं। पैरा 56 से 59 में समीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर पर कानून पर चर्चा की गई थी और इसे पढ़ना और समीक्षा के लिए लाई गई सहजता के तथ्यों के आधार पर न्यायालय किस प्रकार भूमिकाओं को एक से दूसरे में बदलता है, इसकी व्यवस्था को ध्यान में रखना लाभदायक है।

“56. प्रारंभ में हमारे न्यायालय कानून के साथ-साथ प्रशासनिक कार्रवाई का परीक्षण कर रहे थे, जिसे अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण होने के रूप में चुनौती दी गई थी, यह जांच कर रहे थे कि क्या वर्गीकरण इस अर्थ में भेदभावपूर्ण था कि क्या भेदभाव के मानदंड समझदार थे और क्या वर्गीकरण और वस्तु के बीच कोई तर्कसंगत संबंध था। वर्गीकरण द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस अदालत द्वारा तय की गई आसानताओं का हवाला देना आवश्यक नहीं है जहां प्रशासनिक कार्रवाई को भेदभावपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया गया था।

(ii) अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी परीक्षण :

57. लेकिन ई.पी. में. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य [1974] 4 एससीसी 31 न्यायमूर्ति भगवती ने अनुच्छेद 14 के प्रयोजनों के लिए एक और परीक्षण रखा। यह कहा गया था कि

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

यदि प्रशासनिक कार्रवाई 'मनमानी' थी तो इसे अनुच्छेद 14 के तहत रद्द किया जा सकता है। इस सिद्धांत का अब समान रूप से पालन किया जाता है सभी न्यायालयों में वर्गीकरण के आधार पर अधिक कठोरता से। प्रशासक द्वारा की गई मनमानी कार्रवाई को ऐसी कार्रवाई के रूप में वर्णित किया गया है जो तर्कहीन है और ठोस कारण पर आधारित नहीं है। इसे ऐसे भी वर्णित किया गया है जो अनुचित है।

(बी) यदि अनुच्छेद 14 के तहत प्रशासनिक कार्रवाई को भेदभावपूर्ण मानकर रद्द किया जाना है, तो आनुपातिकता लागू होती है और यह प्राथमिक समीक्षा है। यदि इसे मनमाना माना जाता है और यह द्वितीयक समीक्षा है, हम अब मामले में सीधे तौर पर उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण पहलू पर पहुंच गए हैं। गणयुथम में इस पहलू को भविष्य में चर्चा के लिए खुला रखा गया था, लेकिन जैसे ही यहां 'मनमानेपन' (और भेदभावपूर्ण वर्गीकरण का नहीं) का सवाल उठता है, हम कानूनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं।

(59) न्यायालय अनुच्छेद 14 के तहत प्राथमिक समीक्षा प्राधिकारी के रूप में आनुपातिकता परीक्षण कब लागू करता है और न्यायालय द्वितीय समीक्षा प्राधिकारी के रूप में डब्ल्यूसीडीएनसीएसबरी नियम कब लागू करता है? बुनियादी सिद्धांतों की पिछली समीक्षा से उत्तर सरल हो जाता है। वास्तव में हमारे पास इस संबंध में आगे का मार्गदर्शन है।"

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(27) न्यायालय ने पैरा में कानूनी स्थिति का सारांश दिया। 64 से 69 जो पढ़ता है: -

“उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारत में जहां प्रशासनिक कार्रवाई को अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती दी जाती है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है, समानों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है या असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, सवाल यह है कि प्राथमिक समीक्षा करने वाली अदालतों के रूप में संवैधानिक न्यायालयों को भेदभाव के स्तर की शुद्धता पर विचार करना चाहिए। लागू किया गया है और क्या यह अत्यधिक है और क्या इसका प्रशासक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध है। यहां न्यायालय प्रशासक की संतुलनकारी कार्रवाई के गुणों से संबंधित है और संक्षेप में 'आनुपातिकता' लागू कर रहा है और एक प्राथमिक समीक्षा प्राधिकारी है। लेकिन जहां रोयप्पा के आधार पर अनुच्छेद 14 के तहत एक प्रशासनिक कार्रवाई को 'मनमाना' के रूप में चुनौती दी जाती है (जैसे कि उन आसानियों में जहां अनुशासनात्मक आसानी में दंड को चुनौती दी जाती है) सवाल यह होगा कि क्या प्रशासनिक आदेश 'तर्कसंगत' है या 'उचित' है और परीक्षण उसके बाद बुधवारबरी टेस्ट है। तब न्यायालय केवल एक माध्यमिक भूमिका तक ही सीमित रहेंगे और उन्हें केवल यह देखना होगा कि प्रशासक ने अपनी प्राथमिक भूमिका में अच्छा प्रदर्शन किया है या नहीं, क्या उसने अवैध रूप से कार्य किया है या प्रासंगिक कारकों को विचार से हटा दिया है या अप्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा है या क्या उसका दृष्टिकोण वह है जिसे कोई

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

भी उचित व्यक्ति नहीं ले सकता था। यदि उसकी कार्रवाई इन नियमों को पूरा नहीं करती है, तो इसे मनमाना माना जाएगा। जीआईटी महाजन बनाम जलगांव नगर परिषद [1991] 3 एससीसी 91, 111 पर। न्यायमूर्ति वेंकटचलैया (जैसा कि वह तब थे) ने बताया कि प्रशासनिक कानून के संदर्भ में अनुच्छेद 14 के तहत प्रशासक की 'तर्कसंगतता' को इस दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए बुधवारबरी नियम. डेटा के सेल्यूलर बनाम भारत संघ में [1994] 6 एससीसी 651 (पीपी. 679-680 पर); इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र बनाम भारत संघ [1985] 1 एससीसी 641 और 691) सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ और अन्य 1989 [4 एससीसी 187, 241 पर और यू.पी. वित्तीय निगम बनाम जीईएम कैप (इंडिया) प्राइवेट। लिमिटेड, 11993] 2 एससीसी 299 एट 307। यह निर्णय करते समय कि क्या प्रशासनिक कार्रवाई अनुच्छेद 14 के तहत 'मनमाना' है (यानी अन्यथा भेदभावपूर्ण होने के कारण इस न्यायालय ने खुद को हमेशा बुधवार की समीक्षा तक ही सीमित रखा है। इस प्रकार जब प्रशासनिक कार्रवाई पर अनुच्छेद 14 के तहत भेदभावपूर्ण हमला किया जाता है। प्राथमिक समीक्षा का सिद्धांत आनुपातिकता लागू करके न्यायालयों के लिए है। हालांकि जहां अनुच्छेद 14 के तहत प्रशासनिक कार्रवाई को 'मनमाना' माना जाता है, वहां वेडनसबरी सिद्धांतों के आधार पर माध्यमिक समीक्षा का सिद्धांत लागू होता है। सेवा कानून में आनुपातिकता और दंड: सिद्धांतों को अंतिम में समझाया गया है अनुच्छेद 14 के संबंध में पूर्ववर्ती पैराग्राफ को अब यहां लागू किया जाना है जहां अनुच्छेद 14 के तहत सज़ा के आदेश

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

की 'मनमानेपन' का सवाल उठाया गया है। इस संदर्भ में, हम केवल इन मामलों का उल्लेख करेंगे। रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ में [1987] 4 एससीसी 611 इस न्यायालय ने सज़ा की मात्रा में 'आनुपातिकता' का उल्लेख किया लेकिन न्यायालय ने पाया कि सज़ा साबित हुए कदाचार के अनुपात से 'चौंकाने वाली' थी। बी.सी.चतुर्वेदी बनाम भारत संघ [1995] 6 एससीसी 749 में इस अदालत ने कहा कि अदालत तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि सजा ऐसी न हो जिसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया हो। फिर भी न्यायालय मामले को वापस प्राधिकरण को भेज देगा और आम तौर पर एक सज़ा के स्थान पर दूसरी सज़ा नहीं देगा। हालाँकि दुर्लभ स्थितियों में न्यायालय वैकल्पिक दंड दे सकता है। गणयुथम में भी ऐसा कहा गया था। इस प्रकार उपरोक्त सिद्धांतों और निर्णयित मामलों से यह माना जाना चाहिए कि जहां अनुशासनात्मक ढील में सजा से संबंधित एक प्रशासनिक निर्णय पर अनुच्छेद 14 के तहत 'मनमाना' के रूप में सवाल उठाया जाता है, न्यायालय एक माध्यमिक समीक्षा प्राधिकारी के रूप में वेडनसबरी सिद्धांतों तक ही सीमित है। न्यायालय प्राथमिक समीक्षा न्यायालय के रूप में आनुपातिकता लागू नहीं करेगा क्योंकि ऐसे संदर्भ में मौलिक स्वतंत्रता या अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव का कोई मुद्दा लागू नहीं होता है। सज़ा की समीक्षा करते समय न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि वेडनसबरी सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, इसने सज़ा की मात्रा के बारे में नए निर्णय के लिए मामले को प्रशासक के पास भेज दिया है। केवल ऐसे दुर्लभ मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही में लगने वाले समय और

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

अदालतों में लगने वाले समय में लंबी देरी हुई हो और ऐसी अत्यधिक या दुर्लभ आसानी हो, अदालत सजा की मात्रा के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल सकती है।

(28) इस प्रकार यह इस प्रकार है कि रिट कोर्ट को जब अनुचित व्यापार भेदभाव का सामना करना पड़ता है तो यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य है और गलत तरीके से भेदभाव करने वाले व्यक्ति को सममूल्य पर रखकर शत्रुतापूर्ण और द्वेषपूर्ण भेदभाव के दोष को दूर करने में अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहेगा। "भाग्यशाली समूह" (जैसा कि इस मामले में परीक्षण किया गया है) उपचार में समानता ला रहा है, खासकर जब "भाग्यशाली समूह" ने नीतिगत योजनाओं के तहत नियमितीकरण/स्थायित्व के प्रशासनिक आदेश प्राप्त किए हैं, हालांकि वे योजनाएं अब अदालत के हस्तक्षेप के बिना राज्य द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। इस मामले में यहां प्रशासनिक कार्रवाई की तर्कसंगतता या मनमानी के आधार पर जांच की जाने वाली माध्यमिक समीक्षा का कोई सवाल ही नहीं है। रिट कोर्ट अनुचित भेदभाव का प्राथमिक निर्णायक बन जाता है जो वैधानिक औद्योगिक अधिकारों से उत्पन्न हो सकता है लेकिन 5वीं अनुसूची की प्रविष्टि 10 को न्यायिक मंच तक पहुंचाकर अनुच्छेद 14 की कसौटी पर परखा जाता है और जो असाधारण रूप से निर्णय लेने में असमर्थ नहीं है। रिट न्यायालय का क्षेत्राधिकार जहां राज्य न्यायालय को संतुष्ट करने में असमर्थ है कि उसकी कार्रवाई भेदभाव से मुक्त है और जहां मूलभूत और क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य विवादित नहीं हैं।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

परिणाम केवल "वर्षों तक" प्रदान की गई लंबी सेवा के फार्मूले को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है जो कि प्रविष्टि 10 द्वारा वैधानिक रूप से संरक्षित है। "वर्षों तक" का जो अर्थ है वह कला में से एक नहीं है। यह अधिक व्याख्या का प्रश्न है, जिसमें असहनीय और दमनकारी अवधि जैसी चीजों को लागू करना शामिल है, सेवा में हताशा का बिंदु, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के प्रति आशा की हानि, जहां सेवा करने की भावना मर सकती है, लेकिन व्यावहारिक मानवतावाद के सिद्धांतों पर विचार किया जाए तो यह सब मुश्किल हो सकता है। मापने के लिए। हालाँकि केवल एक बात निश्चित है कि नियोक्ता ने बहुत पहले ही किसी सहकर्मी को स्थायित्व प्रदान कर दिया होगा। किसी भी राय को व्यक्त करना मुश्किल है जो इस सहजता में आवश्यक नहीं है और उसे खुला छोड़ दिया गया है, यह संख्यात्मक प्रश्न है कि प्रविष्टि 10 में "वर्षों के लिए" का क्या अर्थ है या क्या योग्यता है। यह आवश्यक नहीं है क्योंकि इन मामलों में तारीखें सहकर्मियों में से "भाग्यशाली समूह" को उनके संबंधित निर्धारण बिंदुओं में जाना जाता है। लेकिन मैं कम से कम इतना तो कहूंगा कि यह मनुष्य द्वारा स्वयं मनुष्य के शोषण के विरुद्ध एक नियम है।

(29) एक पीड़ित व्यक्ति जिसके पास औद्योगिक निर्णायक के समक्ष वैकल्पिक उपचार हैं, को केवल एक औद्योगिक संदर्भ पर मुकदमे में डालना, जहां अकेले संघ द्वारा कारण का समर्थन किया जा सकता है, मेरे विचार से चोट के अपमान को जोड़ना और देरी करना और



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

स्थगित करना होगा सुदूर भविष्य में किसी अप्रत्याशित और अज्ञात बिंदु पर गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार का अधिकार, जो औद्योगिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। इसमें कई जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। आज अनुचित भेदभाव को दूर करना मौलिक मूल्य है और लंबे समय तक चलने वाली मुकदमेबाजी के बाद भेदभाव को दूर करने के समान नहीं है। समानता खंड के चश्मे से देखने पर न्यायालय इस पर आंखें नहीं मूंद सकता है। इसलिए मेरे विचार में रिट कोर्ट 5वीं अनुसूची की प्रविष्टि 10 के माध्यम से समीचीनता के सिद्धांत पर पहली बार औद्योगिक कानून सिद्धांतों को लागू कर सकता है। अधिनियम को कास्टेरिबे के अनुपात के साथ पढ़ा जाता है, बशर्ते तथ्य गंभीर रूप से विवादित न हों, लेकिन प्रतिरोध और खंडन के लिए विवादित न हों। प्रविष्टि 10 को इस तरह से अर्थ दिया जाना चाहिए जिससे हाशिए पर मौजूद श्रमिकों का समय और खर्च बचे, तेजी आए और अदालत के संसाधनों की भी बचत हो और श्रम अदालत में लंबे मुकदमे की पीड़ा से बचा जा सके, जब तक कि परिणाम असाधारण रूप से प्राप्त किया जा सके। रिट क्षेत्राधिकार ज्यादातर औद्योगिक कानून सिद्धांतों पर कानून के चार कोनों के भीतर कार्य करता है। नियम को उचित रूप से सावधानीपूर्वक लागू किया जा सकता है और एक कमजोर नागरिक के प्रतिस्पर्धी हितों और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवारत स्थानीय श्रमिकों के लिए शक्तिशाली राज्य के बीच सावधानी से तौला जा सकता है।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(30) हालांकि कास्ट्राइब श्रमिकों के संघ द्वारा की गई एक शिकायत पर औद्योगिक निर्णय से उत्पन्न हुआ मामला है कि प्रभावित कर्मचारियों को 1980-1985 के बीच बसों की सफाई के लिए निगम द्वारा आकस्मिक मजदूरों के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन श्रम न्यायाधिकरण के समक्ष विवादित मुद्दा यह था कि क्या श्रमिकों को अन्य स्थायी सफाईकर्मियों के समान स्थायीता का दर्जा दिया जा सकता है। औद्योगिक न्यायालय बॉम्बे ने माना कि अनुसूची IV के आइटम 6 के तहत निगम के खिलाफ अनुचित श्रम व्यवहार के संबंध में शिकायत सुनवाई योग्य नहीं थी। हालांकि आइटम 5, 9 और 10 के तहत अनुचित श्रम अभ्यास के संबंध में शिकायतें विचारणीय थीं। एक निष्कर्ष निकाला गया कि अनुसूची IV के आइटम 5 और 9 के तहत अनुचित श्रम अभ्यास किया गया है, महाराष्ट्र राज्य अधिनियम की धारा 30 औद्योगिक और सशक्त बनाती है। श्रम न्यायालय शिकायत में नामित किसी भी व्यक्ति पर निर्णय ले सकते हैं यदि वह किसी अनुचित श्रम व्यवहार में शामिल है या कर रहा है। यह अपने आदेश में तदनुसार घोषणाएं और निर्देश दे सकता है। एमआरटीयू और पीयूएलपी अधिनियमों की अनुसूची IV के आइटम 5, 6 और 9 को देखने की जरूरत है। वे पढ़ते हैं :-

“5. योग्यता की परवाह किए बिना श्रमिकों के एक समूह के प्रति पक्षपात या पक्षपात दिखाना।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

6. कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की स्थिति और विशेषाधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से, कर्मचारियों को "बदली" कैजुअल या अस्थायी के रूप में नियोजित करना और उन्हें वर्षों तक उसी तरह जारी रखना।

9. अवार्ड, निपटान या समझौते को लागू करने में विफलता।”

(31) अनुसूची IV का आइटम 6 केंद्रीय अधिनियम की 5वीं अनुसूची की प्रविष्टि 10 के समान है और इसलिए सामान्य व्याख्या से ग्रस्त होगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (आरए) में अभिव्यक्ति "अनुचित श्रम अभ्यास" को 5वीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी अभ्यास के रूप में परिभाषित किया गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में महाराष्ट्र में एमआरटीयू और पीयूएलपी अधिनियम की धारा 30 जैसे प्रावधान शामिल नहीं हैं। केंद्रीय अधिनियम में अनुचित श्रम व्यवहार को अध्याय वीसी धारा 25टी और 25यू में रखा गया है जो अनुचित श्रम व्यवहार करने पर निषेध और दंड से संबंधित है। प्रावधान इस प्रकार हैं:-

“25टी. अनुचित श्रम व्यवहार का निषेध कोई भी नियोक्ता या कामगार या ट्रेड यूनियन, चाहे वह ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 (1926 का 16) के तहत पंजीकृत हो या नहीं, कोई भी अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

25यू. अनुचित श्रम व्यवहार करने के लिए जुर्माना - कोई भी व्यक्ति जो कोई अनुचित श्रम व्यवहार करता है, उसे कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माने से, जिसे एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(32) किसी नियोक्ता, कामगार या ट्रेड यूनियन के खिलाफ अनुचित श्रम व्यवहार करने पर पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध है। यद्यपि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25वीं के प्रावधानों का उल्लंघन करने का परिणाम कारावास की सजा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि श्रम न्यायालय या रिट न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामला होने पर घोषणा करने और निर्देश जारी करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से रोक दिया गया है। कानून के उल्लंघन से बना है। जहां तथ्यों पर आधारित मुद्दे इतने जटिल नहीं पाए जाते हैं कि श्रम न्यायालय के समक्ष केवल साक्ष्य और सबूत के माध्यम से समाधान किया जा सके, तो इस न्यायालय को अनुचित भेदभाव के कारण निरंतर अधिकार से वंचित व्यक्ति की सहायता के लिए कार्य करने से नहीं रोका जा सकता है। इसके विपरीत, अनुचित भेदभाव को खत्म करना अनुच्छेद 226 के तहत एक बाध्य कर्तव्य के तहत रहेगा। प्रविष्टि 10 शोषण के विरुद्ध एक नियम है। यह आधुनिक गुलामी और अनुचित वर्चस्व के खिलाफ एक नियम है। अनुचित श्रम व्यवहार अनुचित भेदभाव के समान है। ये दोनों एक ही परिवार से हैं। केंद्रीय अधिनियम की प्रविष्टि

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

10 और महाराष्ट्र अधिनियम की प्रविष्टि 6 यह मानती है कि एक ही नियोक्ता के अधीन और एक ही काम करने वाले श्रमिकों का एक समूह स्थायी है जबकि अन्य नहीं। इस प्रकार अनुचित श्रम व्यवहार प्रशासनिक कार्रवाई को चुनौती देने के आधारों के उसी समूह में आएगा, जब रिट न्यायालय दुर्भावना, कानून में द्वेष, वास्तव में द्वेष, पूर्वाग्रह, शक्ति का रंगीन प्रयोग या अधिकार के दुरुपयोग के मामलों से निपटता है और आगे और आगे की ओर। केवल इसलिए कि केंद्रीय अधिनियम में एमआरटीयू और पीयूएलपी अधिनियम और उसकी धारा 30 जैसे विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं हैं, यह इस न्यायालय को अनुचित भेदभाव को दूर करने के लिए रिट कार्यवाही में बाधा नहीं डालेगा, जब भी प्रश्न शुद्ध हो तो श्रम न्यायालय के समक्ष उपचार का सहारा लिए बिना। और निर्णय लेने में सरल प्रविष्टि 10 या प्रविष्टि 6 की सेवा योग्यता परीक्षा के वर्षों की संख्या है जिसे बाद में कास्टेरिबे में माना जाता है। एमआरटीयू और पीयूएलपी अधिनियम की धारा 30 इस प्रकार ध्यान देने योग्य है और इसे तत्काल संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

“30. औद्योगिक और श्रम न्यायालयों की शक्तियां (एल) जहां एक न्यायालय यह निर्णय लेता है कि शिकायत में नामित कोई भी व्यक्ति किसी अनुचित श्रम व्यवहार में शामिल है या कर रहा है, तो वह अपने आदेश में-

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(ए) घोषित करें कि उस व्यक्ति द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार किया गया है या किया जा रहा है, और किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट करें जो अनुचित श्रम व्यवहार में लगा है या लगा रहा है;

(बी) ऐसे सभी व्यक्तियों को इस तरह के अनुचित श्रम अभ्यास को बंद करने और बंद करने और ऐसी सकारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दें (जिसमें अनुचित श्रम अभ्यास से प्रभावित कर्मचारी या कर्मचारियों को उचित मुआवजे का भुगतान या कर्मचारी या कर्मचारियों को बकाया वेतन के साथ या उसके बिना बहाल करना शामिल है) या उचित मुआवजे का भुगतान) जैसा कि न्यायालय की राय में अधिनियम की नीति को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो;

(सी) जहां एक मान्यता प्राप्त संघ किसी भी अनुचित श्रम अभ्यास में लगा हुआ है या संलग्न है, निर्देश देता है कि उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी या धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत उसके सभी या किसी 11 अधिकार या धारा 23 के तहत उसके अधिकार निलंबित कर दिया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के तहत अपने समक्ष होने वाली किसी भी कार्यवाही में, न्यायालय ऐसे अंतरिम आदेश (किसी भी अस्थायी राहत देने वाले प्रतिबंध आदेश सहित) पारित कर सकता है, जैसा कि वह उचित और उचित समझे (व्यक्ति को उस प्रथा को अस्थायी रूप से वापस लेने

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

के निर्देश भी शामिल है जिसके बारे में शिकायत की गई है, जो एक मुद्दा है) ऐसी कार्यवाही में) लंबित अंतिम निर्णय: बशर्ते कि न्यायालय उस संबंध में एक आवेदन पर, उसके द्वारा पारित किसी भी अंतरिम आदेश की समीक्षा कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के तहत जांच करने या कार्यवाही करने के उद्देश्य से न्यायालय के पास वही शक्तियां होंगी जो न्यायालयों में निहित हैं - (ए) शपथ पत्र द्वारा तथ्यों का सबूत; (बी) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, और शपथ पर उसकी जांच करना (सी) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करना: और (डी) गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करना।

(4) न्यायालय के पास अपने समक्ष कार्यवाही के लिए किसी भी पक्ष को लिखित रूप में और ऐसे रूपों में, जो वह उचित समझे, कोई भी जानकारी देने के लिए कहने की शक्ति होगी जो उसके और पक्ष के समक्ष किसी भी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक मानी जाती है। इसलिए बुलाया जाएगा तो उसे अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार जानकारी देनी होगी और यदि न्यायालय द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की गई हो। इसे ऐसे तरीके से सत्यापित करें जैसा निर्धारित किया जा सकता है।"

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(33) मेरे विचार से उपरोक्त धारा 30 बॉम्बे में रिट कोर्ट को औद्योगिक और श्रम न्यायालयों के निर्णय और निष्कर्षों के प्रतिस्थापन में मूल संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने से रोक सकती है, लेकिन ऐसी शक्तियों के प्रयोग पर केंद्रीय अधिनियम के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है। इस क्षेत्राधिकार के भीतर केवल एक वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के कारण जो समान रूप से प्रभावकारी नहीं हो सकता है। यह कहना सामान्य बात है कि श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष उपाय स्वयं रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक उपचार हैं, लेकिन ऐसे मामले में पहली बार कार्रवाई करने के लिए रिट न्यायालय में कोई कानूनी रोक नहीं है जहां अनुचित भेदभाव की वकालत की जाती है और मौजूदा पूर्व दृष्टया और रिट कोर्ट की संतुष्टि के लिए दिखाया गया है जब यह संविधान के अनुच्छेद 14 की सहायता में अच्छी तरह से कार्य कर सकता है और भेदभाव को दूर कर सकता है और यथास्थिति बहाल कर सकता है।

(34) आधुनिक संदर्भ में और उस समय में रहते हुए जब हम ऐसा कर रहे हैं जहां विशाल भीड़ अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। फिर मुझे आश्चर्य होता है कि आम जनता के मन में पनपी कैंसरकारी धारणा और धारणा को कोई कैसे आसानी से खारिज कर सकता है कि रोजगार के लिए सामने वाला दरवाजा वास्तव में पिछला दरवाजा है। पिछले दरवाजे से की जाने वाली प्रविष्टियों पर धर्मप्रचार करना और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की दिखावा



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

करके सभी प्रकार की भर्ती स्थितियों में भारत में सार्वभौमिक रूप से लागू होने में सक्षम पूर्ण योग्यता का एक कानूनी सिद्धांत विकसित करना बहुत आसान है, जो उन प्रावधानों के पीछे एक किले और पवित्रता की ढाल के रूप में छिपा हुआ है। योग्यता। जब हम सार्वजनिक रोजगार की प्राचीरों पर नज़र डालते हैं तो नौकरी की तलाश में उम्मीदवारों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। यदि मौका दिया जाए तो वे सभी योग्यता के सिद्धांतों पर परीक्षण और परीक्षण के इच्छुक हैं। वे सभी सार्वजनिक रोजगार के सामने वाले दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, इस बात से अनजान हैं कि ऊंची प्राचीरों से नीचे की गलियों से लेकर सार्वजनिक दृश्य के लिए बंद किले तक देखा जा सकता है, जहां से कतारें लगने के दौरान रोजगार पत्र जारी किए जाएंगे। भर्ती एजेंसियों की सिफारिशों से लैस कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के अलावा कोई उम्मीद नहीं बची है, जहां अक्सर कैडर पदों को अनुच्छेद 14 और 16 की ढाल द्वारा संरक्षित नियमों और विनियमों का सावधानीपूर्वक पालन करके बोर्डों और आयोगों के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। क्या संविधान निर्माताओं ने कभी सपने में भी ऐसा सोचा होगा, यह प्रश्न है। योग्यता को नये सिरे से विकसित करना होगा। यह धारणा पूरे भारत में और सभी देशों में है, जिसे आम तौर पर लोगों की नज़र कर्मचारी चयन समिति से कर्मचारी चयन समिति, भर्ती बोर्ड से भर्ती बोर्ड, लोक सेवा आयोग से लोक सेवा आयोग और इसी तरह आगे की ओर स्थानांतरित होने के रूप में माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट परेशान है। इसमें कोई शब्द नहीं बचे हैं। इसने बार-बार बोला है और भ्रष्ट नियुक्तियों पर कड़ा प्रहार

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

किया है। लेकिन प्रशासक पिछले सुधार है। मैं केवल हरियाणा लोक सेवा आयोग के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार का उल्लेख करूंगा: **मेहर सिंह सैनी, अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग और अन्य (11)** जहां सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के आचरण पर कड़ी आलोचना की थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए एक संदर्भ पर हरियाणा के राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की सलाह पर कार्य करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को राय देने के लिए किए गए अनुरोध पर उनका 'दुर्व्यवहार' और क्या वे संवैधानिक पद संभालने के योग्य हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्य संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन उन्हें केवल 'कदाचार' के आधार पर हटाया जा सकता है, जबकि अन्य संवैधानिक कार्यालय धारकों को 'साबित कदाचार' के उच्च मानकों पर रखा जाता है। सार्वजनिक कार्यालय में भ्रष्ट नियुक्तियाँ करने के लिए अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की सिफारिश करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन मुद्दों पर गहराई से विचार किया गया था। न्यायालय ने माना कि चयन प्रक्रिया पर 'गंभीर संदेह' जो आयोग और उसके सदस्यों के कामकाज के लिए जिम्मेदार है, तब पर्याप्त है जब ऐसा आचरण उनके पद के लिए आवश्यक व्यवहार, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के मानकों को पूरा नहीं

(11) (2010) 13 एससीसी 586.

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

करता है। और इस प्रकार निष्कासन को उचित ठहराने वाले 'दुर्व्यवहार' के दायरे में आता है।  
न्यायालय ने कहा :-

“आयोग में महान शक्तियाँ निहित हैं और इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी शक्तियों का कोई दुरुपयोग न हो। किसी संस्था के कामकाज में सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांत उसके उचित प्रशासन के लिए आवश्यक हैं। आयोग के कामकाज में जनता के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता की तुलना न्याय प्रशासन में न्यायपालिका के कार्यों से की जा सकती है, जिसे लॉर्ड डेनिंग ने मेट्रोपॉलिटन प्रॉपर्टीज कंपनी बनाम लैनन (1968) 3 ऑल ई के 304) में निम्नलिखित शब्दों में बताया था: “न्याय की जड़ें विवाद में होनी चाहिए; और आत्मविश्वास तब नष्ट हो जाता है जब सही सोच वाले लोग यह सोचकर चले जाते हैं: 'न्यायाधीश पक्षपाती था।’

“अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का आचरण बोर्ड से ऊपर और निंदा से परे होना चाहिए। लोक सेवा आयोग की संस्था की विश्वसनीयता इसके उचित कामकाज पर आम आदमी के विश्वास पर आधारित है। भ्रष्टाचार के लगातार आरोपों और राष्ट्रीय हित की कीमत पर पारिवारिक हितों को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को हटाने के लिए संवैधानिक तंत्र को लागू करने से आयोग में जनता का

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

विश्वास कम हो गया है। प्रो. ब्राउन और गार्नर का अपने ग्रंथ फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तीसरे संस्करण में अवलोकन। इस संबंध में (1983) का संदर्भ उपयोगी रूप से लिया जा सकता है। उन्होंने कहा, "किसी प्रशासन के व्यवहार का मानक अंततः उन सार्वजनिक अधिकारियों की गुणवत्ता और परंपराओं पर निर्भर करता है जो इसे बनाते हैं, न कि ऐसे प्रतिबंधों पर जो न्यायिक नियंत्रण की प्रणाली के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं।" अफसोस की बात है कि वर्तमान मामला इस न्यायालय में किए गए कई संदर्भों में से एक है जहां आयोग के सदस्यों के खिलाफ उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के संबंध में गंभीर आरोप और आरोप लगाए गए हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा कथित तौर पर की गई चूक और गलत व्यवहार के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय में 31 जुलाई 2008 को राष्ट्रपति संदर्भ भेजा गया।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(35) अतीत में ऐसे अन्य राष्ट्रपति संदर्भ और मामले थे जहां लोक सेवा आयोगों का आचरण स्पष्ट रूप से न्यायिक जांच के दायरे में आया था। देखें, राम आश्रय यादे (डॉ.) में 1997 का संदर्भ संख्या 1 (12) इंद्रप्रीत सिंह काहलों बनाम पंजाब राज्य (13) आदि।

(36) फिर यह पूछा जा सकता है: कौन जानता है कि योग्यता कहाँ है? योग्यता का मूल्यांकन करने वालों की योग्यता कहाँ है, कौन जानता है? कौन जानता है कि सत्य अमूर्तता में कहाँ छिपा है? आइए हम उपदेश न दें या मूसा को हमारे लिए गोलियाँ लिखने के लिए न बुलाएँ। आइए हम कानून के दायरे में दूर-दराज के वन नर्सरी (सरकारी विभाग के कार्यालयों में नहीं) में कमजोर मैनुअल श्रमिकों के ऐसे लंबे समय तक चलने वाले शोषणकारी रोजगार का स्वतंत्र, उचित और उदारतापूर्वक समर्थन करने का प्रयास करें और याचिकाकर्ताओं को कुछ हद तक प्रदान करें। मजदूरों के रूप में भी स्थायित्व ताकि उनका दिन सूर्यास्त के साथ शुरू न हो। वास्तव में, जब तक परिदृश्य बदल नहीं गया, उन्होंने एक-एक ईंट जोड़कर राष्ट्र का निर्माण किया।

(12) (2000) 4 एससीसी 309

(13) (2006) 11 एससीसी 356

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

वे घर बनाए जिनमें हम रहते हैं, वे रेस्तरां बनाए गए जिनमें हम सड़कों पर भोजन करते हैं, हम पक्की सड़कों पर यात्रा करते हैं, हवाई जहाज उतरते और उड़ान भरते हैं और वह अदालत जिसमें हम न्याय देने के लिए बैठते हैं। वे न्यायाधीशों के आने से पहले अदालत में आये। ये राष्ट्र के गुमनाम निर्माता हैं जिनके पास उनके द्वारा अर्जित अल्प दैनिक मजदूरी के अलावा न तो पुरस्कार है, न आशा और न ही कोई प्रतिफल, जिसका भुगतान दिन के अंत में भी नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वे अपने घर न जाने कहां चले जाएं।

(37) लेकिन जब तक 'समाजवाद' शब्द संविधान की प्रस्तावना में रहता है तब तक न्यायाधीश संवैधानिक रूप से वितरणात्मक न्याय लागू करने के लिए बाध्य हैं जो कहता है : "प्रत्येक को उसके योगदान के अनुसार" ऐसे योगदान को कौन माप सकता है? निश्चित रूप से न्यायाधीश नहीं. लेकिन हाँ, यदि चिकित्सक बीमारी को ठीक करने में विफल रहता है तो न्यायाधीश एक सर्जन की तरह हस्तक्षेप कर सकता है। यदि प्रशासक वितरणात्मक न्याय के प्रीमियम के साथ भुगतान की गई सामाजिक बीमा योजना के आधार पर आराम के लिए आवश्यक सहायता की न्यूनतम खुराक की गणना करने के बोझ का निर्वहन करने में अपने संवैधानिक कर्तव्य में विफल रहता है, तो न्यायालय न्याय के पिपेट को कैलिब्रेट कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 51ए (जे) द्वारा दिए गए मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

लिए बाध्य करते हैं ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके।  
अफसोस की बात है कि संविधान का यह हिस्सा उस दिन से अड़तीस साल की विकृति से अपंग  
है, जब संसद ने बिग बुक में छापना उचित समझा।

(38) एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (14) में न्यायमूर्ति कपाड़िया ने  
संविधान पीठ के लिए इतनी बातें कीं जितनी उच्चतम न्यायिक ऊंचाई से और इतने वजनदार  
शब्दों में पहले कभी नहीं कही गईं:-

“संवैधानिक निर्णय किसी अन्य निर्णय लेने की तरह नहीं है, हर प्रमुख संवैधानिक मामले में  
एक नैतिक आयाम होता है; पाठ की भाषा आवश्यक रूप से एक नियंत्रित कारक नहीं है।  
हमारा संविधान अपनी सामान्यताओं के कारण और इसकी व्याख्या करते समय न्यायाधीशों  
की अच्छी समझ के कारण काम करता है। यह न्यायाधीशों की कार्रवाई की सूचित स्वतंत्रता  
है जो शासन के हमारे बुनियादी दस्तावेज़ को संरक्षित और संरक्षित करने में मदद करती है  
।”

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(39) उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक उप न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भावना और दर्शन को बनाए रखने में संवैधानिक मुद्दों से निपटने के दौरान बेंच पर स्पष्ट न्यायिक अनुभव से प्राप्त ऐसी मर्मज्ञ तीक्ष्णता के साथ उनका आधिपत्य आगे बढ़ गया और यदि मैं कर सकता हूं न्यायालय ने जो सलाह दी है उसका सार कम से कम शब्दों में बताने की स्वतंत्रता लें, लोगों का कल्याण है और जो सर्वोच्च कानून होना चाहिए। यह सुनाया गया फैसला :-

“संविधान एक अस्थायी कानूनी दस्तावेज़ नहीं है जो गुज़रते समय के लिए कानूनी नियमों का एक सेट शामिल करता है। यह एक विस्तारित भविष्य के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है और आने वाले युगों तक कायम रहने का इरादा रखता है और परिणामस्वरूप मानव मामलों के विभिन्न संकटों के लिए अनुकूलित किया जाता है। इसलिए व्याख्या के लिए सख्त शाब्दिक दृष्टिकोण के बजाय उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। एक संवैधानिक प्रावधान को संकीर्ण और संकुचित अर्थ में नहीं बल्कि व्यापक और उदार तरीके से समझा जाना चाहिए ताकि बदलती परिस्थितियों और उद्देश्यों का अनुमान लगाया जा सके और उन्हें ध्यान में रखा जा सके ताकि संवैधानिक प्रावधान जीवाश्म न बन जाएं बल्कि नई उभरती समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त लचीले बने रहें।



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

व्याख्या का यह सिद्धांत मौलिक अधिकारों की व्याख्या के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। मौलिक अधिकारों को राज्य की ओर से अपने नागरिकों को दिया गया उपहार मानना ग़लत है। व्यक्तियों के पास किसी भी संविधान से स्वतंत्र रूप से बुनियादी मानवाधिकार हैं, इस बुनियादी तथ्य के कारण कि वे मानव जाति के सदस्य हैं। ये मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनका आंतरिक मूल्य है, संविधान का भाग-III मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह उनके अस्तित्व की पुष्टि करता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य कुछ विषयों को राजनीतिक विवाद के क्षेत्र से हटाकर उन्हें बहुमत और अधिकारियों की पहुंच से परे रखना और उन्हें अदालतों द्वारा लागू किए जाने वाले कानूनी सिद्धांतों के रूप में स्थापित करना है। हर अधिकार की एक सामग्री होती है। प्रत्येक मूलभूत मूल्य को भाग-II में मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है क्योंकि इसका आंतरिक मूल्य है। उलटा लागू नहीं होता। एक अधिकार मौलिक अधिकार बन जाता है क्योंकि इसका मूलभूत मूल्य होता है। सिद्धांतों के अलावा अनुच्छेद की संरचना को भी देखना होगा जिसमें मौलिक मूल्य शामिल है। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर एक सीमा है। एक संविधान और विशेष रूप से उसका वह संविधान जो मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है और उन्हें स्थापित करता है जिसके लिए राज्य के सभी व्यक्ति हकदार हैं, को एक उदार और उद्देश्यपूर्ण निर्माण दिया जाना है। सकाल पेपर्स (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय ने माना है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति और सामग्री पर विचार करते

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

समय न्यायालय को भाषा की शाब्दिक अर्थ में व्याख्या करने में बहुत चतुर नहीं होना चाहिए ताकि उन्हें छोटा कर दो। न्यायालय को संविधान की व्याख्या इस तरीके से करनी चाहिए जिससे नागरिक इसके द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का पूरी तरह से आनंद उठा सकें। भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार की शाब्दिक और संकीर्ण व्याख्या का एक उदाहरण ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक निर्णय है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से माना कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित कोई भी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने से इनकार कर दिया। इसने केवल अधिनियमित कानून के अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित किया। तीन दशकों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन (10) मामले में अपने पिछले फैसले को खारिज कर दिया और मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्य मामले में अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 द्वारा विचार की गई प्रक्रिया को तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप भी होनी चाहिए। यह उदाहरण मौलिक अधिकार की व्यापक व्याख्या का एक उदाहरण प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 21 में 'जीवन' शब्द का तात्पर्य केवल भौतिक या पशु

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

अस्तित्व से नहीं है। जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। इस न्यायालय ने कई मामलों में मूलभूत विशेषताएं निकाली हैं जिनका विशेष रूप से भाग-III में इस सिद्धांत पर उल्लेख नहीं किया गया है कि कुछ अस्पष्ट अधिकार प्रगणित गारंटियों में निहित हैं। उदाहरण के लिए सूचना की स्वतंत्रता को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी में अंतर्निहित माना गया है। भारत में हाल तक सूचना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला कोई कानून नहीं है। हालाँकि, इस न्यायालय ने एक उदार व्याख्या द्वारा जानने के अधिकार और जानकारी तक पहुँचने के अधिकार को इस तर्क के आधार पर घटाया कि एक खुली सरकार की अवधारणा जानने के अधिकार का प्रत्यक्ष परिणाम है जो अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है। (1)(ए). ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी अधिकार की सामग्री को न्यायालयों द्वारा परिभाषित किया जाता है। अधिकार की सामग्री पर अंतिम शब्द इस न्यायालय का है। इसलिए संवैधानिक निर्णय इस अभ्यास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवैधानिक न्यायनिर्णयन की प्रकृति कई बहसों का विषय रही है। एक चरम पर यह तर्क दिया जाता है कि कानून की न्यायिक समीक्षा संविधान की भाषा और उसके मूल इरादे तक ही सीमित होनी चाहिए। दूसरे छोर पर गैर-व्याख्यात्मकता का दावा है कि संवैधानिक पाठ का तरीका और अनिश्चित प्रकृति विभिन्न प्रकार के मानकों और मूल्यों की

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

अनुमति देती है। अन्य लोग दावा करते हैं कि अधिकारों के विधेयक का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया की रक्षा करना है।

(40) इन सबके सामने मैं यह सोचने के लिए इच्छुक हूँ कि मामलों का वर्तमान समूह "उदार और उद्देश्यपूर्ण निर्माण" के लिए इस तरह के असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त प्रतीत होता है और मानव संकट से निपटने के लिए एक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। मामले. एम.नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को इस तरह के दृष्टिकोण का अनुकरण करने और पालन करने की सलाह दी है, जिसे दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों से अलग व्यवहार करते समय अनुच्छेद 14 के सिरिंज द्वारा अदालत में पेश किए गए गतिशील और व्यावहारिक मानवतावाद का आदर्श सिद्धांत होना चाहिए। उन व्यक्तियों के मामले जिन्हें पिछले दरवाजे से सार्वजनिक पदों पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों या राज्य, बोर्ड, निगम आदि के स्वतंत्र उपकरण बनाने वाले वैधानिक अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। एक नागरिक न्यायाधीश का संवैधानिक कर्तव्य है जैसा कि भारत के प्रत्येक अन्य नागरिक का है, यह संसद द्वारा 1976 में किए गए बयालीसवें संशोधन द्वारा प्रस्तुत संविधान के अनुच्छेद 51 ए (एच) द्वारा संरक्षित और निर्देशित कर्तव्य है। 'मानवतावाद' की भावना विकसित करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(41) मानवतावाद भारत के सभी नागरिकों के लिए दूरगामी महत्व का एक संवैधानिक शब्द बन गया, जिसका अनुकरण किया जा सके और न्यायाधीशों और नौकरशाहों सहित अपने निर्णयों और प्रशासनिक निर्णयों को संयमित करने के लिए सम्मान के लिए बाध्य महसूस किया जा सके। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अंततः पहले एक नागरिक होता है और उसके बाद पद धारण करने के आधार पर न्यायाधीश होता है। यदि संविधान या कानून द्वारा न्यायालय और प्रशासक पर ऐसे नैतिक कर्तव्य और नैतिक मानकों का पालन करने का कर्तव्य डाला गया है तो यह उन अधिकारों, विशेषाधिकारों या शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक महान और उत्कृष्ट है जिनका वे आनंद ले सकते हैं या प्रशासन के लिए उपयोग कर सकते हैं। न्याय का या शासन का. संविधान एक विनम्र दस्तावेज़ है, एक शाश्वत स्रोत है जो हमेशा फूटता रहता है और कारण के लिए उचित, उचित और आनुपातिक रूप से निर्णय लेने के लिए शक्ति और अधिकार का सौम्य मार्गदर्शन करता है। यह स्वयं अपनी संवैधानिक सीमाओं पर आत्म-संयम के रूप में कार्य करता है। एक न्यायालय को कानून के अनुसार सामाजिक रूप से उचित आदेश देने के लिए कार्यालय के आधार पर राज्य द्वारा स्वीकृत निर्णय लेने वाले उपकरण के रूप में माना जा सकता है, निर्णय बाध्यकारी है और इसके बाध्यकारी क्षेत्राधिकार की गंभीर प्रकृति एक दुर्जेय बाधा और जांच के रूप में कार्य करती है। आदेश या निर्णय देने में यह क्या कर सकता है या क्या करने से बच सकता है। सभी नागरिकों

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

को सौंपा गया कर्तव्य, जिसमें स्पष्ट रूप से उनके पद के आधार पर सर्वोच्च न्यायपालिका के सदस्य शामिल हैं, संविधान के अगुआ के रूप में खड़ा है और जो संसद के ज्ञान के अनुसार अनुच्छेद 51 ए (एच) में योग्य है: -

"वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना का विकास करना"

(42) जब संविधान हमें आगे बढ़ने का निर्देश देता है तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। संवैधानिक कर्तव्य तब संवैधानिक अनिवार्यता और न्यायिक सीमा बन जाता है। फिर न्यायाधीश को अपने सभी निर्णयों को संवैधानिक आदेश के अनुरूप सूचित करना चाहिए। तब न्यायाधीश के लिए कर्तव्य अपने आप में उसके व्यवसाय का आदेश बन जाता है कि वह हमेशा इस मुद्दे से अलग और उदासीन रहे। न्यायाधीश प्रशासक नहीं है। एक प्रशासक यह तर्क दे सकता है और सुना जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य अप्रवर्तनीय हैं। लेकिन न्याय प्रदान करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, न्यायालय इन सिद्धांतों को खारिज नहीं कर सकता है यदि कोई अन्य पूर्ण कानूनी सिद्धांत किसी अन्य तरीके से राहत को पूरी तरह से उचित ठहराने वाला नहीं पाया जाता है। यह रिट के माध्यम से इस कर्तव्य को लागू करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन यदि इसके सिद्धांतों पर आवश्यकता उत्पन्न होती है तो यह अपनी राय बदल सकता है। हालाँकि कर्तव्य

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

को केवल संवैधानिक तरीकों से ही बढ़ावा दिया जा सकता है, **संदर्भ: मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुलभाई (15)**।

(43) मैनुअल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी राज्य के अधीन या राज्य के मामलों के संबंध में पद धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे राज्य से पूछने के लिए उनकी समस्याओं, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को समझने और समझने के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण से देखे जाने के पात्र हो सकते हैं। यद्यपि गतिशील मानवतावाद की भावना के साथ उनकी स्थिति सुधारने में उनकी मदद करना, क्योंकि अमीर और शक्तिशाली लोगों को वास्तव में उन्हें समझने या उनके साथ सहानुभूति रखने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इन मामलों के संबंध में राज्य द्वारा अपने उत्तरों में दिखाए गए भर्ती नियमों की अनुपस्थिति में इस अदालत के लिए कई वर्षों पहले की गई नियुक्तियों में नियम के उल्लंघन को पढ़ना संभव नहीं हो सकता है। दावों को खारिज करने के लिए मछली पकड़ने की जांच करना इस न्यायालय का काम नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह की व्यस्तताओं को देखते हैं, भले ही इसे 'नियुक्तियां' न कहा जाए, तो इसे मानवतावाद की भावना से जोड़ा जाना चाहिए और इसके बारे में न्यायिक

(15) ए आई आर 1976 एससी 1455.

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

रूप से व्यावहारिक होना चाहिए। वर्तमान मामलों में नियम बिना किसी और बात के अपने आप में लोहे के परदे नहीं बन जाने चाहिए, जिसमें हाथ से काम करने वाले श्रमिकों के लिए कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। पीड़ित जनता द्वारा अवैध नियुक्तियों को चुनौती देना जनहित याचिका में और भी अधिक खेदजनक है, जहां सेवा कानून के सिद्धांत मिसाल का हवाला देते हुए किसी गैरकानूनी नियुक्ति को रद्द करने में सक्षम नहीं हैं। गलत काम करने वाले को कानून में कई सुरक्षाएं प्राप्त हैं लेकिन वे सुरक्षाएं केवल तब तक हैं जब तक कि कुछ भी संभव होने पर न्यायालय की अंतरात्मा परेशान न हो जाए और हमें संवैधानिक न्यायाधीशों को इसी तरह देखना चाहिए कि वे क्या कर सकते हैं। यहीं पर एम नागराज में न्यायमूर्ति कपाड़िया की अंतर्दृष्टि धड़कती है। यदि प्रशासक ने कानून को उसी तरह लागू किया और उसका पालन किया जैसा कि बनाया गया था और उसका मतलब था और उसने कभी भी नियम से परोक्ष विचलन नहीं किया था तो यह कहना गलत होगा कि हजारों और हजारों निर्णय लिखे नहीं गए होंगे या उनकी आवश्यकता नहीं होगी। अगर दुनिया में सब कुछ आदर्श रूप से ठीक होता तो शायद उमादेवी के बारे में नहीं लिखा जाता या इसकी आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार पूरी तस्वीर को न्यायालय की कलम द्वारा समग्र रूप से चित्रित किया जाना चाहिए, यहां तक कि राहत के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना में खड़े एक व्यक्ति के लिए भी। मैं यही सोचता हूं और यह पूरी तरह गलत भी हो सकता है।



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(44) उपरोक्त पृष्ठभूमि में विवादास्पद प्रश्न यह है: क्या वे दैनिक वेतन भोगी श्रमिक हैं जिनका राज्य द्वारा अनुचित श्रम प्रथा का सहारा लेकर वर्षों से शोषण किया गया है, क्या वे धूप, छाया और चांदनी में हिस्सेदारी के हकदार नहीं हैं? प्रार्थना करें कि क्या मैं काम की कुछ सुरक्षा मांग सकता हूँ। प्रश्न उठाने के बाद अभी भी एक उत्तर है, एक प्रतिवाद, जिसे राज्य द्वारा उठाए जाने पर एक स्वीकार्य बचाव के रूप में कानून द्वारा अनुमति दी जाती है, जिसे राज्य अदालत में मुकदमे का सामना करते समय नियमित और लापरवाही से उठाता है: आखिरकार उन्होंने सगाई को शुरू करने के लिए स्वीकार क्यों किया? क्या किसी ने उन पर यह जबरदस्ती नहीं की? कौन किसी को मजबूर करता है? आदर्श नियोक्ता बनने की आशा रखने वाले राज्य को कौन नौकरी देने के लिए बाध्य करता है या इसे न छीनने के लिए बाध्य करता है। यह राज्य का विशेषाधिकार है जिसका पता अनुच्छेद 310 में आनंद सिद्धांत से चलता है। शामिल होने के अधिकार में अलग होने का अधिकार भी शामिल है। न्यायालय में तर्क को ग़लत नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिर मानवतावाद के मानकों को लागू करने से यह संवैधानिक न्यायालय द्वारा राहत देने के मामलों में कानून के अनुरूप न्यायिक संवेदनशीलता का मामला बन जाता है, जहां जीवित ऊतकों को रक्त की आपूर्ति करने के लिए पिछले न्यायिक बोझों को खोलने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। कानून ताकि यह विघटित न हो।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(45) यहीं पर मुझे एम.नागराज द्वारा पहले ही उद्धृत किए गए ज्ञान के शब्दों को दोहराने की आवश्यकता होगी और विवादास्पद मुद्दे पर जोर देने के लिए सराहनीय लाभ के साथ उन पर फिर से जोर देना होगा: "संविधान एक अस्थायी कानूनी दस्तावेज नहीं है जो एक सेट का प्रतीक है बीतते समय के लिए कानूनी नियम, यह एक विस्तारित भविष्य के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करता है और आने वाले युगों तक कायम रहने का इरादा रखता है और परिणामस्वरूप मानव मामलों के विभिन्न संकटों के लिए अनुकूलित किया जाता है। इसलिए उसे व्याख्या के लिए सख्त शाब्दिक दृष्टिकोण के बजाय उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक संवैधानिक प्रावधान को संकीर्ण और संकुचित अर्थ में नहीं बल्कि व्यापक और उदार तरीके से समझा जाना चाहिए ताकि बदलती परिस्थितियों और उद्देश्यों का अनुमान लगाया जा सके और उन्हें ध्यान में रखा जा सके ताकि संवैधानिक प्रावधान जीवाश्म न बन जाएं बल्कि नई उभरती समस्याओं और चुनौतियाँ से निपटने के लिए पर्याप्त लचीले बने रहें।" (जोर देने के लिए रेखांकित)

इस न्यायालय ने मजदूरों के संबंध में भेदभाव पर जो विचार व्यक्त किये हैं।

(46) 2009 के सीडब्ल्यूपी संख्या 1169 में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश; वेद पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य; (संक्षेप में "वेदपाल") को यह तय करने के

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

लिए बुलाया गया था कि क्या याचिकाकर्ता उस तारीख से सेवाओं के नियमितीकरण का दावा कर सकते हैं, जिस तारीख से उनके कनिष्ठों को उस समय प्रचलित नीति के अनुसार नियमित किया गया था। उन्होंने पहले 2005 के सीडब्ल्यूपी नंबर 6341 के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें राज्य को नियमितीकरण के दावे पर निर्णय लेने के निर्देश जारी किए गए थे। दावे पर विचार किया गया और सिफारिश की गई, लेकिन अंततः इसे खारिज कर दिया गया, जैसा कि दलीलों में कहा गया था, "सिर्फ उमा देवी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण।" विद्वान एकल न्यायाधीश ने उनके सामने प्रस्तुत तथ्यों पर एक दृष्टिकोण लिया (यह छिपाते हुए कि यदि याचिकाकर्ता बने रहते हैं) निजी उत्तरदाताओं से वरिष्ठ होने के कारण उन्हें नियमितीकरण का पूर्व अधिकार था, उनके दावे पर निजी उत्तरदाताओं के मामले में समान शर्तों पर विचार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया है और इसलिए उनके दावे को खारिज करने का आदेश दिया गया है। 2007 में पारित याचिकाकर्ताओं को कायम नहीं रखा जा सकता और तदनुसार रद्द कर दिया गया। एक निर्देश जारी किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को उसी तारीख से सेवा में नियमित किया जाए जब उनके कनिष्ठों को नियमित किया गया था और उसी शर्तों के तहत ऐसा किया जाए। इस आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा अपील की गई थी।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(47) पंजाब राज्य बनाम सुखमिंदर कौर और अन्य (16) में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच; हरियाणा राज्य बनाम पियारा सिंह में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के बाद भेदभाव से उत्पन्न एक मामले में भाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत के माध्यम से बोलना, लेकिन उमादेवी को नोटिस करने के बाद निम्नानुसार आयोजित किया गया: -

“इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उपरोक्त नीति के कार्यान्वयन पर सैकड़ों वर्कचार्ज/दैनिक वेतनभोगियों को नियमित स्थापना पर लाया गया था, लेकिन निजी उत्तरदाताओं को केवल इस आधार पर इस तरह के लाभ से वंचित कर दिया गया है कि उनकी नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर थीं। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष ली गई इस तरह की याचिका को खारिज कर दिया गया है और हमारे विचार में यह सही है क्योंकि 89 दिनों की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति के बाद निजी उत्तरदाताओं को अस्थायी आधार पर और नियमित वेतनमान में नियुक्त किया गया था (न्यूनतम वेतनमान के साथ) विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी पाया है कि उन्हें अस्थायी आधार पर विधिवत स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किया गया था।

(16) 2013 (3) एससीटी 801.

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

यह सच हो सकता है कि एक रिट कोर्ट आम तौर पर प्रशंसक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक परमादेश जारी नहीं करेगा क्योंकि ऐसा कार्य कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है जैसा कि हरियाणा राज्य और अन्य बनाम पियारा सिंह और अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया है। अन्य (1992 एससीसी (4) 118 और अन्य बाद के निर्णय। हालाँकि जब राज्य या उसके उपकरणों द्वारा लिए गए किसी सचेत निर्णय के कार्यान्वयन का प्रश्न उठता है तो संवैधानिक न्यायालय को ऐसे कार्यान्वयन के लिए वांछित निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। यह नीति भेदभाव रहित तरीके से बनाई गई है ताकि सभी कर्मचारियों को बिना किसी कृत्रिम वर्गीकरण के इसका लाभ दिया जा सके। विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी यही किया है।"

(48) उमादेवी मामले में संविधान पीठ के फैसले पर गौर करने के बाद 2 जुलाई 2013 को यह फैसला सुनाया गया। उसी पीठ ने 2013 के एलपीए संख्या 1214 में सिद्धांत को दोहराया; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चेत राम और अन्य का फैसला 12 जुलाई 2013 को हुआ। अब 2011 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10017 में उन मामलों को मेरे सामने रखते हुए रिमांड आदेश की बारी है।

2011 के सीडब्ल्यूपी नंबर जे 0017 के समझौते:

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(49) वेद पाल के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण को अपील में बरकरार रखा गया था और फैसले के खिलाफ हरियाणा राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में लाई गई एसएलपी को 2 मई 2014 को 2012 की एसएलपी (सिविल) संख्या 36871 में खारिज कर दिया गया था। 2012 के एलपीए नंबर 1037 में 25 जुलाई 2012 को फैसला सुनाया गया। हालांकि लगभग उसी समय विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2011 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10017 में खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में वेद पाल के मामले में वही दृष्टिकोण अपनाया था। 19 सितंबर 2012 को जिसके खिलाफ इंद्रा कोर्ट अपील में अपील की गई थी। यह अपील 2012 के एलपीए नंबर 1965 और 2013 के क्रॉस एलपीए नंबर 643 में ब्रदर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने आई, जब चन्नी में फैसले को डिवीजन बेंच के ध्यान में लाया गया। चूंकि चन्नी में समन्वय पीठ ने पहले ही विद्वान एकल न्यायाधीश के समान आदेशों को रद्द कर दिया था और मामले को नए फैसले के लिए भेज दिया था, खज्जन सिंह के मामले में पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के 19 सितंबर 2012 के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस भेज दिया। नए फैसले के लिए. इस प्रकार 2011 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10017 खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मेरे सामने रखा गया है। इसलिए मैं 2011 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10017 से कुछ आवश्यक तथ्य निकालूंगा।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(50) संक्षेप में कहा गया है कि खज्जन सिंह के मामले में याचिकाकर्ताओं का दावा 31 जनवरी 1996 और 1 अक्टूबर 2003 के नीतिगत निर्णयों के अनुसार याचिकाकर्ता दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को नियमित करने के निर्देश के लिए है, जैसा कि 10 फरवरी 2004 के नीति पत्र द्वारा संशोधित किया गया है, जो संरक्षित है। वे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने 30 सितंबर 2003 को 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और 30 सितंबर 2003 को सेवा में थे और वे नियमितीकरण के हकदार हैं। यहां भी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पिछली तिथियों से सेवा की निरंतरता प्रदान करने का निर्णय था। खज्जन सिंह याचिकाकर्ता संख्या 2 के मामले में पुरस्कार दिनांक 4 जनवरी 2006 है। राज्य ने याचिका का विरोध किया है।

(51) ऐसा कहा गया है कि वन विभाग ने मजदूरों को ज्यादातर वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए लगाया है जो प्रकृति में मौसमी हैं जो मानसून के मौसम के दौरान 2-3 महीने यानी जुलाई से सितंबर तक जारी रहती हैं। जब सीज़न खत्म हो जाता है तो नर्सरी आदि के रखरखाव के लिए केवल कुछ मजदूरों को ही रखा जाता है। उनमें से कुछ को बागानों में सफाई और निराई-गुड़ाई के काम के लिए अक्टूबर और नवंबर में वापस बुला लिया जाता है। बताया गया है कि वन विभाग मस्टर रोल प्रणाली के माध्यम से वानिकी कार्य निष्पादित करता है। पिछले कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा था कि मस्टर रोल अप्रभावी, अप्रभावी तथा अलाभकारी हो गया है। हरियाणा वन मैनुअल के पैराग्राफ 13.70 में प्रावधान है कि वन रक्षक कार्यों के

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

प्रभारी अधिकारी हैं और उन्हें दैनिक मजदूरी पर श्रम लगाने का अधिकार है; सुबह और शाम को रोल कॉल लें और प्रतिदिन किए गए कार्य की दैनिक शीट तैयार करें। वन रक्षक के नियंत्रण वाला क्षेत्र आम तौर पर दूर-दराज के स्थानों पर होता है। यह अनुभव किया गया कि व्यावहारिक रूप से उनके लिए प्रतिदिन प्रत्येक स्थान पर दो बार रोल कॉल लेना असंभव हो गया, अपने नियंत्रण में सभी स्थानों पर काम की निगरानी की तो बात ही छोड़ दें। इसके परिणामस्वरूप मजदूरों के पास काम की कमी हो गई, जिसके कारण वन कर्मचारियों को मजदूरों की कम दक्षता के लिए भुगतान करना पड़ा। हालाँकि सरकार ने भारत के संविधान के निदेशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों (भाग IV के अनुच्छेद 48 ए और भाग IV ए के अनुच्छेद 51 ए (जी) के तहत निहित संवैधानिक जनादेश के संदर्भ में विभिन्न वन गतिविधियों को पूरा करने के अपने कर्तव्य को मान्यता दी। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुरूप देश के वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन की रक्षा और सुधार करना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना और वायुमंडलीय संतुलन सहित पारिस्थितिक संतुलन का रखरखाव सुनिश्चित करना, जो मनुष्यों, पौधों और जानवरों जैसे सभी जीवन रूपों के भरण-पोषण के लिए महत्वपूर्ण हैं। जिसका कोई लाभ का उद्देश्य या आय उत्पन्न करने की इच्छा नहीं है जैसा कि किसी औद्योगिक गतिविधि से अपेक्षा की जाती है। वन विभाग को वित्तीय मदद के लिए राज्य सरकार और बाहरी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। अधिकांश गतिविधियाँ भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं के तहत की जा रही



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

हैं .यूरोपीय संघ, विश्व बैंक आदि से यह आग्रह किया गया कि यदि यह आकस्मिक आधार पर दैनिक वेतन पर नियुक्ति या नियुक्ति है तो यह बंद होने पर समाप्त हो जाएगी। यदि किसी अस्थायी कर्मचारी या आकस्मिक कर्मचारी को उसकी नियुक्ति की अवधि से अधिक समय तक जारी रखा जाता है, तो वह केवल ऐसी निरंतरता के आधार पर नियमित सेवा में शामिल होने या स्थायी होने का हकदार नहीं होगा, यदि मूल नियुक्ति निम्नलिखित का पालन करके नहीं की गई थी। प्रासंगिक नियमों द्वारा परिकल्पित चयन की उचित प्रक्रिया। यह कहा गया कि हरियाणा सरकार ने उमादेवी मामले में फैसले के आलोक में 13 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना के माध्यम से 17 जून 1997, 5 नवंबर 1999, 1 अक्टूबर 2003 और 10 फरवरी 2004 को नियमित करने के संबंध में पिछली नीतियों को वापस ले लिया था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह अधिसूचना "...उन मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी जहां नियमितीकरण पहले ही किया जा चुका है लेकिन विचाराधीन नहीं हैं।"

(52) प्रतिवादी राज्य का बचाव यह था कि याचिकाकर्ताओं को वन विभाग के सबसे निचले क्षेत्र के अधिकारी यानी वन रक्षक द्वारा दैनिक वेतन भोगी मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। ऐसे श्रमिकों का कार्य नर्सरी में पौध तैयार करना, गड्ढे खोदना, रोपण करना, पौधों को पानी देना, पौधों की निराई और गुड़ाई करना है और विशिष्ट कार्य के लिए उनकी नियुक्ति एक विशिष्ट अवधि के लिए होती थी।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(53) फिर भी वन विभाग ने लिखित बयान में स्वीकार किया कि नियमों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्तियाँ/नियोजन किया जा सके। इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का रोजगार नियमों के विपरीत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। इसलिए किसी दैनिक वेतनभोगी को सेवा में बने रहने या नियमित होने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे किसी भी पद के धारक नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था और इसमें कोई विवाद नहीं है कि वे 1980 के दशक और 1990 के दशक की शुरुआत में कार्यरत थे और उनके अधीनस्थ समकक्ष जो काम करना जारी रखते थे, उन्हें उमादेवी में घोषणा के बाद 14 अक्टूबर 2006 को नियमित कर दिया गया और उनकी सेवाएं स्थायी रूप से सुरक्षित रहीं। उन्होंने बर्खास्त होने से पहले 7 से 10 साल (9 याचिकाकर्ताओं) तक काम किया था, जबकि उनमें से एक यानी पवन कुमार याचिकाकर्ता नंबर 2 ने 1 अगस्त 1999 से 16 मार्च 2000 तक सेवा की थी जब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था लेकिन वे वापस आ गए। 18 अप्रैल 2006 को श्रम न्यायालय का फैसला सुनाया गया। उनमें से कुछ ने छंटनी की तारीखों से पहले 10 या उससे अधिक बार निरंतर सेवा की थी। उनके पक्ष में पुरस्कार 4 जनवरी 2006 से 12 नवंबर 2008 की अवधि के दौरान आए हैं। जिस कर्मचारी को 12 जनवरी 2008 को बहाली और सेवा की निरंतरता से सम्मानित किया गया था, वह ओम प्रकाश थे जिन्होंने 15 जुलाई 1986 से 31 अक्टूबर तक वन विभाग में सेवा की

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

थी। 1999 जब उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। इसलिए पवन कुमार याचिकाकर्ता नंबर 2 जैसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने वास्तविक सगाई के थोड़े समय के बाद कुल सेवा के 6/2 वर्षों के बारे में कानूनी कल्पना द्वारा जमा किए गए श्रम पुरस्कारों के परिणामस्वरूप सेवा की निरंतरता हासिल की है और ऐसे मामलों में सरकार बनी रहेगी उमादेवी से पहले 10 साल की सेवा के नियम को ध्यान में रखते हुए और क्या वह राहत के लिए विचार के लिए उपयुक्त कानून के मानकों को पूरा करता है, उन्हें ध्यान में रखते हुए उन्हें नियमित करना है या नहीं, इस बारे में सचेत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

(54) वेद पाल के मामले (पूर्व) में पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण की पुष्टि भाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस प्रकार करते हुए की थी : -

"इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जूनियरों के दावे पर पहले विचार किया गया और उन्हें नियमित किया गया।" हालाँकि, प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए निजी उत्तरदाताओं के पक्ष में की गई सिफारिशों को प्रधान कार्यालय द्वारा इस दलील पर स्वीकार नहीं किया गया कि इस बीच कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी 2006 (4) एससीसी- में माननीय सर्वोच्च न्यायालय 1 ने सरकारी नीतियों को रद्द कर दिया

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

था जिससे नियमितीकरण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं रह गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी यही तर्क दिया गया था जिसे यह देखते हुए खारिज कर दिया गया कि निजी उत्तरदाताओं के साथ भेदभाव किया गया है। विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में एकमात्र प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या निजी उत्तरदाताओं ने सरकारी नीति के संदर्भ में या संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के भेदभाव और उल्लंघन की दलील पर अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग की है? चूँकि यह रिकॉर्ड पर स्वीकार किया गया है कि निजी उत्तरदाताओं के कनिष्ठों को नियमित कर दिया गया था और उनकी सेवाओं को डी-रेगुलराइज़ करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी कि वरिष्ठों की अनदेखी की गई है और हमारे विचार में किसी भी उचित वर्गीकरण के बिना निजी उत्तरदाताओं की अनदेखी की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के दायरे में शत्रुतापूर्ण भेदभाव का मामला बनाया। इसका मतलब यह होगा कि भले ही सरकारी नीति अस्तित्व में नहीं है और इसे रद्द माना जाता है, निजी उत्तरदाता उस तारीख से अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग करने के हकदार होंगे, जब उनके कनिष्ठों को ऐसा लाभ दिया गया था..."

(55) श्री सुनील नेहरा को पता चला कि राज्य की ओर से पेश हुए हरियाणा के वरिष्ठ

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

उपमहाधिवक्ता, **राजिंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (17)** में डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा करते हैं; यह प्रस्तुत करने के लिए कि भेदभाव की दलील को इस कारण से खारिज कर दिया गया था कि उमादेवी के अनुपात का स्पष्ट रूप से उन सभी पिछले उदाहरणों को खारिज करने का इरादा था जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों के विपरीत हैं, जिससे उच्च न्यायालयों को आवश्यक रूप से निर्धारित कानून का पालन करना पड़ता है। पैरा 14 में इस न्यायालय ने कहा कि हमें यह देखने में कोई झिझक नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत 1.10.2003 को जारी नियमितीकरण की नीति या ऐसी कोई अन्य नीति नियमितीकरण के उद्देश्य से कर्मचारियों को लागू करने योग्य अधिकार प्रदान नहीं करेगी। उक्त नीतियों और योजनाओं के तहत पहले से प्राप्त लाभ अप्रभावित रहेंगे। जिन कर्मचारियों को फैसले के पैरा 15 के साथ पढ़े गए पैरा 53 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नियुक्त किया गया है, उनके लिए एकमात्र रास्ता उन लोगों के लिए प्रस्तावित एकमुश्त-माप योजना थी, जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है। गौरतलब है कि डिवीजन बेंच ने नियमों के तहत नियुक्त पदों पर विचार किया था और नियमों

(17) 2006 (3) एससीटी 838 = 2006 (4) आर एस जे 290.

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

के विपरीत की गई नियुक्तियां नियमितीकरण या स्थायीकरण के संदर्भ में लागू करने योग्य नहीं थीं।

(56) वकील **यू.पी. पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार और अन्य (18)** को संदर्भित करता है; सुप्रीम कोर्ट का मामला संविधान के 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संशोधन और उनकी संवैधानिक वैधता तथा **एम.नागराज बनाम भारत संघ(19)** मामले में निर्धारित नियमों के संदर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित था। मुझे पैरा 12 से 14 का संदर्भ लेना होगा जहां सुप्रीम कोर्ट का मानना है :-

“12. हमने दोनों निर्णयों के पैराग्राफों को विस्तार से इस बात पर प्रकाश डालने के लिए पुनः प्रस्तुत किया है कि इलाहाबाद पीठ को लखनऊ में पहले दायर किए गए मामलों की संख्या के बारे में अवगत कराया गया था, जिनकी आंशिक सुनवाई हो रही थी और सुनवाई निरंतर चल रही थी। यह उचित होगा कि लखनऊ पीठ में फैसले की प्रतीक्षा की जाए या दोनों स्थानों पर समान मामलों की सुनवाई के बारे में इसे विद्वान मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाया जाए। न्यायिक शिष्टाचार और मर्यादा में ऐसे अनुशासन की आवश्यकता होती है जिसकी विद्वान से अपेक्षा की जाती है। लेकिन

(18) 2012 (7) एससीसी 1.

(19) (2006) 8 एससीसी 212

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

अथाह कारणों से किसी भी पाठ्यक्रम का सहारा नहीं लिया गया। इसी तरह लखनऊ की डिवीजन बेंच ने गलती से इलाहाबाद बेंच के फैसले को एम.नागराज मामले में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर बाध्यकारी मिसाल नहीं माना। (पूर्व) को उचित रूप से सराहना नहीं की गई और बेंच द्वारा सही ढंग से लागू नहीं किया गया, जबकि उक्त निर्णय का संदर्भ था और कई अंशों को उद्धृत किया गया था और गलत तरीके से सराहना की गई थी, वही फैसले को गलत तरीके से मानने का आधार नहीं हो सकता था या नहीं। एक बाध्यकारी मिसाल. न्यायिक अनुशासन ऐसी स्थिति में आदेश देता है जब मामले को बड़ी बेंच को सौंपने पर असहमति हो। ऐसा करने के बजाय लखनऊ की डिवीजन बेंच ने मामले का फैसला करने का बोझ अपने ऊपर ले लिया। इस संदर्भ में हम लाला श्री भगवान और अन्य बनाम राम चंद और अन्य, एआईआर 1965 एससी 1767 का एक अंश उद्धृत कर सकते हैं :-

“18. .. इस बात पर ज़ोर देना शायद ही आवश्यक है कि न्यायिक औचित्य और मर्यादा के विचार के लिए यह आवश्यक है कि यदि किसी मामले की सुनवाई करने वाला विद्वान एकल न्यायाधीश यह विचार करने के लिए इच्छुक है कि उच्च न्यायालय के पहले के फैसले, चाहे वह डिवीजन बेंच के हों या एकल न्यायाधीश के, की आवश्यकता है। इस बात पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि उन्हें एकल न्यायाधीश के रूप में बैठकर उस जांच को शुरू नहीं करना

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

चाहिए, बल्कि मामले को एक डिवीजन बेंच को भेजना चाहिए या उचित मामले में संबंधित कागजात मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखना चाहिए ताकि वह प्रश्न की जांच के लिए एक बड़ी बेंच का गठन कर सकें। ऐसे मामलों से निपटने का यही उचित और पारंपरिक तरीका है और यह न्यायिक मर्यादा और औचित्य के स्वस्थ सिद्धांतों पर आधारित है। यह खेदजनक है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने वर्तमान मामले में इस पारंपरिक तरीके से हटकर स्वयं प्रश्न की जांच करने का फैसला किया।"

14. सुंदरजस कन्यालाल भतीजा और अन्य बनाम कलेक्टर में,

ठाणे, महाराष्ट्र और अन्य, 1989 (2) आर.आर.आर. III: AIR 1991 SC 1893 न्यायिक अनुशासन से निपटते समय दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार व्यक्त किया है: -

“किसी को यह याद रखना चाहिए कि कानून का पालन चाहे कितना भी ग्लैमरस क्यों न हो, बेंच पर उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। बहु-न्यायाधीश न्यायालय में, न्यायाधीश उदाहरणों और प्रक्रिया से बंधे होते हैं। वे अपने विवेक का प्रयोग तभी कर सकते थे जब कोई घोषित सिद्धांत न हो, कोई नियम न हो और कोई अधिकार न हो। न्यायिक मर्यादा और कानूनी औचित्य की मांग है कि जहां एक विद्वान एकल न्यायाधीश या डिवीजन बेंच समन्वय



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

क्षेत्राधिकार वाली बेंच के फैसले से सहमत नहीं है, तो मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा जाएगा।  
इस प्रक्रिया का पालन न करना न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।”

उपरोक्त घोषणाएँ स्पष्ट रूप से बताती हैं कि जब न्यायाधीशों को एक ही मुद्दे पर समन्वय पीठ के फैसले का सामना करना पड़ता है तो उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। कोई भी विपरीत रवैया चाहे कितना ही साहसिक और गौरवपूर्ण क्यों न हो, अनिश्चितता और असंगति को जन्म देगा। मौजूदा मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। एक ही उच्च न्यायालय की दो खंडपीठों द्वारा दो फैसले दिए गए हैं। हम दोनों पीठों द्वारा न्यायिक मर्यादा और अनुशासन से विचलन के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वे समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित इस तरह के अनुशासन की वैचारिक स्थिति द्वारा उचित रूप से निर्देशित होंगे। हमने इस आशा के साथ ऐसा कहा है कि न्यायिक उत्साह से न्यायाधीशों से अपेक्षित गहन जिम्मेदारी खत्म नहीं होनी चाहिए।”

(57) यह निर्णय विद्वान राज्य वकील द्वारा 28.2.2013 को तय किए गए 2012 के एलपीए संख्या 1746 में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में उद्धृत किया गया है; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चन्नी और जुड़े मामले (इसके बाद चन्नी को संदर्भित किया गया है)। यह अपील 9 जुलाई 2012 को दिए गए फैसले के खिलाफ विद्वान

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

एकल न्यायाधीश के आदेश पर आधारित थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादियों की सेवाओं को उस दिन से नियमित करने का निर्देश दिया था, जिस दिन से उनके कनिष्ठों को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियमित किया गया था। डिवीजन बेंच ने उमादेवी में निर्धारित कानून को लागू किया। नियमितीकरण के लिए चन्नी में उत्तरदाताओं के दावे को विद्वान एकल न्यायाधीश ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन राज्य द्वारा अपील में खारिज कर दिया गया था, परिभाषा के अनुसार मालिस द्वारा तब किया गया था जब 53 कैडर पदों का विज्ञापन किया गया था जो दैनिक वेतनभोगियों के लिए भरने के लिए नहीं थे। डिवीजन बेंच ने कहा कि राजिंदर कुमार के मामले (पूर्व) में की गई श्रमसाध्य कवायद ने उमादेवी के प्रभाव के मामले में उनके काम को आसान बना दिया है। बेंच ने उमादेवी में संविधान पीठ द्वारा अवैध और अनियमित नियुक्तियों के बीच किए गए एक अंतर पर गौर किया, पहले को बचाया नहीं जा सका लेकिन अनियमित नियुक्तियां पैरा 53 में दिए गए अपवाद के माध्यम से आ सकती हैं। उमादेवी के पैरा 53 पर भरोसा किया गया जिसमें लिखा है :-

“एक पहलू को स्पष्ट करने की जरूरत है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अनियमित नियुक्तियां (अवैध नियुक्तियां नहीं) जैसा कि एस.वी.नारायणप्पा (पूर्व), आर.एन. में बताया गया है। नंजुंदप्पा (पूर्व), और बी.एन.नगरराजन (सुप्रा), और उपरोक्त पैराग्राफ 15 में उल्लिखित रिक्त पदों पर विधिवत योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया गया होगा और कर्मचारियों ने दस

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

साल या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखा है, लेकिन आदेशों के हस्तक्षेप के बिना। अदालतों का या न्यायाधिकरणों का। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित मामलों में तय किए गए सिद्धांतों और इस निर्णय के आलोक में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। उस संदर्भ में भारत संघ, राज्य सरकारों और उनकी संस्थाओं को ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त लोगों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एकमुश्त उपाय करना चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, लेकिन अदालतों के आदेशों की आड़ में नहीं। न्यायाधिकरणों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्तियां की जाएं, जिन्हें भरने की आवश्यकता है, जहां अब अस्थायी कर्मचारी या दैनिक वेतनभोगी कार्यरत हैं। इस तिथि से छह महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई नियमितीकरण पहले ही हो चुका है, लेकिन न्यायाधीन नहीं है, तो उसे इस फैसले के आधार पर फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संवैधानिक आवश्यकता को और अधिक दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए और संवैधानिक योजना के अनुसार विधिवत नियुक्त नहीं किए गए लोगों को नियमित करना या स्थायी करना नहीं चाहिए।"

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(58) राजिंदर कुमार के मामले में यह बताया जा सकता है कि विचाराधीन पद वालर पंप ऑपरेटर ग्रेड-11 का था जो कि ग्रुप-सी का पद है और इसलिए निर्णय उन मामलों के सेट से तथ्यों पर अलग है जो दैनिक ग्रामीणों से संबंधित हैं। और सार्वजनिक पदों के धारक नहीं। चन्नी में माननीय डिवीजन बेंच ने **आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य (20)** में सुप्रीम कोर्ट के तनाव भरे शब्दों पर ध्यान दिया; विलाप:-

“57. संविधान के अनुच्छेद 141 के आधार पर, सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी (पूर्व) मामले में संविधान पीठ का निर्णय इस न्यायालय सहित सभी अदालतों पर तब तक बाध्यकारी है जब तक कि इसे बड़ी पीठ द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता। तदर्थ/अस्थायी/दैनिक वेतनभोगी/आकस्मिक कर्मचारियों द्वारा किए गए सेवा के नियमितीकरण के दावे पर विचार करने से इनकार करने या ऐसे कर्मचारियों को राहत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेशों को उलटने के लिए संविधान पीठ के फैसले के अनुपात का पालन विभिन्न दो-न्यायाधीशों की पीठों द्वारा किया गया है। कर्मचारी - इंडियन ड्रग्स एंड फार्माक्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन {2007 (1) एससीसी 4081}, गंगाधर पिल्लई बनाम सीमेंस लिमिटेड [2007 (1) एससीसी 533], केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम एल.वी.

(20) 2008 (10) एससीसी 1

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

सुब्रमण्येश्वर (2007 (5) एससीसी 326] हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाम दान  
बहादुर सिंह [2007(6) एससीसी 207], हालांकि

यूपी, एसईबी बनाम पूरन चंद पांडे [2007 (11) एससीसी 92] में, जिस पर श्री गुप्ता ने भरोसा  
जताया है, दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इसे कमजोर करने का प्रयास किया है। संविधान पीठ  
के फैसले में यह सुझाव दिया गया है कि उक्त निर्णय को ऐसे मामले में लागू नहीं किया जा  
सकता है जहां संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसरण में नियमितीकरण की मांग की गई है  
और यह मेनका गांधी बनाम यूनियन मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के विपरीत  
है। भारत [1978(1) एससीसी 248]।

70. हम यह जानकर व्यथित हैं कि इस विषय पर कई घोषणाओं के बावजूद न्यायिक  
अनुशासन की बुनियादी बातों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।  
उच्च न्यायालयों के विद्वान एकल न्यायाधीश और पीठ तथ्यों में मामूली अंतर का हवाला  
देकर समन्वय और यहां तक कि बड़ी पीठों द्वारा निर्धारित फैसले और कानून का पालन करने  
और स्वीकार करने से इंकार कर देते हैं। इसलिए यह दोहराना आवश्यक हो गया है कि  
संवैधानिक लोकाचार का अनादर और अनुशासन का उल्लंघन न्यायिक संस्थान की  
विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव डालता है और आकस्मिक मुकदमेबाजी को बढ़ावा देता है।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

यह याद रखना चाहिए कि पूर्वानुमेयता और निश्चितता इस देश में पिछले छह दशकों में विकसित न्यायिक न्यायशास्त्र की एक महत्वपूर्ण पहचान है और उच्च न्यायपालिका के परस्पर विरोधी निर्णयों की आवृत्ति में वृद्धि से व्यवस्था को अपूरणीय क्षति होगी, साथ ही जमीनी स्तर पर अदालतें भी। यह तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फैसला सही कानून बताता है और किसका पालन किया जाना चाहिए। हम यह जोड़ सकते हैं कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करे। जिन लोगों को व्यवस्था के संचालन और राज्य के विभिन्न घटकों के संचालन का काम सौंपा गया है और जो संविधान के अनुसार कार्य करने और उसे कायम रखने की शपथ लेते हैं, उन्हें संवैधानिक आदर्शों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता प्रदर्शित करके एक उदाहरण स्थापित करना होगा। इस सिद्धांत का न्यायिक बिरादरी के सदस्यों द्वारा अधिक कठोरता से पालन किया जाना आवश्यक है, जिन्हें महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर निर्णय लेने और समग्र रूप से व्यक्तियों और समाज के अधिकारों की रक्षा और संरक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायिक प्रणाली के प्रभावी और कुशल कामकाज के लिए अनुशासन अनिवार्य शर्त है। यदि न्यायालय दूसरों को संविधान के प्रावधानों और कानून के शासन के अनुसार कार्य करने का आदेश देते हैं तो उन लोगों द्वारा संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करना संभव नहीं है जिन्हें कानून बनाने की आवश्यकता है।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

71. ऊपर जो कहा गया है उसके आलोक में हम यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि यूपी राज्य बिजली बोर्ड बनाम पूरन चंद्र पांडे (सुप्रा) मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों और टिप्पणियों को ओबिटर और उसी के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। किसी भी मामले को उच्च न्यायालयों द्वारा बाध्यकारी नहीं माना जाना चाहिए। न्यायाधिकरणों और अन्य न्यायिक मंचों पर न तो उन पर भरोसा किया जाना चाहिए और न ही उन्हें संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को दरकिनार करने का आधार बनाया जाना चाहिए।" (ज़ोर दिया गया)

(59) सुप्रीम कोर्ट अक्सर संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत अपने पिछले संविधान पीठ के फैसलों को संरक्षित और एहतियाती शब्दों में लागू करते समय उनका उल्लेख नहीं करता है कि "अनुच्छेद 141 के आधार पर..." यह "...सभी पर बाध्यकारी है" इस न्यायालय को तब तक शामिल करें जब तक कि इसे एक बड़ी पीठ द्वारा खारिज न कर दिया जाए। किसी ने सोचा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ अपने अनुपात निर्णय के आधार पर बाध्यकारी हैं और अनुच्छेद 141 के कारण के अलावा अन्य बाध्यकारी नहीं हैं। इसमें बहुत कुछ है यहां जानें.

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(60) विभिन्न कारणों से विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चन्नी में अस्थिर माना गया। अपीलें स्वीकार कर ली गईं और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया गया। मामले को रिमांड पर लिया गया. भेदभाव के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के उमादेवी और दयानंद फैसलों के संदर्भ में छुआ और निपटाया गया। श्री नेहरा ने आग्रह किया है कि हरियाणा राज्य बनाम चन्नी और पंजाब राज्य बनाम श्रीमती सुखमिंदर कौर (पूर्व) मामले में दो खंडपीठों की दो परस्पर विरोधी राय हैं और इस प्रकार यह मामला एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। स्पष्ट संघर्ष को सुलझाने के लिए ।

परिशिष्ट भाग।

(61) इन मामलों में आदेश 13 दिसंबर 2013 को सुरक्षित रखे गए थे। उस समय मुझे संदेह था कि चैनिन (2013) और राजिंदर कुमार (2006) में दो डिवीजन बेंचों में प्रतिपादित कानून के सिद्धांत पूरी तरह से दैनिक मामलों पर लागू नहीं हो सकते हैं। स्थानीय स्तर पर नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी और जिनकी सेवाएँ भर्ती के नियमों द्वारा कड़ाई से शासित नहीं हो सकती हैं। इन अधिकारों की औद्योगिक कानून सिद्धांतों के सुविधाजनक दृष्टिकोण से जांच और घोषणा की जानी चाहिए और इन मामलों को अलग-अलग उपचार के लिए समूहित किया जाना चाहिए। सोच की यह दिशा कास्टेरिबे से प्रभावित थी जिसे चन्नी में डिवीजन बेंच



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

के ध्यान में नहीं लाया गया था। आगे का कारण संविधान के अनुच्छेद 14 के दो अलग-अलग हिस्सों पर ओम कुमार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों के अनुरूप था, एक मनमानी का और दूसरा भेदभाव का, जिसके सिद्धांतों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना पड़ सकता है। संबंधित पक्षों के अधिकारों के निष्पक्ष, सार्थक और प्रभावोत्पादक निर्णय के लिए। मनमानी के एक मामले में रिट कोर्ट को सूचित किया गया था कि वह द्वितीयक समीक्षा के सिद्धांतों को अच्छी तरह से लागू कर सकता है, लेकिन जब अनुचित भेदभाव की वकालत की जाती है, दबाव डाला जाता है और अभ्यास किया जाता है और मूलभूत तथ्यों पर गंभीरता से विवाद नहीं किया जाता है तो रिट कोर्ट के पास आरोपमुक्त करने के अलावा बहुत कम विकल्प बचता है। प्राथमिक समीक्षा के सिद्धांतों को लागू करके अनुचित भेदभाव को खत्म करना उसका संवैधानिक कर्तव्य है, चाहे जो भी हो उस कर्तव्य से पीछे हटना नहीं। गनयुथम और ओम कुमार में बताए गए कानून के सिद्धांतों को भी अनुचित भेदभाव के बिंदु पर विचार के लिए चन्नी में डिवीजन बेंच के ध्यान में नहीं लाया गया था।

(62) आदेश सुरक्षित रखने के बाद निर्णय तैयार करने के बाद मैंने उत्सुकता से सोचा था कि इस मामले को कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसमें शामिल संवेदनशील मुद्दों पर क्या किया जाए और क्या मुझे चन्नी को अलग करना चाहिए और सुखमिंदर कौर का अनुसरण करना चाहिए और उमादेवी को कास्टेरिबे द्वारा अलग करना चाहिए या संदर्भित करना चाहिए हरि

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

**नन्दन प्रसाद और एक अन्य बनाम एफसीआई और अन्य (21);** नियोक्ता आई/आर मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में श्री नेहरा द्वारा उठाए गए संघर्ष को हल करने के लिए एक बड़ी पीठ के सामने तैयार किए गए आठ प्रश्न। मेरे संज्ञान में यह आया कि उच्चतम न्यायालय ने कास्टेरिबे और उमादेवी को चन्नी के तीव्र प्रस्थान पर ध्यान देने के बाद (दोनों को माननीय श्री न्यायमूर्ति ए. उच्चतम न्यायालय ने पैरा 34 में भेदभाव के जटिल प्रश्न का समाधान इस प्रकार करते हुए किया: -

“34. ऊपर विस्तार से चर्चा किए गए दोनों निर्णयों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने पर हमारी राय है कि जब किसी अनुचित श्रम प्रथा के अभाव में पद उपलब्ध हों तो श्रम न्यायालय केवल इसलिए नियमितीकरण के लिए निर्देश नहीं देगा क्योंकि एक कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में जारी रहा है। कई वर्षों तक तदर्थ/अस्थायी कर्मचारी। इसके अलावा, यदि कोई पद उपलब्ध नहीं है तो नियमितीकरण के लिए ऐसा निर्देश अस्वीकार्य होगा। उपरोक्त परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति को केवल दैनिक वेतन भोगी आदि के रूप में बिताए गए वर्षों की संख्या के आधार पर नियमित करने का निर्देश देना सेवा में पिछले दरवाजे से प्रवेश के समान हो सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 14 के लिए अभिशाप है। इसके अलावा ऐसा कोई निर्देश

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

तब नहीं दिया जाएगा जब संबंधित कर्मचारी भर्ती नियमों के अनुसार संबंधित पद की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हो। हालाँकि, जहाँ भी यह पाया जाता है कि समान स्थिति वाले श्रमिकों को किसी योजना के तहत या अन्यथा नियोक्ता द्वारा नियमित किया जाता है और जिन श्रमिकों ने औद्योगिक/श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, वे उनके बराबर हैं, ऐसे मामलों में नियमितीकरण की दिशा कानूनी रूप से उचित हो सकती है अन्यथा नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में बचे हुए श्रमिकों के साथ भेदभाव करना स्वयं उनके साथ घृणित भेदभाव होगा और क्या यह संविधान की धारा 14 का उल्लंघन होगा। इस प्रकार औद्योगिक विज्ञापन न्यायाधीश इस संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करने के बजाय अनुच्छेद 14 को बरकरार रखते हुए समानता प्राप्त करेंगे। (महत्व जोड़ें)

और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना)

(63) फैसले में ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि ने स्थिति बदल दी है। तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए पैरा 34 में दिए गए फैसले ने औद्योगिक न्यायशास्त्र की सीमाओं को इतना व्यापक रूप से बढ़ाया है जितना पहले कभी नहीं हुआ था। यह यूपीएस.ई.बी बनाम पूरन चंद पांडे (22) के समान ही है, जिसे आधिकारिक परिसमापक बनाम

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

दयानंद और अन्य में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अस्वीकार कर दिया था, जो कास्टेरिबे से पहले का निर्णय है। तथापि,

(64) उमादेवी (3) को अब श्रम न्यायशास्त्र के अनुप्रयोग में कास्टेरिबे और हरि नंदन प्रसाद दोनों के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए, पहले अनुचित श्रम अभ्यास के दृष्टिकोण से और दूसरे अनुचित के दृष्टिकोण से भेदभाव जबकि उमादेवी मुख्य सेवा कानून न्यायशास्त्र और उनके सूक्ष्म अंतर के विपरीत श्रम कानून के दायरे से परे हैं। श्रम कानून कास्टेरिबे में चित्रित किया गया था। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी ताकत नहीं लगाई और उमादेवी (3) में निर्धारित संविधान पीठ के सिद्धांतों से बंधे रिक्तियों के सिद्धांतों और प्रारंभिक नियुक्तियों की प्रकृति के आधार पर सेवा कानून सिद्धांतों पर अपने फैसले को सीमित नहीं किया। फिर भी हरि नंदन प्रसाद (पैरा 34) के लिए बनाया गया अपवाद वह जगह है जहां पैर जमा हुआ है और मामलों के वर्तमान बैच का टेकऑफ़ बिंदु अब आराम कर रहा है। अनुचित भेदभाव के सिद्धांतों पर नियमितीकरण की मांग अब औद्योगिक न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों के माध्यम से आने वाले मामलों में नियमितीकरण के अनुकूल कार्यालय आदेश पारित करने के लिए तेज हो गई है, जिससे भेदभाव पर संवैधानिक कानून सिद्धांतों को लागू करने की मांग बढ़ रही है। मैं कह सकता हूं कि कोई भी छोटा-मोटा भेदभाव अनुचित

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

नहीं है क्योंकि उस पर कानून द्वारा अनुमत उचित प्रतिबंध लग सकते हैं। इसीलिए मैंने केवल अनुचित भेदभाव पर ध्यान दिया है जो न्यायिक रूप से अस्वीकार्य है, लेकिन केवल भेदभाव नहीं है जिस पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं। लेकिन यहां स्थिति अस्वीकार्य है क्योंकि किसी समरूप समूह को कृत्रिम रूप से तोड़ना कानूनी रूप से उचित नहीं है। ऐसा न होने पर बचे हुए श्रमिकों/दुर्भाग्यशाली समूह का नियमितीकरण न होना, जैसा कि अब हरि नंदन प्रसाद में परिभाषित है, शत्रुतापूर्ण और द्वेषपूर्ण भेदभाव होगा। इसलिए, न्यायिक हस्तक्षेप के बिना पारित प्रशासनिक आदेशों द्वारा समकक्षों को नियमितीकरण का लाभ प्राप्त करने की तारीखों से यथास्थिति प्रदान करके संतुलन बहाल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हरि नंदन प्रसाद के मामले में कहा कि "...औद्योगिक निर्णायक को लक्ष्य हासिल करना होगा।" इस संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करने के बजाय अनुच्छेद 14 को बरकरार रखते हुए समानता"।

(65) अनुच्छेद 14 में संवैधानिक सीमाओं से बंधे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रतिकूल राज्य कार्रवाई या निष्क्रियता के परिणामस्वरूप समानता में अनुचित को मिटाने का आदेश दिया गया है और वे न्यायिक कर्तव्यों का पालन करते समय शपथ के तहत रहेंगे कि वे अनुचित भेदभाव पाते ही उसे खत्म कर देंगे। यह उनके सामने रखे गए केस पेपर्स से बदसूरत सिर पीछे की ओर है। वे अनुच्छेद 14 के घास के मैदान में उगने से पहले खरपतवार को मारने

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

के लिए बाध्य रहेंगे। अनुच्छेद 14 कम से कम कानून का दिल है जो संविधान की कोशिकाओं में रस पंप करता है ताकि यह अच्छी तरह से पोषित हो और एक बरगद के रूप में विकसित हो सके। वृक्ष अपनी जड़ प्रणाली के साथ सभी चीजों में व्याप्त है। दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी के बाद उसके संवैधानिक न्यायालय का प्रतीक बरगद का पेड़ बन गया।

(66) राज्य द्वारा किए जाने वाले किसी भी अनुचित भेदभाव को कानून के मजबूत हाथों से कठोर सकारात्मक कार्रवाई द्वारा निपटाया जाना चाहिए ताकि अनुचित भेदभाव को दूर किया जा सके और इसे बढ़ावा न दिया जाए ताकि किसी भी नागरिक के अधिकार बिना निवारण के न रह जाएं। याचिकाकर्ताओं को अकेला छोड़ देना और यह महसूस करना बेहद शर्म की बात होगी कि अनुच्छेद 14 उनके लिए नहीं है और केवल 'संपन्न' के लिए है। अनुच्छेद 14 में समानता खंड को जानबूझकर नष्ट करना संविधान के लिए अभिशाप होगा। फिर न्यायाधीश भी अपना बैग पैक करके घर जा सकते हैं।

(67) हालाँकि मैं यहां सावधानी का एक शब्द भी जोड़ सकता हूँ, मैंने इस फैसले में सरकार के विभागों में सेवा की इकाइयों की कैडर शक्ति पर स्वीकृत पदों पर संदिग्ध नियुक्तियों में आसानी से उत्पन्न होने वाले नियमितीकरण के मुद्दे को नहीं छुआ है। राज्य के साधन और यहां कही गई कोई भी बात तृतीय श्रेणी सेवा में पदों के धारकों द्वारा किए गए नियमितीकरण

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

के दावों से जुड़े लंबित सहजताओं के अन्य सेट पर लागू नहीं होगी, जिनका निर्णय उनके अपने तथ्यों और लागू कानूनों के आधार पर किया जाना है।

(68) चूंकि पैरा 34 में हरि नंदन प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब हावी हो गया है, उमा देवी के मामले में चन्नी के फैसले और राजिंदर कुमार द्वारा कास्टेरिबे में सुप्रीम कोर्ट के बाद के दृष्टिकोण की अनदेखी के कारण स्पष्ट संघर्ष हुआ है। महत्वहीन हो जाता है। तदनुसार, इस न्यायालय का पहले से ही तैयार किया गया दृष्टिकोण, जो अब हरि मंडन प्रसाद के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में परिलक्षित होता है, दृढ़ और समर्थित है। इससे इस न्यायालय के पहले के विचारों के बीच किसी भी कथित टकराव को सुलझाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। हरि मंडन प्रसाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम दृष्टिकोण से शक्ति प्राप्त करने के बाद यह निष्कर्ष निकालना मेरे लिए सुरक्षित हो सकता है कि उमादेवी की व्याख्या में अब कोई मतभेद मौजूद नहीं है। इसलिए मुझे इस मामले को इस न्यायालय की बड़ी पीठ के समक्ष रखे जाने के श्री नेहरा के अनुरोध को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि यह मुद्दा हरि मंडन प्रसाद के प्रबुद्ध दृश्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही हल किया गया लगता है।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(69) ऊपर दिए गए नौ प्रश्न आंतरिक रूप से संकेत देते हैं कि उनके उत्तर क्या हो सकते हैं, लेकिन उन सभी के बीच एक व्यापक सूत्र चल रहा है जो सकारात्मक पूर्वव्यापी समता प्रदान करने के मामले का संकेत देता है और उत्तर देता है कि क्या यह राहत याचिकाकर्ताओं को दी जाने योग्य है। अनुचित भेदभाव की बुराई को दूर करें, भले ही यह कानून के तहत समानता के मूलभूत सिद्धांत और कानूनों के समान संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से हो। एक समानता जिसे राज्य की नीतियों पर स्थापित कानूनों द्वारा मापा जाता है, जिसके लाभार्थी भाग्यशाली समूह थे, तो क्या याचिकाकर्ताओं को कानूनी रूप से उन सामाजिक और भौतिक लाभों से वंचित किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, के अधिकार श्रम न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में दिए गए निर्णयों से प्राप्त होते हैं और उन्हें सेवा की निरंतरता प्रदान करते हैं। हालाँकि, जहां श्रम न्यायालय द्वारा सेवा की निरंतरता प्रदान नहीं की गई है और ऐसे पुरस्कारों को अंतिम रूप दिया गया है, वह अवधि जिसके लिए पिछली सेवा का लाभ प्रदान नहीं किया गया है, वह इरादों और उद्देश्यों के लिए गणनीय अवधि से वंचित हो जाएगा। वर्तमान मामलों में याचिकाकर्ताओं को सेवा में माना जाएगा जैसे कि प्रतिकूल छंटनी आदेश कभी पारित नहीं किए गए थे। राज्य इनमें से किसी भी मामले में जंगल और सिंचाई विभाग में दैनिक वेतन पर याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक नियुक्ति के लिए लागू सेवा के नियमों को दिखाने में सक्षम नहीं था। इसलिए इन मामलों में उनकी अवैध या अनियमित नियुक्तियों



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

का सवाल बहस का मुद्दा नहीं है और एक मजबूत धारणा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जाएगी कि उनकी प्रारंभिक नियुक्तियाँ कानून के विपरीत नहीं थीं, क्योंकि उन्हें नियोजित करने की शक्ति राज्य में थी। मस्टर रोल प्रणाली को संचालित करने के लिए मैनुअल से प्राप्त शक्ति के साथ अपने स्थानीय पदाधिकारियों के माध्यम से उन्हें दैनिक वेतन रोजगार की पेशकश करना। औद्योगिक विवाद अधिनियम लाभकारी सामाजिक कल्याण कानून का एक हिस्सा है जो संवैधानिक सेवा कानून से अलग और अलग है। हालाँकि जैसे-जैसे समय बीतता गया और वैश्वीकरण और मुक्त उद्यम के लिए भारत के खुलने के साथ प्रस्थान हुआ, धुरी को पूंजी की ओर एक आदर्श बदलाव का सामना करना पड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (23) में बढ़ते ज्वार को वापस करने के लिए बात की। हरजिंदर सिंह की अगुवाई में त्वरित निर्णयों की श्रृंखला से एक बड़ा बदलाव आया। श्रम कानूनों की मूल योजना को कमज़ोर करने में योगदान देने वाले न्यायालयों पर न्यायालय की गहरी पीड़ा को पैरा 30-31 से अधिक अधिक करुणा के साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता था, जो टिप्पणियाँ वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं और लाभप्रद रूप से देखी जा सकती हैं: -

“30. हाल ही में, सामाजिक कल्याण कानूनों की व्याख्या से जुड़े मामलों से निपटने में

(23) (2010) 3 एससीसी

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

अदालतों के दृष्टिकोण में स्पष्ट बदलाव आया है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के आकर्षक मंत्र तेजी से न्यायिक प्रक्रिया का आधार बनते जा रहे हैं और यह धारणा बन गई है कि संवैधानिक अदालतें अब औद्योगिक और असंगठित श्रमिकों की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति नहीं रखती हैं। मौजूदा मामले जैसे बड़ी संख्या में मामलों में, तीन दशकों में इस न्यायालय द्वारा विकसित न्यायशास्त्र में उप-गलियाँ और साइड-लेन बनाकर अवैध रूप से सेवा से हटाए गए श्रमिकों की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को राहत देने से इनकार कर दिया गया है। ऐसे मामलों में सार्वजनिक नियोक्ता द्वारा उठाई गई स्टॉक दलील यह है कि श्रमिक-कर्मचारी का प्रारंभिक रोजगार/नियुक्ति किसी न किसी कानून के विपरीत थी या श्रमिक की बहाली प्रतिष्ठान के वित्तीय स्वास्थ्य पर असहनीय बोझ डालेगी। अदालतों ने गलती करने वाले की जवाबदेही की परवाह किए बिना ऐसी याचिका को तुरंत स्वीकार कर लिया है और अप्रत्यक्ष रूप से गलती के छोटे लाभार्थी को इस तथ्य की अनदेखी करते हुए दंडित किया है कि वह कई वर्षों तक रोजगार में रहा होगा और उसके द्वारा अर्जित सूक्ष्म मजदूरी ही उसकी आजीविका का एकमात्र स्रोत हो सकती है।

31. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यदि किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित किया जाता है तो वह अपने सभी मौलिक और संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जाता है और उसके लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय, स्थिति और अवसर की समानता का

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

लक्ष्य, संविधान में निहित स्वतंत्रताएं भ्रामक बनी रहती हैं। इसलिए अदालतों का दृष्टिकोण संवैधानिक दर्शन के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक अभिन्न अंग हैं और नियोक्ता - सार्वजनिक या सार्वजनिक द्वारा सामने रखे गए विशिष्ट और अस्थिर आधारों पर विचार करके श्रमिक को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।"

(70) कानून का यह कथन या जिसे मैं कानून का पुनः कथन और पुनः अवलोकन कह सकता हूं वह प्रभावी रूप से न्यायिक सहारा के अंतिम न्यायालय से कार्रवाई में मानवतावाद का सारांश है।

(71) जाने से पहले मैं प्रशासनिक कार्रवाई की प्राथमिक और माध्यमिक समीक्षा के सिद्धांतों पर कुछ और शब्द कहूंगा, जो कि ओम कुमार को उनके आधिपत्य द्वारा वितरित किए जाने से कुछ साल पहले न्यायमूर्ति एम.जगन्नाथ राव द्वारा पेश किया गया था। **भारत संघ बनाम जी.गनयुथम (24)** में। इस विषय पर कानूनी स्थिति को रिपोर्ट के पैरा 31 में संक्षेपित किया गया था, जो मेरे विचार से प्रशासनिक कानून और विषय वस्तु श्रम कानून में सार्वभौमिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम है। ऐसा प्रतीत होता है कि गणयुथम में उप पैरा 4(बी) में खुला छोड़ा

(24) (1997) 7 एससीसी 463.

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

गया प्रश्न ओम कुमार में विस्तृत रूप से उत्तर दिया गया है - यूनाइटेड किंगडम और विदेशी न्यायालयों में इस विषय पर शीर्ष स्तर पर बैठे न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णयों में बताई गई न्यायिक विचार प्रक्रियाओं को देखने के बाद। संयुक्त राज्य अमेरिका आदि पैरा 31 इन मार्गदर्शक शब्दों से अवगत कराता है: -

(31) इंग्लैंड और भारत में प्रशासनिक कानून में आनुपातिकता की वर्तमान स्थिति को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है :

(1) किसी भी प्रशासनिक आदेश या वैधानिक विवेक की वैधता का आकलन करने के लिए आम तौर पर वेडनसबरी परीक्षण लागू किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या निर्णय अवैध था या प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से ग्रस्त था या ऐसा था जिसे कोई भी समझदार निर्णयकर्ता अपने सामने सामग्री पर नहीं कर सकता था। और कानून के दायरे में आ गए हैं। न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या प्रासंगिक मामलों को ध्यान में नहीं रखा गया था या क्या अप्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखा गया था या क्या कार्रवाई प्रामाणिक नहीं थी। न्यायालय इस पर भी विचार करेगा कि निर्णय बेतुका था या विकृत। हालाँकि, न्यायालय प्रशासक द्वारा उसके लिए खुले विभिन्न विकल्पों में से चुने गए विकल्प की सत्यता पर विचार नहीं करेगा। न ही न्यायालय अपने निर्णय को प्रशासक के निर्णय से प्रतिस्थापित कर सकता है। यह बुधवारबरी परीक्षण है।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(2) न्यायालय प्रशासक के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वह अवैध न हो या प्रक्रियात्मक अनौचित्य से ग्रस्त न हो या इस अर्थ में तर्कहीन न हो कि यह तर्क या नैतिक मानकों की अपमानजनक अवहेलना है। भविष्य में अंग्रेजी प्रशासनिक कानून में आनुपातिकता सहित अन्य परीक्षण लाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया गया है। ये सीसीएसयू सिद्धांत हैं।

(3) (ए) बगडेके, ब्रिंड और स्मिथ के अनुसार जब तक कन्वेंशन को अंग्रेजी कानून में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक अंग्रेजी अदालतें केवल यह पता लगाने के लिए एक माध्यमिक निर्णय का प्रयोग करती हैं कि क्या निर्णय लेने वाला प्राथमिक पर पहुंचने से पहले सामग्री पर विचार कर सकता था। जैसा उसने किया था वैसा ही निर्णय।

(3)(बी) यदि कन्वेंशन को आनुपातिकता के सिद्धांत को उपलब्ध कराते हुए इंग्लैंड में शामिल किया गया है तो अंग्रेजी अदालतें प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता पर प्राथमिक निर्णय देंगी और पता लगाएंगी कि क्या प्रतिबंध अनुपातहीन या अत्यधिक है या किसी पर आधारित नहीं है मौलिक स्वतंत्रता का उचित संतुलन और उस पर प्रतिबंध की आवश्यकता।

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(4)(ए) हमारे देश में प्रशासनिक कानून में स्थिति जहां उपरोक्त कोई मौलिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है, वह यह है कि न्यायालय/न्यायाधिकरण केवल एक माध्यमिक भूमिका निभाएंगे जबकि तर्कसंगतता के बारे में प्राथमिक निर्णय कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी के पास रहेगा। न्यायालय का द्वितीयक निर्णय क्रमशः लॉर्ड ग्रीन और लॉर्ड डिप्लॉक द्वारा बताए गए वेडनसबरी और सीसीएसयू सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी प्राथमिक प्राधिकारी के रूप में अपने निर्णय पर उचित रूप से पहुंचे हैं या नहीं।

(4) (बी) क्या मौलिक स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक या कार्यकारी कार्रवाई के मामले में हमारे देश में न्यायालय 'आनुपातिकता' के सिद्धांत को लागू करेंगे और मान लेंगे कि प्राथमिक भूमिका को उचित मामले में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया है जहां ऐसी कार्रवाई का आरोप लगाया गया है मौलिक स्वतंत्रता का अपमान करना। तब यह तय करना आवश्यक होगा कि क्या न्यायालयों की प्राथमिक भूमिका केवल तभी होगी जब अनुच्छेद 19, 21 आदि के तहत स्वतंत्रताएं शामिल होंगी न कि अनुच्छेद 14 के तहत।”

(महत्व जोड़ें)

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

(72) स्वर सेट हो चुका था। जहां तक प्राथमिक समीक्षा का सवाल है, अनुच्छेद 19 और 21 बहस योग्य थे। अनुच्छेद 14 प्रभावहीन था. यह समझौता योग्य नहीं है. ओम कुमार (सुप्रा) में अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के प्रश्न का उत्तर सीधे उसी माननीय न्यायाधीश द्वारा दिया गया था। इस प्रकार दोनों निर्णयों को एक साथ जोड़ना होगा, पहला खोजपूर्ण और दूसरा अनुच्छेद 14 के दमनकारी उल्लंघन से निपटने के दौरान प्राथमिक समीक्षा क्षेत्राधिकार का व्याख्यात्मक। इसलिए जब प्राथमिक समीक्षा क्षेत्राधिकार के साथ सशक्त होता है तो न्यायालय समानता का प्रशासक और रक्षक बन जाता है। कानून और कानूनों की समान सुरक्षा ताकि तथ्यों की मांग और तथ्यों और परिस्थितियों में साक्ष्य आवश्यक नहीं पाए जाने पर गैर-संवैधानिक न्यायनिर्णयन के माध्यम से निवारण के लिए ऐसे अधिकार वंचितों को स्थगित न करके मौलिक स्वतंत्रता को सार्थक, त्वरित और सुधारात्मक प्रभाव दिया जा सके। किसी दिए गए मामले का. वर्तमान मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई की प्राथमिक समीक्षा के इन मानकों को लागू करके, जहां भाग्यशाली लोगों ने अदालत के हस्तक्षेप के बिना नियमितीकरण की स्वतंत्रता हासिल की है, लेकिन जिसके परिणामस्वरूप शत्रुतापूर्ण और द्वेषपूर्ण भेदभाव हुआ है, उन्हें कानून की नजर में बुरा घोषित किया गया है। कानून का शासन स्पष्ट रूप से है मनुष्य की मनुष्य के प्रति अमानवीयता के विरुद्ध। इस प्रकार का अभाव नागरिकों के बीच समानता के प्राकृतिक कानून का उल्लंघन है, जो मानव के रूप में दोनों के पास मौजूद बुनियादी अधिकारों के सभी मामलों में समान हैं या हो गए हैं, भले ही कोई लिखित

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

संविधान या वैधानिक कानून नहीं था जो श्रमिकों को अन्याय से बचाता हो। जो लोग अपने समकक्षों के साथ समानता के व्यवहार के हकदार हैं, उनके बीच भेदभाव और अनुचित श्रम व्यवहार श्रम न्यायालय के मुकदमे की धीमी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप कानून की कल्पना से अनुकूल पुरस्कार मिलते हैं, फिर भी न्यायालय को आत्मा की अधीनता को खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। किसी भी पीड़ित व्यक्ति को यह सोचकर लौटाया नहीं जाना चाहिए कि न्यायालय प्रशासक द्वारा बनाए गए अनुचित असंतुलन को बहाल करने में सहायता करने में विफल रहा है।

(73) उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कानून और निर्णयों के सूत्र को एक साथ पढ़ा जाता है और न्यायिक निर्णयों को आपस में जोड़ने वाले विभिन्न कारणों से सेवाओं के पूर्व-दिनांकित नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को उनके पक्ष में और राज्य के खिलाफ घोषित किया जाता है।

(74) रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। मामलों के इस बैच में नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के प्रतिवादी राज्य के आदेश को रद्द कर दिया गया है। ऐसे मामलों में जहां 2003 से नियमितीकरण प्रदान किया गया है, वे इस निर्णय के संदर्भ में उन तारीखों से पूर्व-दिनांकित होंगे, जब ऐसे याचिकाकर्ताओं को उनके पूर्व कनिष्ठों



खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

और साथी श्रमिकों से अलग किया गया था। तदनुसार, हरियाणा राज्य इस आदेश पर सवाल उठाने के लिए निर्धारित सीमा अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक मामले में इस निर्णय के संदर्भ में नए आदेश पारित करेगा। **आदेश आप दें :-**

**पी.एस. बाजवा**

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

**अंकिता महाजन**

**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**(Trainee Judicial Officer)**

**कैथल, हरियाणा**

खज्जन सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायमूर्ति राजीव नाराइन रैना)  
आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा